



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

*H.O.
5/11/99*

सं. 290]
No. 290]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 1999/ज्येष्ठ 21, 1921
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 1999/JYAISTHA 21, 1921

महानिदेशक (रक्षोपाय) का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 1999

विषय :—भारत में फिनाल के आयात से संबंधित रक्षोपाय जांच—अंतिम निष्कर्ष

सा.का.नि. 430.(3)—सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम 1997 के अधीन।

(क) प्रक्रिया :

1. भारत में फिनाल के आयात से संबंधित रक्षोपाय जांच आरंभ करने का नोटिस 2-2-99 को जारी किया गया था और 8-2-99 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था। नोटिस की एक प्रति विभालिखित सभी ज्ञात इच्छुक पक्षों को प्रेपित की गयी थीः—

धरौलू उत्पादक

- (i) हिन्दुस्तान आर्गेंशिक केमिकल्स लिं. (एच.ओ.सी.) मुम्बई
- (ii) हरडिलिया केमिकल्स लिमिटेड (एच.सी.एल.), मुम्बई
- (iii) नेवेली लिंगाइट कार्पोरेशन, तमिलनाडु

आयातक

- (i) सी.जे.शाह ऐण्ड कम्पनी, मुम्बई
- (ii) हरेश कुमार ऐण्ड कम्पनी, मुम्बई
- (iii) पी.सी.एल. इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली
- (vi) कान्सी लाल मणिलाल ऐण्ड कम्पनी, मुम्बई
- (v) विनमार इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लि., मुम्बई

प्रयोगकर्ता उद्योग

- (1) एक्सप्रो इंडिया, मुम्बई
- (ii) बेकलाइट हाइलम लि., हैदराबाद
- (iii) ग्रांन प्लाई इण्डस्ट्रीज लि. जिला रत्नगिरि, महाराष्ट्र,
- (vi) गार्गी हटेन्स अल्लर्ट्स प्रा. लि., मुम्बई

- (V) आल्टो लेबोरेटरीज लि., दादर, मुम्बई
- (VI) यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड, मुम्बई
- (VII) कलर केम लिमिटेड, बालकुम, थाणे

निर्यातक

- (I) फेनालकेमी जी.एम.बी.एच., जर्मनी
- (II) एसीकेम, इटली
- (III) जार्जिया गलफ कार्पोरेशन, यू.एस.ए.
- (IV) मित्सुई केमिकल्स, टोकियो
- (V) कुम्हो केमिकल कम्पनी, सियोल, कोरिया
- (VI) ताइवान प्रास्परिटी केमिकल कम्पनी, ताइवान
- (VII) मेरिसोल, दक्षिण अफ्रीका
- (VIII)) कोलमार पेट्रोकेमिकल्स ए.जी., स्विटजरलैण्ड
- (IX) आई.सी.सी. केमिकल कार्पोरेशन, च्यूयार्क
- (X) वर्बैष्ट उर केमिस्ट्री इण्टर्स्ट्री - वी.सी.एल., जर्मनी

विदेशी एसोसियेशन

- (I) केमिकल सेपटी मैगेजमेंट सेण्टर, जापान केमिकल इण्टर्स्ट्री एसोसियेशन - जे.सी.आई.ए., टोकियो 100, जापान।
- (II) केमिकल ऐण्ड इलाइंड इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन - (सी.ए.आई.ए.) आकलैण्ड पार्क 2006, दक्षिण अफ्रीका।
- (III) कोरियन पेट्रोकेमिकल इण्डस्ट्री एसोसिएशन - (के.पी.आई.ए.) चोग्न - कू, सियोल, कोरिया।
- (IV) पेट्रोकेमिकल इण्डस्ट्री एसोसिएशन आफ ताइवान (पी.आई.ए.टी.) सेक्शन - 4 चुहुंग, सिन्हु, ताइवान।
- (V) केमिकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (सी.एम.ए.) वर्जीनिया - 22209, यू.एस.ए.

भारतीय एसोसिएशन

- (I) सोसाइटी आफ थर्मो सेटिंग इण्डस्ट्रीज, मुम्बई
- (II) इंडियन लैमिनेट्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, मुम्बई
- (III) इंडियन केमिकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, मुम्बई

2. प्रार्थना पत्र और प्रश्नावली के साथ नोटिस की एक प्रति निर्यातक देशों की सरकारों को दिल्ली स्थित उनके उच्चायोग/राजदूतावासों जैसे दीन, दीनी ताइपेई, जर्मनी, इण्डोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया डी.पी.आर., कोरिया आर.पी., लुहैत, मलेशिया, नीदरलैण्ड, च्यूजीलैण्ड, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, यू.के. और यू.एस.ए. के माध्यम से प्रेषित की गई थी।

3. उसी दिन प्रश्नावलियाँ सभी छात घरेलू उत्पादकों, नियांतकों और आयातकों को भी प्रेषित की गयी थी, जिससे कहा गया था कि वे अपना प्रत्युत्तर 12-3-99 तक प्रस्तुत कर दें ।

4. निम्नलिखित पक्षों द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ावे हेतु अनुरोध किया गया था :-

- (i) हिन्दुस्तान आर्गेंगिक केमिकल्स लिमिटेड, मुम्बई
- (ii) हरड़ीलिया केमिकल्स लिमिटेड, मुम्बई
- (iii) मित्सुइ केमिकल्स इन्क., जापान
- (iv) कुम्हो पी. ऐण्ड बी. केमिकल्स इन्क., सियोल, कोरिया ।
- (v) हरेश कुमार एण्ड कम्पनी, मुम्बई

उनके अनुरोधों को तथा साधियिक अवधि में जांच पूरी कर लेने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 19-3-99 तक समय बढ़ावी अनुमति दी गयी थी और तदनुसार संबंधित पक्षों को सूचित कर दिया गया था ।

5. दिनांक 2-2-1999 के नोटिस और प्रश्नावली के प्रत्युत्तर निम्नलिखित पक्षों से प्राप्त हुए थे :-

घरेलू उत्पादक

- (i) हिन्दुस्तान आर्गेंगिक केमिकल लि., मुम्बई
- (ii) हरड़ीलिया केमिकल्स लिमिटेड, मुम्बई
- (iii) नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि०, नेवेली

आयातक

- (i) सी.जे.झाह एण्ड कम्पनी, मुम्बई
- (ii) हरेश कुमार एण्ड कम्पनी, मुम्बई
- (iii) काच्चीलाल मणिलाल ऐण्ड कम्पनी, मुम्बई

प्रयोगकर्ता संघोग

- (i) गार्गी हटेंस एल्बर्ट्स प्राइवेट लि., मुम्बई
- (ii) आल्डा लेबोरेट्रीज लि., दादर, मुम्बई

नियांतक

- (i) फेनालकेमी जी.एम.बी.एच ऐण्ड कम्पनी, जर्मनी
- (ii) एनीकेम इटली
- (iii) मित्सुइ केमिकल्स इन्क., जापान
- (iv) कुम्हो केमिकल कम्पनी, सियोल, कोरिया

(V) मेरिसोल, दक्षिण कोरिया
 (VI) ताइवान प्रासपरिटी केमिकल कार्पोरेशन, ताइवान

यूरोपीय यूनियन/भारत में यूरोपीय आशोग के प्रतिनिधि मंडल ने भी महानिदेशक (रक्षोपाय) से अनुरोध किया था कि जांच में उन्हें भी इच्छुक पक्ष के रूप में विचार किया जाए। इच्छुक पक्ष के रूप में उनके अनुरोध को ध्यान में रखा गया और यूरोपीय यूनियन/ भारत में यूरोपीय प्रतिनिधि मंडल को तदनुसार सूचित किया गया था ।

भारतीय एसोसियेशन

(i) इंडियन केमिकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन, मुम्बई ।

6. नोटिस का प्रत्युत्तर निम्नलिखित पक्षों द्वारा भी प्रस्तुत किया गया :-

(i) लघु उद्योग भारती, फरीदाबाद
 (ii) इंडियन कोर आयल्स प्रा. लि. फरीदाबाद
 (iii) केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि., मुम्बई
 (iv) मार्बेल थर्मोसेट्स प्रा. लि. मुम्बई
 (v) डि इस्टीट्यूट आण इंडियन फाउण्डीशन, कलकत्ता
 (vi) रोमित रेसिन्स प्रा. लि. पनवेल - 410206
 (vii) फोसिको इंडिया लि., पुणे
 (viii) अतुल लि., गुजरात
 (ix) शेनेकटेडी स्पेशलिटीज एशिया लि., मुम्बई
 (x) सेन्ट्रुरी लैमिनेटिंग कॉ. लि., कलकत्ता
 (xi) ए.बी.सी. प्रोडक्ट्स लि., कलकत्ता
 (xii) किटप्लाई इण्डस्ट्रीज लि., कलकत्ता
 (xiii) बिनलैम इण्डस्ट्रीज लि., कलकत्ता
 (xiv) अण्डमान्स टिम्बर इण्डस्ट्रीज लि., कलकत्ता
 (xv) वण्डुर लैमिनेट्स प्रा. लि., कलकत्ता
 (xvi) किरण ट्रेकिंग कम्पनी, कलकत्ता
 (xvii) यूनाइटेड मेटाकेम प्रा० लि०, पुणे
 (xxviii) फार्मसन फार्मास्यूटिकल गुजरात लि०, बडोदरा

7. जांच के लिए आवश्यक समझी जाने वाली सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए अधिकारियों के दल ने मे० हिन्दुस्तान आर्मिक केमिकल्स लि०, कोटीन, मे० हरहीलिया केमिकल्स लि०, मुम्बई, मे० केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स लि०, मुम्बई, मे० सी.जे. शाह एण्ड कम्पनी, मुम्बई और मे० कान्तीलाल मणिलाल एण्ड कॉ०, मुम्बई के परिसरों का दौरा किया । जांच के परिणामों को संबंधित पक्षों को सूचित कर दिया गया था और जांच रिपोर्ट की एक प्रति को सार्वजनिक फाइल में भी रखा गया था ।

8. सभी इच्छुक पक्षों की एक सार्वजनिक सुनवाई 16.4.99 को आयोजित की गयी थी जिसके लिए नोटिस 19.3.99 को प्रेषित की गयी थी। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान इच्छुक पक्षों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने द्वारा दिये गये मौखिक ढलीलों की लिखित प्रस्तुति 23 अप्रैल 1999 तक दर्ज करायें तथा दूसरों द्वारा दर्ज कराए गए उल्लंघनों को 26 अप्रैल, 1999 को प्राप्त करें और अपना खंडन, यदि कोई हो, तो 7 मई 1999 तक प्रस्तुत कर दें। निम्नलिखित पक्षों ने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया :-

- (i) हिन्दुस्तान आर्गेंशिक केमिकल्स, मुम्बई
- (ii) हरछीलिया केमिकल्स लिं, मुम्बई
- (iii) नेहेली लिंगनाइट कार्पोरेशन, नेहेली
- (iv) ड्यूगाइस बूल्स इण्डिया प्रारूप लिं, प्रतिनिधि फिलाल केमी, जर्मनी
- (v) सैन्युग कार्पोरेशन, मुम्बई, प्रतिनिधि, कुम्हो पी, ऐण्ड बी केमिकल्स, कोरिया
- (vi) सेनेकटेडी स्पेशलिटीज एसिया लिं, मुम्बई
- (vii) कनोरिया पेट्रो प्रोडक्ट्स लिं, नई दिल्ली
- (viii) सेरीकेम - ससोल आर.एस.ए. (पी.टी.वाई.) लिं, दक्षिण अफ्रीका, अपने दिल्ली प्रतिनिधि के माध्यम से
- (ix) एम्बेसी आफ कोरिया, नई दिल्ली
- (x) एम्बेसी आफ जापान, नई दिल्ली
- (xi) यूरोपियन यूनियन, डेलीगेशन आफ डि यूरोपियन कमीशन इन इंडिया, नई दिल्ली
- (xii) सुमीटोनो कार्पोरेशन, जापान
- (xiii) मिल्सुई केमिकल्स/मिल्सुई ऐण्ड कॉ, जापान (वकील के माध्यम से)
- (xiv) यूनाइटेड मेटाकेम लिं, पुणे
- (xv) फोसेको इंडिया लिं, पुणे
- (xvi) आश्र चूगर लिं, नई दिल्ली
- (xvii) हरेश कुमार ऐण्ड कॉ, मुम्बई
- (xviii) केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स लिं, मुम्बई (वकील के माध्यम से)
- (xix) फार्मसन फार्मास्यूटिकल्स, बड़ोदरा
- (xx) गार्गी हटेस्स अल्वट्स, मुम्बई
- (xxi) अबुल लिमिटेड, गुजरात
- (xxii) ए.बी.सी. प्रोडक्ट्स लिं, कलकत्ता
- (xxiii) एलाइल रेसिन्स ऐण्ड केमिकल्स लिं, कलकत्ता
- (xxiv) सेन्युरी लैमिनेटिंग कॉ, लिं, नई दिल्ली
- (xxv) बेकेलाइट हाइलम लिं, हैदराबाद
- (xxvi) इस्टीट्यूट आफ इण्डियन फाउण्ड्रीमेन व लघु उद्योग भारती, फरीदाबाद (अपने अध्यक्ष के माध्यम से)
- (xxvii) आल्टा लेबोरेट्रीज, मुम्बई

(ख) नियांतकों के वृष्टिकोष

नियांतकों द्वारा निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाये गये हैं :-

(क) में० फिनोल केमी जी.एम.बी.एच.एप्ल कं० जर्मनी

(i) उन्होंने फिनाल के नियात बिक्री के अपने रिकार्ड को 1995 से पूरी तरह जांचा और पाया कि भारत में उनके द्वारा सीधी बिक्री नहीं की गयी है।

(ii) फिनाल केमी अन्तर्राष्ट्रीय व्यावसायिक कम्पनियों को छिट्ठ पुट रूप से फिनाल बेचता है और इन मात्राओं के अंतिम गतव्य के बारे में वे जानकारी नहीं रखते हैं। जर्मनी से दिखाये गये आधात शायद इसी कारण हुए हैं।

(iii) पिछले लगभग पच्छह महीनों के दौरान सभी क्षेत्रीय फिनाल बाजारों (यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया) ने मांग और पूर्ति में बढ़ते असंतुलन और कच्चे माल की कीमतों में ऐतिहासिक कमी (क्यूमीन बेस्जीन, प्रापिलीन) के कारण फिनाल की कीमतों में 50% तक की कमी हुई है। इसलिए भारत में भी इसी तरह की स्थितियों का होना कोई आश्वर्य की बात नहीं है। लगातार तकनीकी सुधारों, जिसने वर्तमान फिनाल संयंत्रों को और अधिक लागत-प्रभावी बना दिया है, साथ ही साथ ये आधुनिक विश्व स्तरीय फिनाल संयंत्रों, जिनकी क्षमता 4,00,000 मी.टन प्रति वर्ष तक है, ने इन स्थितियों को और भी बढ़ावा दिया था।

(iv) अगले 24 महीनों के दौरान विश्व भर में लगभग 80000 मी०टन प्रति वर्ष की क्षमता और बढ़ जाएगी। ये ये संयंत्र स्टेट-आफ-डि-आर्ट तकनीक का प्रयोग करेंगे और फिनाल बनाने के लागत प्रभाव से और भी सुधार लाएंगे। वर्तमान बाजार परिस्थितियों के अधीन इस तरह की स्थिति का अधिकांश लाभ विश्व भर में फिनाल उपमोक्ताओं को मिलेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

(v) भारत में सभी फिनाल उपमोक्ता उस लाभ में सम्मिलित होने के अवसर का स्वागत करेंगे जिसे आधुनिक, अन्तर्राष्ट्रीय फिनाल उद्योग देखे में समर्थ होगा।

(ख) मित्सुइ केमिकल्स इन्क०, जापान

(i) फिनाल के भारतीय विनिर्माता प्रार्थी भारत ने एकाधिकार की स्थिति में हैं। (जैसा उन्होंने स्वयं दावा किया है कि वे घरेलू बाजार का 91% तक का नियन्त्रण रखते हैं) और ऐसा लगता है कि वर्तमान प्रार्थना पत्र का उपयोग उस एकाधिकारवादी स्थिति को बनाये रखने के लिए एक औजार के रूप में किया जा रहा है। इस समय जिन मुद्दों की शिकायत की गयी हैं, उनमें से अधिकांश मुद्दे पिछले बर्षों में भी रहे हैं, जिन बर्षों में प्रार्थीयों ने 94% से अधिक उपयोगिता क्षमता को प्राप्त किया था, जिससे स्पष्ट है कि इन कारकों ने उन्हें महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं किया था। यह स्पष्ट है कि नियात में तीव्र गिरावट, जो यह संकेत करता है कि प्रार्थी अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अप्रतिस्पर्धी हो चुके हैं, ही वर्तमान प्रार्थना पत्र का कारण है जिसका अनिप्राय भारतीय बाजार के एकाधिकारवादी प्रमुख को बनाये रखना है।

(ii) मौगी गयी प्रभावी लेवी की मात्रा से भी यह संकेत मिलता है कि प्रार्थीयां अपने लिए लाभ के एक स्तर को बनाए रखने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वर्तमान रुझान से संबंधित नहीं है। यह पूरी तरह भारतीय घरेलू उपयोगकर्ता उद्योग की लागत को प्रभावित करके ही होगा। यह कार्रवाई पूरी तरह भारतीय

उद्योग के लिए हानिकर लगती है और दो प्रार्थनियों के लिए अवास्तविक कीमत/लाभ वसूलने के लिए तथा बाजार में प्रमुख बनाये रखने के लिए बहुत संकीर्ण परिप्रेक्ष्य के लिए की गयी लगती है।

(iii) यह प्रार्थना पत्र किसी 'गंभीर क्षति' को दिखाने में असफल रहा है तथा विशेष रूप से आयात और दर्शायी गयी क्षति के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने में भी असफल रहा है।

(iv) यह प्रार्थना पत्र किसी 'गंभीर परिस्थिति' को और विशेष रूप से 'अपूरणीय क्षति' को स्थापित करने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप अनन्तिम शुल्क के अधिशेषण के लिए अनुरोध मानने योग्य नहीं लगता है।

(v) प्रार्थना पत्र कुछ गंभीर मुद्दों पर चुनी हुई और अनुचित रूप से सूचनाएँ प्रदर्शित करता है। इस तरह का एक उदाहरण उत्पादन क्षमता उपयोगिता के रूप में सूचना के संबंध में है जिसके लिए "घरेलू मौंग को पूरा करने के लिए क्षमता की उपयोगिता" के संबंध में आंकड़े दिए गए हैं। जो उल्लेख किया जाना आवश्यक था, वह आंकड़े हैं जो उत्पादन के सभी स्रोतों के लिए सम्पूर्ण उत्पादन क्षमता उपयोगिता के हैं, न कि केवल वह सूचना है जो घरेलू मौंग के लिए क्षमता उपयोगिता हेतु प्रासंगिक है। इस मुद्दे पर विचार करना, मौंगी गयी क्षति के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रस्तुत स्थानात्मक सूचनाओं से अर्थ निकलता है कि आवेदन कर्ताओं ने जानबूझ कर उस आवश्यक सूचनाओं को छिपाने की दृष्टि से यह कार्य किया है जो उनके लिए हानिकर ढो सकती थीं।

(vi) क्षति के मुद्दे पर, रोजगार आदि के साथ-साथ विभिन्न प्रस्तुतियों मुद्दों को संदर्भित नहीं किया गया है जिससे यह संकेत मिलता है कि इन मुद्दों पर सूचनाएँ प्रार्थी के मामले का समर्थन नहीं करती हैं।

(vii) आवेदन कर्ताओं के विभिन्न प्रस्तुतियों के समर्थन में सूचना के स्रोतों का उल्लेख नहीं किया गया है या बाजार सूचना स्रोत के रूप में किया गया है। इस प्रकार के बाजार सूचना स्रोत स्पष्ट रूप से कमज़ोर हैं और सत्यापन के समय टिक नहीं सकते हैं, इससे प्रार्थना पत्र दोषपूर्ण हो जाता है।

(viii) विभिन्न आंकड़े जैसे घरेलू मौंग के आंकड़े पूर्ण आंकड़े नहीं हैं। गणितीय सूत्रों का प्रयोग करके तैयार किए गए हैं। इसलिए इस प्रकार के आंकड़े सही स्थिति को नहीं दर्शाते हैं।

(ix) लाभ के प्रतिशत में गिरावट के संबंध में दिए गए कुछ आंकड़े उत्तर स्थिति को शुद्ध रूप से प्रदर्शित करते हुए दिखाई नहीं पड़ते जो कि प्रार्थी कम्पनी के आडिट किए हुए प्रकाशित कुछ एकाउण्टों में दिए गए हैं। ऐसा प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थनापत्र की विश्वसनीयता के संदर्भ में यह कुछ गंभीर समस्या का मामला है।

(x) उत्पादन में गिरावट के संबंध में, यद्यपि हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. (एच.ओ.सी) और हरडीलिया केमिकल्स लि. (हरडीलिया) उल्लेख करते हैं कि फिनाल का घरेलू उत्पादन 1997-98 से 1998-99 तक गिर रहा है, तथापि घरेलू फिनाल की मौंग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है। सम्पूर्ण उत्पादन में गिरावट के कारण नियोत में कभी होनी चाहिए जो कि एच.ओ.सी और हरडीलिया के नियन्त्रण में है, न कि आयात में वृद्धि।

मी० टन

अवधि	1997-98 (रु)	1998 दिसम्बर तक (बी)	1998-99 (अगुस्त)	अन्तर (बी x 4/3=सी)
कुल घरेलू उत्पादन (एक्स)	69,281	48,703	64,937	- 4,344
निर्यात (वाई)	7,675	52	69	- 7,606
घरेलू मौग को पूरा करने हेतु घरेलू उत्पादन (एक्स - वाई)	61,606	48,651	84,868	3,262

(xi) एच.ओ.सी. और हरडीलिया दूसरे देशों को अपने फिनाल करके अपना सम्पूर्ण उत्पादन (घरेलू मौग और निर्यात दोनों के लिए) बढ़ा सकते थे जैसा कि उन्होंने पहले के वर्षों में किया था। भारत में रक्षोपाय शुल्क के उद्ग्रहण का कोई प्रभाव एच.ओ.सी. और हरडीलिया द्वारा दूसरे देशों को किए गए फिनाल के निर्यात पर नहीं है जो कीमत में उनकी स्वयं की अस्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा पर और उनके उत्पाद की गुणवत्ता पर निर्भर करता है।

(xii) क्षमता उपयोगिता के संबंध में, घरेलू मौग को पूरा करने के लिए एच.ओ.सी और हरडीलिया की क्षमता उपयोगिता दर 86% पर स्थिर है जैसा कि मिम्लिखित सारणी से प्रमाणित होता है :-

मी० टन

अवधि	1997-98	1998-99 (दिसम्बर तक)
एच.ओ.सी. और हरडीलिया की उत्पादन क्षमता	71,500	56,250
घरेलू मौग को पूरा करने हेतु घरेलू उत्पादन	61,606	48,651
घरेलू मौग को पूरा करने हेतु क्षमता उपयोगिता	86.2%	86.5%

(xiii) प्रार्थना पत्र में दिए गए आंकड़े, घरेलू मॉग के लिए क्षमता उपयोगिता के आंकड़े हैं, जो संदर्भ हेतु समुचित आधार नहीं हैं क्योंकि उत्पादन के सभी स्त्रोतों में क्षमता उपयोगिता पर विचार किया जाना अपेक्षित है। क्षमता उपयोगिता का एक विश्लेषण दिखाता है कि घरेलू बिक्री और निर्यात को ध्यान में रखने पर पहले की अवधि में क्षमता उपयोगिता बहुत अधिक थी। उदाहरण के लिए वर्ष 1995-96 में क्षमता उपयोगिता 99.56% है। रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रार्थियों के लिए निर्यात बाजार में महत्वपूर्ण गिरावट रही है और क्षमता उपयोगिता में कोई गिरावट का सीधा असर, अन्य के साथ-साथ इस तथ्य पर भी पड़ता है कि प्रार्थियों अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाये हैं।

(xiv) आवेदनकर्ताओं ने उल्लेख किया है कि भारत में सी.आई.एफ. मूल्य के आधार पर फिनाल की कीमत जनवरी 1998 और सितम्बर 1998 की कीमत को तुलना में अन्य क्षेत्रों की कीमत के मुकाबले अधिक तेजी से गिरी है, फिर भी, अन्य अवधि में की जाने वाली तुलना एक दूसरा दृश्य प्रस्तुत करेगी। फिनाल विश्व भर में बेता जाना वाला उत्पाद है और इसकी कीमत में गिरावट अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत में गिरावट के कारण है। भारत में गिरावट की दर का स्तर अन्य क्षेत्रों की तरह ही है।

(xv) यद्यपि एच.ओ.सी. और हरड़ीलिया अपने आवेदन पत्र में प्रत्येक नौमरण के आयात कीमत को प्रदर्शित करते हैं, फिर भी वे इस विचार के हैं कि 395 अमरीकी डॉलर प्रति भी.टन एक अपवाद स्वरूप मामला है और सामान्य विचार के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना आहिए।

(xvi) विश्वायीकरण के वर्तमान दौर में, स्थानीय कीमतें भी अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों का प्रतिविन्द्र हैं। जैसा आवेदन पत्र से संकेत मिलता है कि आवेदनकर्ताओं की भारत के अम्बर बने रहने में समर्थ हो सकने की भक्षा है। (भारतीय घरेलू उपयोगकर्ता उद्योग की कीमत पर), और पहले की तरह लाभ कमाते रहें, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के प्रभाव को पहचान पाने में पूर्णतः असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदन कर्ता इन कार्यवाहियों का उपयोग, लाभ के अवास्तविक स्तर के लिए प्रयत्न करने और उसे प्राप्त करने हेतु कर रहे हैं, जिसे वे भारतीय बाजार के अपने एकाधिकारवादी प्रमुख की दृष्टि से इस्तेमाल कर सकें।

(xvii) दोनों आवेदनकर्ताओं के बिक्री आंकड़ों का परीक्षण यह दिखाता है कि हरड़ीलिया के बिक्री आंकड़ों ने लगातार बढ़िया को ही प्रदर्शित किया है। बढ़िया का यह प्रतिस्लप वर्ष 1998-99 के लिए दिए गए वार्षिक आंकड़ों के अनुसार ही है। जहाँ तक एच.ओ.सी. का संबंध है, दिए गए आंकड़े 1991-92 और उसके बाद से बिक्री के उत्तर-दक्षाव वाले रुझान को प्रदर्शित करते हैं। 1998-99 के लिए योजनालक्षण बिक्री भी बिक्री के इस उत्तर-दक्षाव वाले रुझान का प्रतिविन्द्र है जो पहले एच.ओ.सी. के लिए थी। इसलिए प्रश्नगत आयात, आवेदनकर्ताओं को उनके बिक्री के संदर्भ में कोई गंभीर क्षति पहुँचाने वाला प्रतीत नहीं होता है।

(xviii) जहाँ तक तैयार हो चुके स्टाक का मुद्दा है, एच.ओ.सी. के स्टाक की स्थिति का परीक्षण स्पष्ट करता है कि इसने भी उत्तर-दक्षाव वाले प्रतिमान को प्रदर्शित किया है, यह प्रतिमान 1998-99 और उसके बाद जी बना रह सकता है। जहाँ सक्त हरड़ीलिया का संबंध है, समाप्त रुझान के उनके आंकड़ों का परीक्षण उनके पहले के निर्यात की तुलना के संदर्भ में किया गया, उन्होंने 1997-98 और 1998-99 में कोई निर्यात नहीं किया था, इससे स्पष्ट होता है कि स्टाक का जमा होना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा को बनाये रखने में असफलता के कारण है। इसलिए प्रश्नगत आयात आवेदनकर्ताओं के स्टाक की स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं ढानता है।

(xix) आवेदनकर्ताओं के विभिन्न प्रकार के प्रकाशित दस्तावेज और रेटर्म स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि इन कार्यवाहियों के लिए संकटपूर्ण विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने विशेष रूप से विवरण दिया है, जहाँ लाभ में कमी के संबंध में विस्तृत कारण दिये गये हैं। इन विवरणों में वास्तव में विच्छयपूर्वक अधिक बिक्री की साज़ा के संबंध में कहा गया है। दिये गये बहुत से कारण - अप्रत्यक्ष करों का उद्ग्रहण, स्थानीय करों का अधिरोपण, बिजली की समस्या, बन्दरगाहों पर अपर्याप्त डॉकागत सुविधाएं आदि हैं। इसलिए आवेदनकर्ताओं को क्षति, यदि कोई है, तो उसके कारक और मुद्दे आयात के अलावा हैं।

(xx) यह प्रासंगिक है कि रक्षोपाय कार्यवाही उन अन्य कार्यवाहियों से मिलते हैं जिसे क्षति को स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है, रक्षोपाय कार्यवाही को 'गमीर क्षति' को स्थापित करने की विशेष आवश्यकता होती है। वर्तमान मामले में, अपेक्षित गमीर क्षति या इस मामले के लिए क्षति भी स्थापित नहीं की गयी है। क्षति का मूल्यांकन इच्छुक घरेलू उद्योग के सदर्भ में और इस प्रकार के घरेलू उद्योग के हित के संतुलन पर किया जाना आहिए। वर्तमान कार्यवाही घरेलू उपयोगकर्ता उद्योग के व्यापक हितों की ही कीमत पर आवेदनकर्ताओं के केवल संकीर्ण हितों को सुरक्षित करने के लिए ही है। उनका विश्वास है कि आवेदनकर्ताओं द्वारा की जाने वाली आपूर्तियाँ गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हैं और उन्हें पुनः संसाधित किये जाने की आवश्यकता है, और यह कि आवेदनकर्ता सुपुर्दगी के समय सारणी के अनुपालन में असमर्थ है और उन्होंने विवरण और मूल्य की ऐसी रणनीति अपनायी है जो स्थानीय भारतीय उपभोक्ताओं को पूरी तरह स्वीकार्य नहीं है।

(xxi) फिनाल के घरेलू उपभोग (आयात सहित) में 1997-98 से 1998-99 तक बहुत अधिक वृद्धि हुई है। यद्यपि एच.ओ.सी. और हरडीलिया ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन में वृद्धि की है किन्तु वे घरेलू मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए इस प्रकार के बढ़े हुए उपभोग को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए, भारत में फिनाल के उपयोगकर्ताओं को अपने उत्पादन के लिए फिनाल का आयात करना पड़ता था। घरेलू उपभोग में एच.ओ.सी. और हरडीलिया के अंशदान में गिरावट का कारण उनके द्वारा और अधिक फिनाल के उत्पादन में असफलता है, यद्यपि उनके पास अधिक उत्पादन क्षमता है, और यह आयात में वृद्धि के कारण नहीं है।

(xxii) 72% की दर से मौंगे गये रक्षोपाय शुल्क की एच.ओ.सी. और हरडीलिया की गणना, लगायी गयी पूँजी पर 12% समुचित प्रतिफल के रूप में प्रयोग करते हुए उनके न्यूनतम उधित कीमत पर आधारित है। आज 12% की यह दर वस्तु रसायनों के विनिर्माताओं के लिए अनुचित रूप से बहुत अधिक है और यहाँ तक कि एच.ओ.सी. और हरडीलिया द्वारा पहले वसूली गयी जाम की दरों से भी अधिक है। वर्ष 1995-96 में एच.ओ.सी. ने 14.20% का लाभ अर्जित किया था, किन्तु उस अधिक के दौरान रसायन उत्पादों की कीमतें अपवाद स्वरूप बहुत ऊँची थीं और ये कीमतें 1997 में गिरी।

(xxiii) भारत में फिनाल की मौंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। विभिन्न प्रकार के फिनाल व्युत्पन्नों के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मूल रसायनों में से फिनाल एक है। इन फिनाल व्युत्पन्नों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में जैसे प्लाईवुड उद्योग से लेकर विद्युत उपकरण उद्योग अथवा औषधि उद्योग में किया जाता है जो गमीर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में है। फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से फिनाल चाहने वाले बहुत से विनिर्माताओं की कीमत पर केवल दो घरेलू फिनाल उत्पादकों को लाभ होगा। इन विनिर्माताओं के विकास में देरी से भारत की सामान्य अर्थ व्यवस्था पर अपर्याप्त विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वे स्वीकार करते हैं कि घरेलू फिनाल उत्पादक फिनाल पर घटे

हुए आयात शुल्क से कटिलाई का अनुभव कर रहे हैं। फिर भी, भारत में फिनाल पर आयात शुल्क दर अब भी अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है।

(xxiv) छूकि घरेलू फिनाल उत्पादकों की उत्पादन क्षमता भारत में फिनाल की कुल मौग को पूरा नहीं कर सकती है, इसलिए फिनाल उपयोगकर्ताओं को, रक्षोपाय शुल्क लगाने के बाद भी, आयातित फिनाल खरीदना पड़ेगा। अन्सर्ट्स्ट्रीय बाजार की कीमत से अधिक कीमत पर फिनाल प्राप्त करना उन उपयोगकर्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मकता को गंभीर रूप से कम करेगा। भारत में फिनाल उपयोगकर्ताओं द्वारा उनसे अमुरोध किया गया है कि वे उन्हें उच्च गुणवत्ता का फिनाल प्रतिस्पर्धी दर पर आपूर्ति करें जिसे घरेलू फिनाल उत्पादक प्राप्त करने में असमर्थ हैं, और आशा करते हैं कि मित्सुई द्वारा निमित फिनाल की लगातार आपूर्ति करके वे उनका सहयोग करें।

(ग) मेरीसोल, दक्षिण अफ्रीका

(i) मेरीकेम-ससोल आर.एस.ए. (पी.टी.वाई.) लिं. (मेरीसोल आर.एस.ए.) और इसके पूर्ववर्ती ससोल फेनोलिक्स, अपने वितरक एजेंट में कनोरिया पेन्ट्री प्रोडक्ट्स लिं. तथा इसके साथ ही साथ आई.सी.सी केमिकल कार्पोरेशन के भारत में प्रतिनिधि कार्यालय के माध्यम से भारतीय बाजार में फिनाल के बड़े स्थाई आपूर्तिकर्ता रहे हैं।

(ii) भारत में बड़े उत्पादकों द्वारा उत्पादित सिस्टेटिक फिनाल के विपरीत, मेरीसोल आर.एस.ए प्राकृतिक फिनाल के आपूर्तिकर्ता हैं जो सम्पूर्ण विश्व की कुल उत्पादन क्षमता के 1% से कम है। घरेलू दक्षिण अफ्रीकी मौग से अधिक उत्पादन करके मेरीसोल आर.एस.ए., अति विस्तृत भूमडलीय आधार पर अपने फिनाल को बाजारों में निर्यात करने की रणनीति को अपनाता है। एक छोटे उत्पादक के रूप में मेरीसोल आर.एस.ए कीमत निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है, बल्कि यह घरेलू और अन्सर्ट्स्ट्रीय बाजार - परिस्थितियों द्वारा निर्देशित कीमतों के अनुसार अपनी कीमतें समायोजन करने की रणनीति को अपनाता है।

(iii) भारतीय बाजार में फिनाल की कीमतों का सम्बन्ध विश्व बाजार की कीमतों से है जिनमें भारत में अन्सर के कारण कुछ विसंगतियाँ हैं। जैसा कि आई.सी.आई.एस. - एल.ओ.आर. द्वारा 1999 के प्रथम तिमाही में रिपोर्ट किया गया है, संसार के विनियन क्षेत्रों में कीमतें 410-450 अमरीकी डालर प्रति मी.टन. सी.एफ.आर. (टक्की पूर्व एशिया), 400-430 अमरीकी डालर प्रति मी.टन. सी.आर.एफ. (चीन) से 430-470 अमरीकी डालर प्रति मी.टन. ग्राहक पर एफ.डी. (यूरोप) तक हैं। उनके अनुभव के अनुसार आई.सी.आई.एस. - एल.ओ.आर. द्वारा बतायी गयी कीमतें बाजार में वसूली गयी वास्तविक कीमतों से हमेशा अधिक हैं। उनकी सूचना के अनुसार, उसी अवधि के दौरान भारतीय बाजार में प्राप्त की गयी कीमतें 400-420 अमरीकी डालर प्रति मी.टन. सी.आई.एफ. रही हैं।

(iv) विश्व की फिनाल कीमतें, संसार भर में फिनाल की मौग और पूर्ति के संतुलन से उत्पन्न परिणाम के फलस्वरूप हैं। पण्य उत्पाद होने के कारण, विश्व भर में फिनाल की कीमतें एक ही ऊँझान के अनुरूप होती हैं। जैसा कि इसी सिद्धान्त के आधार पर इसके उपभोक्ता और उत्पादक कीमतों के स्तर को स्थापित करते हैं। ऊपर उद्धृत कीमतों के स्तर और साथ ही साथ 1998 के प्रथम तिमाही के दौरान पायी गयी कीमतों के ऊंचे स्तर से यह प्रमाणित है, 660-710 अमरीकी डालर प्रति मी.ट. सी.एफ.आर. (द पू.एशिया), 670-700 अमरीकी डालर प्रति मी.ट. (चीन) और 780-820 अमरीकी डालर प्रति मी.ट एफ.डी. ग्राहक पर (यूरोप)। उनकी सामान्य सूचना के अनुसार, उसी अवधि के दौरान भारत में 670-700 अमरीकी डालर प्रति मी.ट. (सी.आई.एफ.) की कीमत के स्तर पर फिनाल का व्यापार हुआ।

(v) फिनाल के कुल आयातके रूपमें, भारत के उपभोक्ता अपनी मांग को पूरा करने हेतु उसके आयात पर इस आशा के साथ निर्भर करते रहेंगे कि देशमें आर्थिक विकास होगा, घाटा निश्चित रूप से बढ़ता रहेगा।

(vi) फिनाल पर आयात के विरुद्ध रक्षोपाय शुल्क को लागू करना भारतमें ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रोंमें तथा विश्व बाजारमें भी उसकी माँग और पूति में असंतुलन को नियन्त्रित करने के लिए हानिकार होगा और ऐसी बाजार परिस्थिति को निर्माण करेगा जिसे सुधारनेमें बहुत अधिक समय लगेगा।

(vii) इसलिए भारतमें व्यापार जारी रखने के प्रति समर्पित कम्पनी के रूपमें नियंत्रित आर.एस.ए. शोडे समय के लिए भी फिनाल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क लागू करनेपर अपनी वित्ती प्रकट करने की इच्छा रखता है।

(घ) एनीकेम, इटली

(i) वित्त वर्ष 1996-97में सम्पूर्ण आयात के मूल्यमें 1% और मात्रा में 0.08% की न्यूनतम गिरावट के साथ पूरे उर्ष भरमें भारतमें उनका निर्यात कम होता रहा है।

(ii) एनीकेम अपने उत्पादन के सीधे और एनीकेम के शाखा कार्यालयों के माध्यमसे, दोनों तरफ से बेचता है, शेष संसार के लिए बहुत कम अवसरोंपर फिनाल की अति अल्प मात्रा को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारियों को बेचा गया। उनका मुख्य बाजार यूरोप है और केवल अति अल्प मात्रा में (कुल बिक्री का लगभग 1%) सेष संसार को भेजा जाता है।

(iii) एनीकेम की सामरिक बाजार नीति घरेलू बाजार शेयर को यथासंभव सबसे ऊंचा (70% से अधिक) रखते हुए इटली के बाजार की सेवा करना है। उनकी दूसरी प्राथमिकता मुख्य यूरोपीय ग्राहकों, जैसे बिसफेनाल-ए के उत्पादकों, के बढ़ते हुए उपभोग का अनुसरण करना और यूरोपीय बाजारमें अपनी उपस्थिति बनाये रखना है। सामान्यतः कैप्टिव प्रयोग हेतु उपभोग किये जाने वाले फिनाल का लगभग 50% उत्पादन एनीकेम करता है।

(iv) उनकी क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्री मूल्य, भारत की निर्यात का मूल्य, निर्यात की मात्रा के विवरण निम्नानुसार थे :-

वर्ष	क्षमता (के.टी.)	उत्पादन (के.टी.)	अमरीकी डालरमें मूल्य घरेलू	निर्यात (भारत) (बजट)	भारत की निर्यातित मात्रा (एम.टी.)
1996	390	373	648	850	198
1997	390	373	560	738	16.3
1998	395	343	525	--	--
1999	395	345	450	--	--
		(बजट)	(बजट)		

(द) कुम्हों पी एण्ड बी केमिकल इन्क. सियोल, कोरिया

(i) कम्पनी ने वर्ष 1998-99 के दौरान अपनी क्षमता, उत्पादन, उत्पादन की लागत, घरेलू बाजार में बिकी मूल्य और भारत में प्रति यूनिट निर्णीत मूल्य के संबंध में कुछ विवरण प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है :-

	1998	1999
क्षमता	1,20,000	1,20,000
उत्पादन	1,24,248	1,24,000
उत्पादन लागत	416 अमरीकी डालर	411 अमरीकी डालर
घरेलू उद्योग में बिकी मूल्य	450 अमरीकी डालर	450 अमरीकी डालर
निर्णीत मूल्य	437.06 अमरीकी डालर	—
	एफ ओ.बी. कोरिया	

(ii) कम्पनी ने यह भी उल्लेख किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्होंने निम्नानुसार फिनाल का निर्णीत किया है -

1996	2009 मी.टन
1997	4351 मी.टन
1998	9801 मी.टन
1999	शून्य

(य) ताइवान प्रास्परिटी केमिकल कार्पोरेशन

(i) 1996 से 1998 तक उनका भारत में फिनाल का निर्णीत क्रमशः 3089 मी.टन, 3519 मी.टन, और 999 मी.टन था। उनका आर्डर प्रति वर्ष कभी-कभी ही नीमरण किया जाता है और 1998 में निर्णीत किये गये कुल फिनाल की मात्रा महत्वपूर्ण रूप से कम हुई है और 1997 में 3519 मी.टन से घटकर 1998 में केवल 999 मी.टन रह गयी है और भारत में उनके कोई एजेण्ट नहीं हैं।

(ii) उन्होंने साइक्लोहेक्सान का उत्पादन आरम्भ किया जिसे फिनाल की आवश्यकता होती थी। चूंकि कभी-कभी इस नई मांग को पूरा करने के लिए उनके अपने फिनाल का उत्पादन अपर्याप्त रह जाता है, इसलिए उन्होंने फिनाल आयात करने की आवश्यकता पड़ती है। चूंकि उनका स्वयं का उत्पादन उनकी आवश्यकताओं के लिए इस समय अपर्याप्त है, इसलिए वे फिनाल का निर्णीत आक्रमक रूप से नहीं कर सकते हैं।

(iii) ताइवान प्रास्परिटी केमिकल्स कार्पोरेशन ने सदैव बहुत ऊंचे नैतिक स्तर के साथ कार्य किया है और ताइवान में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा को अर्जित किया है। कम्पनी का प्रबन्धन दृढ़ता से विश्वास करता है कि व्यापार के सभी क्षेत्रों में नैतिक ईमानदारी की आवश्यकता होती है। परिणाम स्वरूप उनकी कम्पनी ने सदैव ताइवान में प्राधिकारियों के नियमों और विनियमों का आदर और अनुपालन किया है। विदेशी कम्पनियों के साथ कार्य करते

समय विदेशी प्राधिकारियों द्वारा तैयार किये गये नियमों और विनियमों का उन्होंने पूर्णतः अनुपालन किया है। भारत में फिनाल का व्यापार करने वाली कम्पनियों के साथ व्यापार करते समय यहाँ की सरकार द्वारा नियंत्रित संबंधित कानूनों का उन्होंने अनुसरण किया है।

(ग) नियंत्रित देशों के दृष्टिकोण

(क) यु.के.

व्यापार और उद्योग विभाग लंदन ने ब्रिटिश उच्चायोग, नई दिल्ली के माध्यम से उल्लेख किया है कि वर्तमान में भारत में फिनाल बाजार में ड्रिटेन को कोई लाभ नहीं है और भारत में फिनाल के बड़े तुर आयात के विरुद्ध रक्षोपाय जांच शुल्क करने के विरुद्ध उन्हें कोई आधिकारिक आपत्ति नहीं है।

(ख) जापान

भारत में फिनाल के आयात में वर्तमान दृष्टि घरेलू मांग में दृष्टि के कारण है जो कि घरेलू उत्पादन क्षमता से अधिक है। घरेलू उत्पादकों द्वारा घरेलू परेषण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वर्तमान मारी गिरावट के बाद भारतीय कम्पनियों में मूल्य प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण भारतीय उत्पादकों द्वारा नियंत्रित में अक्षणक कमी को समझा जा सकता है। इसीलिए यह आवश्यक रूप से स्पष्ट नहीं है कि क्या आयात में तीव्र दृष्टि और घरेलू उद्योगों को गम्भीर क्षति की आशंका के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए उपरित आधार है या नहीं। किसी भी तरह रक्षोपाय उपायों के अधिशेषण का संबंध आवश्यकता के लिए समझा जाना चाहिए एवं इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। यदि रक्षोपाय उपायों को लागू करना ही था तो इन्हें डब्ल्यूटीओ. समझौते में अनुबन्ध पूर्व अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए और इसकी आवश्यकता की भावना और अवधि सख्ती से निर्मित होनी चाहिए।

क्या रक्षोपाय शुल्क का अधिशेषण किया जाए? इससे न केवल संबंधित उत्पाद के उपभोक्ता प्रभावित होंगे, बल्कि पूरा उद्योग जगत प्रभावित होगा। भारत सरकार द्वारा भविष्य में अपनाये गये उपायों को जापान बड़ी गम्भीरता के साथ देखेगा।

(घ) भारतीय संगठनों के दृष्टिकोण

कुछ व्यापार संगठनों एवं आई.सी.एम.ए. ने निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाए हैं :

इंडियन केमिकल मैन्यूफैचरर्स एसोसिएशन, मुंबई

(i) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और हड्डीलिया केमिकल्स लिमिटेड, आई.सी.एम.ए के सदस्य हैं और उन्होंने रसायनों पर उच्च स्तर के शुल्क तक फिनाल पर सीमा शुल्क के पुनः स्थापन के लिए प्रार्थना की है। उनकी इस प्रार्थना पर ट्रेड एण्ड विजनेस डेवलपमेंट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में अनुकूल दृष्टि से विचार किया गया था और उन्होंने भारत सरकार को संस्तुति की है कि फिनाल पर सीमा शुल्क उच्च स्तर पर पुनः स्थापित किया जाए।

(ii) फिनाल ने पिछले तीन दशकों से केमिकल उत्पादों पर लागू सीमा शुल्क की अधिकतम दर को

आकृष्ट किया है। तथापि पिछले 4 वित्तीय वर्षों के दौरान फिनाल पर शुल्क कम स्तर पर निर्धारित किया गया था। 1998-99 के केंद्रीय बजट में फिनोल पर मूल सीमा शुल्क (25%), अन्य रसायनों पर (30%) शुल्क से कम रही है।

(iii) फिनाल, ब्लाक स्टेज बनाने (बेर्जीन और प्रोपिलीन) से लेकर कई स्तरों की प्रक्रिया के पश्चात् निर्मित किया जाता है। उदारीकरण के साथ, बेर्जीन और प्रोपिलीन पर आयात शुल्क 10% तक घटा दिया गया है। इसके अलावा, पिछले कुछ वर्षों में फिनाल पर सीमा शुल्क और इसके आयात योग्य फीड स्टाक बेर्जीन पर शुल्क का अन्तर 70% से घटकर 15% तक आ गया जिससे कि घरेलू निर्माताओं को उपलब्ध मूल्य वृद्धि की संभावना में गम्भीर कटौती हुई है।

(ख) सघु उत्थान भारती, फरीदाबाद

(i) यह एक तथ्य है कि भारत में फिनाल का निर्माण हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एच.ओ.सी.) एवं हड्डीलिया केमिकल्स लि. द्वारा किया जाता है और इन दोनों निर्माताओं का एकाधिकार है। इन्हें एकाधिकार अधिनियम के अधीन किया जाना चाहिए।

(ii) यह बिल्कुल असत्य है कि भारत में फिनाल के वर्धित आयात से घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति हुई है।

(iii) फिनाल के वर्धित आयात ने फिनाल के घरेलू उत्पादकों को कोई गम्भीर क्षति नहीं पहुँचाई है। सच्चाई है कि इस व्यापार में इन दोनों विनिर्माताओं का एकाधिकार है और जब कमी भी इनकी इच्छा हुई इन्होंने फिनाल की कृत्रिम कमी दिखा कर इसका मूल्य बढ़ाया। फिनाल की कमी छलयोजित थी और फिनाल बहुत उच्च दरों पर बेचा गया।

(iv) भारत में फिनाल के आयात पर कोई रक्षोपाय शुल्क शुरू करने का कोई औपचित्य नहीं था और वास्तव में फिनाल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए कोई आधार नहीं है।

(v) फिनाल की कमी क्यों उत्पन्न की जाती है और तभी घरेलू उत्पादकों द्वारा मूल्य 25% से 50% बढ़ाकर इसे कैसे उपलब्ध करा दिया जाता है, इसके बारे में जाव शुरू की जानी चाहिए।

(ग) दी इन्स्टीट्यूट आफ इंडियन फार्मासीमेन, कलकत्ता

(i) वे देश में 6000 से अधिक फार्मासी का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले 50 वर्षों में फार्मासीयों में फिनाल का अकाल पड़ गया और निर्माताओं ने जब चाहा अपने मूल्य बढ़ा दिये। विनिर्माताओं ने विशेष तरीके अपना कर कृत्रिम कमी उत्पन्न की। भारत में आयातित फिनाल पर रक्षोपाय आयात शुल्क आदि के उद्यग्रहण का कोई औपचित्य नहीं है।

(ii) पिछले पचास वर्षों में पहली बार पिछले दो महीनों में फिनाल के मूल्य कम हुए और फिनाल के

विनिर्माताओं को उपभोक्ताओं से सम्पर्क करना पड़ा, अन्यथा हमेशा उपभोक्ताओं को ही विनिर्माताओं से सम्पर्क करना पड़ता था। इसीलिए फिनाल पर कोई अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है जबकि वर्तमान मूल्य जो घरेलू उत्पादक लेते हैं वह फिनाल के अंतर्राष्ट्रीयमूल्य से अधिक है।

(छ) आयातक/उपभोक्ता उद्योगों के दृष्टिकोण

उन्होंने निम्ननिखित मुख्य मुद्दे उठाए हैं :-

(क) इंडियन कोर आयल्स प्राइवेट लि. फरीदाबाद

- (i) ये फिनाल के उपभोक्ता हैं और फिनाल पर आधारित विभिन्न प्रकार के रेसिन्स का निर्माण करते हैं।
- (ii) यह एक तथ्य है कि भारत में फिनाल का निर्माण हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. और हड्डीलिया केमिकल्स लि. द्वारा किया जाता है और ये दोनों विनिर्माता एकाधिपत्य रखते हैं। इन्हें एकाधिपत्य अधिनियम द्वारा शासित किया जाना चाहिए।
- (iii) यह बिल्कुल गलत है कि भारत में फिनाल के वर्धित आयात से घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति हुई है।
- (iv) ये फाउंड्रीज द्वारा प्रयुक्त होने वाले रेसिन्स का निर्माण कर रहे हैं। इन दिनों फाउंड्रीयों ने रेसिन्स का आयात शुरू कर दिया है और बहुत सी बड़ी फाउंड्रीयों मार्टीय विनिर्माताओं से रेसिन्स नहीं खरीद रही हैं क्योंकि उन्हें इसका आयात करना सस्ता पड़ता है। यह एक तथ्य है कि फिनाल के विनिर्माण में आवश्यक रसायनों के कच्चे माल फार्मलडीहाइड, क्यूरान रेसिन्स आदि विदेशों में सस्ते हैं। उदाहरणार्थ मैथानोल, जो कि आवश्यक मूल कच्चा माल है, यू.एस. डालर 90 प्रति मीट्रिक टन से कम की दर से बेचा जाता है जबकि भारत में मैथानोल 200 डालर प्रति मीट्रिक टन अधिक है। इसी प्रकार की स्थिति रेसिन्स विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाले अन्य माल पर भी है।
- (v) फिनाल जैसे कच्चे माल के आयात पर शुल्क में वृद्धि का वास्तव में कोई औचित्य नहीं है।
- (vi) फिनाल के वर्धित आयात ने फिनाल के घरेलू उत्पादकों को कोई गम्भीर क्षति पैदा नहीं की है। सच्चाई यह है कि इस व्यापार में इन दोनों निर्माताओं का एकाधिकार है और जब कभी भी इनकी इच्छा हुई, इन्होंने कृत्रिम कभी दर्शाकर फिनाल के मूल्य बढ़ा दिए। फिनाल की कभी छलयोजित थी और फिनाल अधिक मूल्य पर बेचा गया।
- (vii) फिनाल की कभी कैसे उत्पन्न हुई और किस तभी घरेलू उत्पादकों द्वारा मूल्य 25% से 50% तक बढ़ाकर फिनाल उपलब्ध करा दिया गया, इस बारे में जांच शुरू की जानी चाहिए।

(ख) केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि., मुम्बई

(i) भारत में वे फिनाल के सबसे बड़े उपमोक्ता हैं जो बिसफिनाल - ए का विनिर्माण करते हैं। बिसफिनोल-ए के विनिर्माण में एसीटोन के साथ फिनाल मुख्य कच्चा माल है।

(ii) रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से केवल दो विभिन्नता लाभाच्छित होंगे यथा मैं हिन्दुस्तान आर्गनिक लिं ० और मैं० हड्डीलिया केमिकल्स लिमिटेड। ये दोनों विभिन्नता एकाधिपत्य स्थिति का लाभ उठा रहे हैं और नियमित रूप से एक दूसरे से आपसी सामंजस्य करके मूल्य बढ़ा रहे हैं जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एवं उपमोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है क्योंकि एकाधिपत्य स्थिति के कारण फिनाल के मूल्यों में अव्याहनीय वृद्धि से कम उत्पादन होगा और राष्ट्र को इससे प्राप्त राजस्व में भी अक्षर पड़ेगा।

(iii) देश में फिनाल का साधारणतया आयात लगभग 10000-15000 टन प्रति वर्ष है। इस वर्ष ढाई माह के लिए घरेलू विभिन्नताओं द्वारा अपने संयंत्र बंद कर दिए जाने के कारण आयात में वृद्धि हुई जिससे कि आयात बढ़कर लगभग 25000 मी.टन (15000 मी.टन के सामान्य वार्षिक आयात से) तक पहुंच गया।

(iv) सभी रसायनों यथा बेंजीन, क्यूमिन, एसीटोन और बिसफिनाल-ए के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य मांग और आपूर्ति में अक्षर के कारण और दक्षिण पूर्व एशिया में मर्दी के कारण पर्याप्त रूप से कम हुई और फिनाल के मूल्य इसका अपवाद नहीं है।

(v) भारत में फिनाल की मांग इस कारण बढ़ रही है कि रसायन उद्योग के लिए फिनाल मुख्य निर्माण खण्ड है इसलिए फिनाल के मूल्यों में कोई भी वृद्धि फिनाल से नियमित होने वाले अन्य उत्पादों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।

(vi) घरेलू विभिन्नताओं द्वारा ठीक समय पर आयातित उत्तराई के समय की लागत पर आधारित मूल्यों में कमी करने की अनिच्छा के कारण 1998 की अतिम तिमाही में फिनाल का आयात बढ़ा। उन्होंने अपने मूल्य देश में फिनाल की बड़ी मात्रा में आयात होने के पश्चात ही घटाए। अब एवं ओ सी ने भी अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के समान मूल्य प्रस्तावित करने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने उनसे जनवरी - मार्च 1999 के दौरान 1000 मी.टन फिनाल की आपूर्ति करने का एक अनुबंध किया है।

(vii) मई-जुलाई 98 के दौरान घरेलू विभिन्नताओं ने फिनाल की कमी दर्शाई थी। अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम होने के बावजूद उन्होंने फिनाल के मूल्य बढ़ा दिए थे।

(viii) फिनाल के उपमोक्ता फिनाल आयात करने के लिए बाध्य हो गए क्योंकि घरेलू विभिन्नता अपनी इन्पुट लागत में कमी का लाभ उन्हें नहीं दे पाए। जब कमी सी इनके कछ्वे माल जैसे बेंजीन, क्यूमिन के मूल्यों में या शुल्क में कोई कमी आई तो उन्होंने इसका लाभ फिनाल के उपमोक्ताओं को नहीं दिया। मूल्यों में कमी न करने के एकाधिपत्य नजरिये के कारण ही आयात में बड़ी वृद्धि हुई जो उनके द्वारा रोकी जा सकती थी।

(ix) घरेलू विभिन्नताओं द्वारा 1970 और 1980 के दौरान पुरानी तकनीक और कम क्षमता वाले अक्षम संयंत्र लगाए गए जबकि अन्तर्राष्ट्रीय संयंत्रों के पास बेहतर तकनीकें थीं जिससे वे उत्पादन के लाभकारी स्तर को प्राप्त कर रहे थे।

(X) घरेलू उद्योग को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिके रहने के लिए फिनाल के उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए।

(XI) फिनाल पर किसी रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण फिनाल के उपभोक्ता को निश्चित रूप से क्षति पहुंचाएगा जिससे रसायन उद्योग को भी क्षति होगी।

(XII) गांधिकाकर्त्ताओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से यह प्रमाणित है कि मारतीय बाजार में फिनाल की डिमिंग की गयी प्रतीत होती है और इस विषय में आगे कार्यवाही करने के लिए महानिदेशक (रक्षोपाय) को नियमों के सहारे रोका गया।

(XIII) आवेदनकर्ता फिनाल को कैप्टिव रूप में भी उपभोग करते हैं और उनको उस सीमा तक उपलब्ध सुविधाएं व्यापारी बाजार को उपलब्ध नहीं हैं और देश में मांग को पूरा करने के लिए आदेशकर्त्ताओं की क्षमताओं में से उसे अलग करना चाहिए।

(XIV) चूंकि फिनाल और एसीटोन संयुक्त उत्पाद है, यह उपचित नहीं होगा कि एसीटोन के संबंध में स्थिति का मूल्यांकन किये बिना केवल फिनाल के लिए घरेलू उद्योगों को होने वाली क्षति का ही रांगन किया जाए।

(XV) जांच आरम्भ किये जाने का नोटिस उल्लेख करता है कि घरेलू उद्योग ने 2 वर्ष की अवधि के लिए शुल्क हेतु अनुरोध किया है। यह गांधिकाकर्त्ताओं द्वारा किये गये अनुरोध के विपरीत है। गांधिकाकर्त्ताओं ने अनुरोध किया है कि तीन साल के लिए रक्षोपाय शुल्क लगाया जाए जो तीन वर्ष की सामान्य पर आगे बढ़ाया जा सके।

(XVI) अप्रैल-दिसम्बर 1998 के दौरान दावा किये गये फिनाल के आयात को कोई प्रमाण नहीं है। किसी कागज पर कम्पनी द्वारा तैयार किये गये एक विवरण से ही कम्पनी कोई प्रमाण स्थापित नहीं कर सकती है और पूरी सूचना का अमाव आवेदनकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न करता है। आवेदनकर्त्ताओं ने अपने समायन स्टॉक के आंकड़ों को भी उद्धृत किया है जो उनके नियंत्रण में ही था।

(XVII) शेयर मूल्यों में भारी गिरावट को क्षति के एक प्रमुख प्रतीक के रूप में बताया गया है। यदि शेयर कीमतें क्षति के लिए एक प्रतीक हैं तो सम्पूर्ण भारतीय उद्योग गमीर रूप से क्षतिग्रस्त है। गांधिकाकर्त्ताओं का पूरा मामला दिसम्बर 1998 में हाजि और लाम से कमी का है। एक महीने में कुल हाजि और लाम की कमी को गमीर क्षति के रूप में नहीं संर्णित किया जा सकता है।

(XVIII) यह दावा भी है कि निर्यात बढ़ाने (संरक्षण) के लिए प्रयुक्त वस्तुओं के लिए फिनाल का आयात गांधिकाकर्त्ताओं को प्रभावित करता है। इस प्रकार के आयात पर कोई शुल्क देय नहीं है। ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है कि इन्होंने देश के वाणिज्य में प्रवेश नहीं किया है। इसलिए निर्यात के उद्देश्य हेतु फिनाल के हुए आयात को घटा देना चाहिए। यदि इन आयातों को घटा दिया जाता है तो यह प्रमाणित होगा कि आयात बिल्कुल नहीं बढ़ा है।

(XIX) एच.ओ.सी. को लाम दबाव में, उच्च ब्याज की लागत और इनकी हाल ही में पूरी की गयी

योजनाओं जैसे कलोरो अल्कली और हाइड्रोजन पराक्साइड से अवमूल्यन के कारण हैं। इन विविधकृत योजनाओं में कम्पनी के वर्तमान कार्यों के आकार के अनुपात में बहुत बड़ी पैंजीगत व्यय शिहित हैं और इन्हें मुख्यतः ऋण लेकर उपलब्ध कराया गया था। इन निवेशों से अभी भी सकारात्मक धन प्राप्त होना बाकी है जो कम्पनी की सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा।

(ग) मार्वल थर्मोसेट्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई, और
 (घ) रोमित रेसिन्स प्राइवेट लिमिटेड पनवेल, महाराष्ट्र

(i) वे लघु स्तरीय औद्योगिक इकाई हैं जो कि थर्मोसेटिंग और बेकलाइट में कॉल्ड सेटिंग, बाइंडिंग, लेमिनेटेस, प्लाश्युल, ग्राइंडिंग छील्स, रेफ्रेक्चरी ब्रिक्स, कार्क, फाउंड्रीज आदि में प्रयुक्त होने वाले फिनाल फार्मलडीहाइड रेसिनों का निर्माण करती है। यह मूल आर्थिक थर्मोसेटिंग बाइंडर, फिनाल से विभिन्नित होता है।

(ii) वर्तमान में यह एक ज्ञात तथ्य है कि भारत में 1995-96 से औसतन 20,000 टन फिनाल प्रतिवर्ष आयात किया जा रहा है जो शियमित और लगातार आयात है।

(iii) आयातित फिनाल, फिनाल के देशी विनिर्माताओं के मूल मूल्य को वियक्त करने का एक माध्यम है।

(iv) फिनाल के भारतीय विनिर्माता अपने संयुक्त वर्ष में दो बार अपनी मशीनों के रखरखाव के लिए बंद करते हैं जो कि तकनीकी रूप से आवश्यक लगता है। तथापि फिनाल विनिर्माण संयंत्रों के बंद होने के समय मूल्यों में वृद्धि विनिर्माताओं के विकृत आल को प्रदर्शित करता है।

(v) फिनाल के मूल्यों का पुनरीक्षण भारतीय विनिर्माताओं की अपनी इच्छा पर किया जाता है। इससे लघु स्तर इकाईयों प्रभावित होती है क्योंकि उन्होंने चार्षिंग या अर्क्चरार्सिंग आर्सर या ट्रेलर अग्रिम रूप में तय किए जाते हैं जो कि एक व्यवन्वाद्धता है और फिनाल के मूल्यों में कोई भी वृद्धि उनके बोझ को बढ़ाता है जिससे उस वर्ष में घाटा होता है।

(vi) 1998-99 में दिसम्बर 98 तक फिनाल का घरेलू उत्पादन 48703 टन दर्शाया गया है और 1997-98 के आँकड़ों की तुलना में इसे कम होने का दावा किया गया है। यदि 9 माह से 48703 टन का उत्पादन होता है तो बारह महीनों में यह आँकड़ा 85000 टन तक पहुँचना चाहिए जो एक औसत उत्पादन है।

(vii) 1998-99 में, जून 98 और अगस्त 98 के बीच भारतीय विनिर्माण इकाईयों ने फिनाल का उत्पादन और विपणन बंद कर दिया और साथ ही इसकी कमी दर्शाकर इसके मूल्य बढ़ा दिए गए। इस अवधि के दौरान रेसिन उत्पादों के विनिर्माता आयातित फिनाल के कारण टिके रहे।

(viii) फिनाल का प्रयोग करके मूल्य वर्द्धित उत्पाद जैसे रेसिन का निर्माण किया जाता है। फिनाल के उपयोगकर्ताओं की सूची भारतीय विनिर्माण इकाईयों से प्राप्त की जा सकती है जो इस फिनाल के उपयोगकर्ताओं द्वारा लगाये गए वित्त एवं निवेश को दर्शाएगा जो फिनाल विनिर्माताओं द्वारा लगाये गये वित्त एवं

निवेश से काफी अधिक है। इसके साथ ही फिनाल विनिर्माताओं की तुलना में फिनाल उपयोगकर्ता क्षेत्र ने रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए हैं।

(इ) फोसेको इंडिया लि., पुणे

(i) भारत में वे फारम्ही के रेसिन और फ्लाक्सों के मुख्य विनिर्माता हैं और सभी मुख्य फारम्हीयों एवं स्टील संयंग्रों को माल की आपूर्ति कर रहे हैं। ये फारम्ही, आटोमोटिव, रेलवे, थर्मलपावर और निर्यात आदि क्षेत्रों के लिए विशेषता वाली डलाई की वस्तुओं का उत्पादन करती हैं।

(ii) वे फिनाल की अपनी शतप्रतिशत मांग की खरीद में छिप्पुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. और ने हड्डीलिया केमिकल्स लि. से करते हैं। सरकार की अपनी नीतियों के उदारीकरण के पश्चात दोनों भारतीय विनिर्माता अपने उत्पाद का मूल्य अपनी लागत के आधार के बजाए आयातित फिनाल के मूल्यों के आधार पर तय कर रहे हैं। वे अपना मूल्य, आयातित फिनाल की उत्तराई के समय की लागत से ₹ 0.50 ₹. से ₹ 1.00 ₹. तक अधिक रखते हैं।

(iii) 1998 के केंद्रीय बजट में फिनाल और क्यूमिन पर शुल्क घटाया गया। उन्होंने एवं ओ सी और हड्डीलिया, दोनों से अपनी इन्पुट लागत पर शुल्क में कमी होने के कारण फिनाल के मूल्यों में कमी करने के लिए अनुरोध किया। एवं ओ सी और हड्डीलिया ने स्पष्ट रूप से बताया कि उनके मूल्य बजट के आधार पर न होकर फिनाल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित हैं और उन्हें उस लाभ से वित्त कर दिया जो कि उद्योगों को सरकार द्वारा दिया गया था।

(iv) भारतीय वस्तुओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए भारत सरकार ने अपनी नीति का उदारीकरण किया है एवं सुधार लागू किया है जिससे कि अंततः व्यापार/ निर्यात में ही वृद्धि में मदद होगी। लेकिन एवं ओ सी एवं हड्डीलिया दोनों ने फिनाल की मूल्य वृद्धि की, जबकि रास्ते में कोई आयातित फिनाल नहीं था।

(v) एवं ओ सी और हड्डीलिया ने प्राकृतिक आपदाओं का लाभ उठाया। जून 98 के माह में विध्वंसक घटनाकाल का प्रहार गुजरात में हुआ और कांडला पत्तन पर सभी गतिविधियाँ रुक गईं, जहाँ आयातित फिनाल उत्तरार्ण की एकमात्र सुधार है। दोनों भारतीय विनिर्माता जानते थे कि घटनाकाल के विध्वंसक प्रभाव के कारण निकट भविष्य में फिनाल का आयात संभव नहीं हो सकेगा और उन्होंने फिनाल की अपनी मूल कीमत ₹ 40/- प्रति कि.ग्रा. तक बढ़ा दी हालांकि उस समय आयातित फिनाल की उत्तराई के समय की लागत ₹ 33.50 प्रति कि.ग्रा. आ रही थी।

(vi) एवं ओ सी और हड्डीलिया ने भारतीय उद्योगों की मांग की पूरी तरह अनदेखी कर दी और मुनाफाखोरी शुरू कर दी। फोसेको ने अविवेकी भ बनने के लिए और फिनाल के मूल्य कम करने के लिए अनुरोध किया क्योंकि उपयोगकार बाजार में मंदी की प्रवृत्ति के कारण किसी भी मूल्य वृद्धि को बदौश्वत करने से वे असमर्थ होंगे। दोनों विनिर्माताओं ने उत्तर देने की भी जरूरत नहीं समझी। अंततः उन्होंने अपने मूल्य आयातित फिनाल कांडला पत्तन पर उत्तरने के बाद ही कम किये।

(VII) आटोमोटिव सेक्टर/ स्टील सेक्टर/ टैक्सटाइल मशीनरी विनिर्माता गहरी मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और उनके लिए अपने उपभोक्ताओं से कोई मूल्य वृद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। एच.ओ.सी. और हड्डीलिया द्वारा अनुधित मूल्य वृद्धि के कारण हुई सभी वृद्धि को उन्हें समाहित करना पड़ता है। इस स्थिति ने उन्हें आयात के लिए प्रयास करने हेतु बाध्य किया क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था।

(VIII) उन्हें भर है कि यदि सरकार रक्षोपाय शुल्क लगाती है तो दोनों भारतीय विनिर्माता अपनी कीमतों को पुनः बढ़ा देंगे और उनके ग्राहक कोई भी मूल्य वृद्धि देने में असमर्थ होंगे। उनके कुछ ग्राहकों ने उन्हें बताया था कि यदि कीमत बढ़ती है तो वे स्वयं रेसिन का आयात करेंगे क्योंकि आयातित फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क लगाये जाने पर एच.ओ.सी. और हड्डीलिया दोनों अपनी कीमते बढ़ा सकते हैं।

(च) गार्गी हटेन्स - एल्बर्टस लिंग, मुम्बई:

(i) दोनों विनिर्माताओं, हिन्दुस्तान आर्मेनिक केमिकल्स लिंग एवं हड्डीलिया केमिकल्स लिंग ने सही तस्वीर प्रस्तुत नहीं की है। उन्होंने उत्पादक संघ बना लिया है एवं पिछले कुछ वर्षों से फिनाल के मूल्यों के साथ खिलवाड़ किया है।

(ii) वे भारत सरकार के साथ पजीकृत एक लघु स्तरीय उद्योग हैं जो कि फारड़ी उद्योग में प्रयुक्त फिनाल फार्मलडीहाइड रेसिन का निर्माण करते हैं। उनका मुख्य कच्चा माल तरंग फिनाल है। उनका संयुक्त हड्डीलिया केमिकल्स के निकट स्थित है एवं वे एच.सी.एल. और एच.ओ.सी. दोनों से खरीदते हैं।

(iii) लगभग तीन वर्ष पहले, फिनाल न्यून आपूर्ति में थी। जब कभी भी कभी उत्पन्न की गई, मूल्य बढ़ाये गए। यह आयातित माल ही है जिसने भारत से कम लागत और उनकी मौंग के अनुसार माल उपलब्ध कराकर उद्योगों सहायता की। जब कभी भी कभी हुई, एच.सी.एल. एवं एच.ओ.सी. ने हमेशा जाम उठाने की कोशिश की।

(iv) एच.ओ.सी. और एच.सी.एल. के लाभ में कभी उनके फिनाल विनिर्माण में क्षमता के कारण हुई। फिनाल पर आयात शुल्क में वृद्धि का यह कोई कारण नहीं हो सकता।

(v) खरीदार के रूप में वे घरेलू स्वोतों से ही फिनाल खरीदना चाहते हैं क्योंकि इससे समय, लागत और देश को विदेशी मुद्रा की बदल होती है, लेकिन वितरकों द्वारा खेले गए संघ बनाने के खेल के कारण, आयात ही इस उत्पादक संघ की नियन्त्रण और अनुशासित करने का एक रास्ता है।

(vi) भारत में फिनाल उद्योग को किसी रक्षोपाय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विदेशी उत्पादकों का कोई ढर नहीं है।

(vii) जब काडला ने प्राकृतिक आपदा का सामना किया एवं अधिकतर भड़ारण टैक नष्ट हो गए तो 3 जून से 24 जून, 1998 के दौरान एच.ओ.सी.एल. और एच.सी.एल. ने तुरस्त अपने मूल्य बढ़ा दिये जिसे दस्तावेजों से साबित किया जा सकता है।

(viii) दोनों भारतीय विनिर्माता सदैव अपने संयुक्त वर्ष में कम से कम एक शा दो बार बद करते हैं और ग्राहकों को फिनाल की आपूर्ति अचानक बद कर देते हैं जिसकी उन्होंने ग्राहकों को कभी भी अग्रिम सूचना नहीं

दी, जिससे घरेलू मूल्य बढ़े, क्योंकि मूल्यों का निर्धारण उनके बीच किया जाता है। नए मूल्यों को स्वीकार करके माल प्राप्त करने के अलावा उनके पास कोई रोक्ता नहीं था।

(ix) मारत सरकार की उदाहरण, फार्मासिटी, फिनालिक एसिन को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर आयात कर सकती है। मारतीय फिनाल की अधिक कीमतों के कारण विश्व बाजार में फिनाल के दो मुख्य आपूर्तिकर्ता यथा मै० आशलैंड केमिकल्स, गु.एस.ए. और मै० बोर्डन केमिकल्स, गु.के ने मारतीय बाजार में पहुँचने की योजना तैयार की और मै० डी.सी.एम. इंजीनियरिंग, रोपड, एव.डी.सी., कलकत्ता, मै० सिक्काल्स, रानीपेट और कई अन्य को कम मूल्य पर फिनाल की आपूर्ति पहले ही कर दी है।

(च) अतुल लिमिटेड, गुजरात :

(i) वे फिनोक्सी हबीसाइड्स के विनिर्माण के मारत में प्रमुख एवं विश्व में चतुर्थ सबसे बड़े विनिर्माता हैं जिसमें फिनाल एम.सी.ए. एसिड के साथ प्रमुख कच्चे माल के रूप प्रयुक्त होता है। उनकी फिनाल की खपत प्रतिवर्ष लगभग 3000 मी.टन है और घरेलू बाजार में बिक्री करने के अलावा उनके उत्पाद विभिन्न देशों को बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाते हैं।

(ii) फिनाल के दोनों मुख्य विनिर्माता देश में अपना एकाधिपत्य रखते हैं एवं शियमित अंतराल पर एक दूसरे से विचार-विमर्श करके मूल्य निर्धारण कर रहे हैं जो कि शुक्रसान दायक है और फिनाल के उपयोगकर्ताओं को हानि पहुँचा रहा है।

(iii) फिनाल के घरेलू विनिर्माता घरेलू मॉग (विभिन्न कारणों के कारण यथा उच्च मूल्य, कृतिम कमी, सयत्र बंद होना) को पूरा करने में असमर्थ हैं, इसीलिए आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 20000 मी.टन फिनाल आयात किया गया।

(iv) वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में दौड़ेरेलू निर्माता अपने मूल्य तुलनात्मक रूप में उच्च स्तर पर बनाये हुए हैं जिससे कि आयात अधिक लाभप्रद हो गया है।

(v) कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा फिनोक्सी हबीसाइड्स का विनिर्माण किया जाता है जिनमें से कुछ मूल कच्चे माल - फिनाल के विनिर्माता भी हैं। उन्हें (अतुल) विश्व बाजार में इस प्रकार की कई कम्पनियों से प्रतिस्पर्धा करनी है और रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से उनके उत्पाद पूर्णतया अप्रतिस्पर्धी हो जाएंगे।

(vi) फिनोक्सी हबीसाइड्स (फिनाल से निर्मित) से अनुमानित वार्षिक टर्मओवर 45 से 50 करोड़ रुपये हैं। फिनाल के मूल्यों में किसी भी वृद्धि का न केवल इस व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, बल्कि उनकी उत्पादन क्षमता के एक बड़े भाग को भी बम्ब होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मॉग को पूरा करता है।

(ज) आल्टा लैबोरेट्रीज लिमिटेड, मुम्बई

(i) वे ऐस्प्रिन (ऐसिटिल सेलिसिलिक एसिड आई.पी.) के निर्माता हैं तथा फिनाल उनका मूल कच्चा माल है। उनकी फिनाल की वार्षिक खपत लगभग 1400 मी.टन है। डी.पी.सी.ओ. 1987 के अधीन ऐस्प्रिन की कीमत

कानून सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती है। इस उत्पाद के निर्माण के लिए फिनाल मुख्य काष्ठा साल है इसलिए ऐस्प्रिन की कीमत पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। गत तीन वर्षों में घरेलू निर्माताओं द्वारा फिनाल की असाधारण ऊँची कीमत वसूलने के कारण उन्हें हानि हुई है क्योंकि सरकार द्वारा बिक्री मूल्य तीन साल में एक बार संशोधित किया जाता है और अतरिभ राहत लेने की प्रक्रिया लम्बी तथा अमर्साध्य है। बढ़ते मूल्यों और मूल्य पुनरीक्षण में हमेशा अत्यधिक विलम्ब होता है।

(ii) 1987 में मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड के आगमन से पूर्व देश में केवल मैसर्स हरडिलिया कैमिकल्स लिमिटेड, फिनाल के एकमात्र निर्माता थे। आज भी देश में केवल दो निर्माता हैं और मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड का कुल बाजार में लगभग 65% भाग पर नियंत्रण है। वास्तव में यह एक एकाधिकारिक स्थिति है तथा यह कहना गलत नहीं होगा कि मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि. तथा मैसर्स हरडिलिया कैमिकल्स लिमिटेड के बीच मूल्य संबंधी आपसी सॉट-गॉड हैं।

(iii) पिछले तीन वर्षों में कम उत्पादन तथा क्षमता का कम उपयोग एक आम घटना है जो कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सभी बड़े उद्योगों पर लागू होती है। उदारीकरण की ओर्धी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपनी चायेट में लेकर सभी घरेलू उत्पादकों को गमीर क्षति पहुंचायी एवं सौमा शुल्क में 200% से 35% तक की कमी ने स्थिति को और अधिक बिगाड़ दिया और भारतीय निर्माताओं के बाजार अंशदान को बुरी तरह प्रभावित किया।

(iv) अधिक और अधिकतम लाभ पर न होकर लागत घटाने तथा लागत-प्रतिस्पर्धा पर ढोना चाहिए। लाभ की मात्रा सदैव व्यक्तिनिष्ठ और विवाद योग्य मुद्दा होती है। फिनाल की अधिक कीमतों के कारण लोग फिनाल आधारित उद्योग में प्रवेश करने में हिचकिचाते हैं। यदि फिनाल की कीमत लम्बी अवधि के लिए एक उचित स्तर पर निर्धारित कर दी जाए तो इस उत्पाद की मांग बढ़ेगी और इसके फलस्वरूप निर्माता अत्यधिक लाभदायी आर्थिक गतिविधियों को चलाने में समर्थ होंगे।

(v) वे नहीं जानते कि फिनाल का किसी भी मात्रा में आयात भारत में 410 अमरीकी डालर प्रति मी.टन से भी कम कीमत पर किया गया। वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय कीमत 500 अमरीकी डालर प्रति मी.टन से भी अधिक है और कीमतें पहले ही ऊपर उठ़नी शुरू हो चुकी हैं।

(vi) वित्तीय कियाकलाप एक वार्षिक घटना है और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों के आधार पर एक पुनरीक्षण किया जाता है तथा दो साल हेतु डम्पिंग शुल्क लगाने की मांग तर्कसंगत और स्थायोदित नहीं है।

(vii) यदि डम्पिंग शुल्क अधिरोपण के अनुरोध को मान लिया जाता है तो अन्य सभी पैदोलियम आधारित रसायनों के लिए बहुत रास्ते खुल जाएंगे और यह बीमारी अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में भी फैल सकती है।

(viii) पिछले पांच वर्षों में फिनाल निर्माताओं विशेषकर मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड ने विश्वमर्क में सभी देशों को बड़ी मात्रा निर्यात किया है। केवल वर्ष 1997-98 में ही 7675 मी.टन फिनाल का निर्यात था। उनकी समझ में नहीं आता कि यदि अतर्राष्ट्रीय बाजार में फिनाल की कीमतें अलाभकारी थीं तो 7875 मी.टन की इतनी बड़ी मात्रा में देशी निर्माताओं द्वारा निर्यात कैसे किया गया।

(ix) फिनाल निर्माताओं का यह आम कथन कि फिनाल के सस्ते आयात के कारण उभका लाभ बुरी तरह प्रभावित हुआ है, गलत होगा। वास्तव में उनके पास और उत्पादों की भी विस्तृत श्रृंखला है। यह भी मान्य तथ्य है कि अर्थव्यवस्था में आम शिथिलता के कारण और साथ - साथ मांग में कमी के कारण सभी क्षेत्रों में मुख्य निर्माता इकाइयों कठिनाईयों का सामना कर रही हैं और फिनाल निर्माताइसके अपवाद नहीं हैं। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिनाल की कीमत केवल विभिन्न विदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ली जाने वाली कीमतें और शुल्क दौद्ये पर ही नहीं, बल्कि विदेशी विनियमन दर पर भी निर्भर करती है जो कि अति परिवर्तगशील है और विशेषज्ञों को उम्मीद है कि डालर की वर्तमान कीमत 42.50 रुपये से बढ़कर 45/- रुपये तक जा सकती है।

(x) निर्यात की धीमी प्रगति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चिंता का कारण है और फिनाल की उच्ची कीमतों के समर्थन के कारण फिनाल द्वारा निर्मित उत्पादों के निर्यात पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दूसरे शब्दों में अस्तराष्ट्रीय बाजार में मूल्य प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी।

(xi) वे दृष्टिकोण से महसूस करते हैं कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के अनुरोध को मान लेने की स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था का विच्छापीकरण संकुचित हो जाएगा एवं फिनाल विनिर्माता अस्तराष्ट्रीय बाजार से विघटित हो जाएगे। इसलिए सरकार को जल्दबाजी से ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे नई उदारीकरण नीति को कोई खतरा पैदा हो।

(अ) विनलेम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता

(i) पूर्वी भारत में वे हेकोरेटिव लैमिनेट्स के प्रमुख निर्माता हैं और उन्होंने फिनाल पर उन्मिंग विरोधी शुल्क के अधिरोपण की भांग को रद्द कर देने का अनुरोध किया है।

(ii) उन्मिंग विरोधी शुल्क का अधिरोपण आम उपभोक्ता की कीमत पर केवल स्थानीय निर्माताओं की ही सहायता करेगा।

(iii) उन्होंने पहले पाया है कि जब आयात नहीं होता था तब भी स्थानीय निर्माताओं ने पर्याप्त रूप से कीमतें बढ़ाई थीं। इसके अलावा, उच्च शुल्क दर व्यापार के स्वच्छ बातावरण के विपरीत होगा, और एकाधिकार एवं उच्च कीमतों को बढ़ावा देगा।

(iv) कम कीमत पर फिनाल का आयात भारतीय उत्पाद को अस्तराष्ट्रीय उत्पाद के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक बनाता है और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करता है।

(ण) अष्टमान टिम्सर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता

(i) उन्हें ज्ञात हुआ है कि सरकार भारत में फिनाल के आयात पर 72% रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की योजना बना रही थी।

(ii) वे इस प्रकार के शुल्क अधिरोपण के यक्ष ने नहीं हैं क्योंकि इससे स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को व्यापक रूप से कीमतें बढ़ाने में सहायता मिलेगी जैसा कि उन्होंने पहले किया है, जब कोई आयात नहीं होता था।

(iii) इस प्रकार के उच्च शुल्क का अधिरोपण स्वच्छ व्यापार वातावरण के विरुद्ध है, और एकाधिकार एवं उच्च कीमतों को बढ़ावा देता है।

(ट) किंशुण ट्रेडिंग कम्पनी, कलकत्ता

(i) उन्हें पता थला है कि 3 साल के लिए भारत में फिनाल के आयात के विरुद्ध डम्पिंग विरोधी शुल्क / रक्षोपाय शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।

(ii) फिनाल के बड़े आयातके नाते वे इस प्रकार के शुल्क अधिरोपण के पक्ष में नहीं हैं।

(iii) यह केवल एच.ओ.सी. और एच.सी.एल. जैसे स्थानीय निर्माताओं को व्यापक रूप से कीमतें बढ़ाने में सहायता करेगा जैसा कि यह उभकी नियमित कार्य पद्धति थी, जब आयात नहीं होता था।

(iv) इस प्रकार के उच्च शुल्क का अधिरोपण स्वच्छ व्यापार वातावरण के विरुद्ध है और एकाधिकार एवं उच्च कीमतों को बढ़ावा देता है।

(छ) मैसर्स ए.बी.सी. प्रोफेक्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता तथा

(छ) मैसर्स किटप्सार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता

(i) उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण उल्टानी जा सकने वाली चीति है। डब्ल्यू.टी.ओ के साथ अनुबंध के अनुसार सीमा शुल्क को स्वीकार्य स्तर तक घटाना पड़ेगा। जो शुल्क 1992-93 में 85% था अब घटकर 25% रह गया है, उसमें रक्षोपाय शुल्क के नाम से किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी और कुछ नहीं, बल्कि स्थीरत चीति से पीछे हटा है।

(ii) महा निदेशक (रक्षोपाय) कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी से यह स्पष्ट है कि भारत में फिनाल की सौंग हमेशा घरेलू क्षमता से अधिक रही है। यह स्थिति घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्यातित फिनाल की भी शानिल करने के पश्चात है। अतः फिनाल का आयात अति आवश्यक है जाहे फिनाल की अस्तराष्ट्रीय कीमतें घरेलू कीमत से अधिक भी हों।

(iii) यह आश्चर्यजनक है कि 85 - 90 % क्षमता उपयोगिता वाले विद्यमान संयंत्र भी इसे पूरा नहीं कर सकते। व्यापार में बहुत अधिक अवरोधों का लाभ उठाते हुए भारतीय निर्माताओं ने घरेलू कीमतों को विश्व कीमतों से अधिक रखकर आसान रास्ता अपनाया। वर्तमान निर्माताओं की समझदारी संयंत्र की दक्षता को बढ़ाकर अपनी क्षमता को बढ़ाने की होनी चाहिए थी। वर्तमान निर्माता स्वयं यह मानते हैं कि फिनाल के उत्पादन के लागत की कीमत 4 रुपये से 6 रुपये प्रति किलोग्राम कम की जा सकती है। दुर्भाग्य से वे अभी भी लागत कम करने के उपायों को न अपनाकर रक्षोपाय शुल्क द्वारा आसान शास्ते डेटु प्रयासरत हैं।

(iv) जब इस मंदी के दौर में नी 12% पैंजी की वापसी अपने आप में अनुकूल है तो मैसर्स हड्डीलिया

द्वारा फिनाल संयंत्र में 53 करोड़ रुपये के निवेश का विचार भी स्वीकार्य नहीं है। ये संयंत्र 15 वर्ष से भी अधिक पुराने हैं तथा पूरी तरह से इनका मूल्य छास हो चुका है। संयोग से यह वह समय आ जब उनके पास 30 से 85% शुल्क का व्यापार अवरोध उपलब्ध था। निश्चित रूप से संयंत्र से शुरू के बाँधों से पर्याप्त लाभ कमाया गया होगा और वह भी लब, जब उत्पाद क्षमता से भींग अधिक थी। पूर्ण मूल्य छासित संयंत्रों के चलते हुए किसी भी प्रकार का रक्षोपाय शुल्क का अनुरोध न्याय संगत नहीं है।

(V) यह सत्य है कि वर्ष 1998 में फिनाल की विश्वव्यापी कीमतें बहुत अधिक गई गई हैं। लेकिन इसे अल्प कालिक ही माना जा सकता है। फिनाल की कीमतों में वर्ष- प्रति -वर्ष महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव आता रहता है। इस वर्ष की न्यूनतम कीमत को उत्तराई के समय की कीमत की गणना के लिए आधार नहीं माना जा सकता है।

(VI) कथित उचित मूल्य और उत्तराई के समय के मूल्य के बीच बड़े अक्षर को सिद्ध करने के लिए निकासी और अग्रेषण की कीमत बहुत कम दर्शाई गई है। 510/- रुपये प्रति मी.टन सी.एन.एफ. लागत के विपरीत वर्तमान अग्रेषण और निकासी लागत 1200/- रुपये से 1500/- रुपये प्रति मी.टन के बीच है। इसके अलावा आयातक एल./सी. खोलने की लागत (मूल्य का 125% तक), इन्वेस्टी कास्ट (एक ही समय में भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है) भछारण लागत (टैक भाड़ा 165/- रुपये प्रति मी.टन प्रति माह), विनिमय जोखिम लागत, हाई सी ब्रिकी पर अतिरिक्त सीमा शुल्क वर्गरह पर भी खर्च करता है। मैसर्स हॉलिया कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा गणना की गई उत्तराई के समय की लागत में कम से कम 1500/- प्रति मी.टन जोड़ दिया जाना चाहिए।

(VII) फिनाल के कच्चे माल पर नगण्य सीमा शुल्क के लाभ के बारे में घरेलू निर्माता भी नहीं हैं। रक्षोपाय शुल्क की माँग के बदले उन्हें घटाये गए शुल्क का लाभ उठाकर अपनी लागत कम करनी चाहिए।

(VIII) फिनाल के उपयोगकर्ताओं में से अनेकों, निर्यात के लिए मूल्य बढ़ित उत्पादों का निर्माण करते हैं। शुल्क के व्यापारिक अवरोध के साथ (25% सी.डी.+10% अधिमार) भी अगर घरेलू निर्माता डीक से कार्य नहीं कर सकते तो ऐसी इकाइयों को बाढ़ होने देना चाहिए जिसकी उनकी अक्षमता फिनाल के उपयोगकर्ताओं पर छाली जाए और उनको अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रतिस्पर्धात्मक बना दिया जाए।

(ग) सेनेकटेडी स्पेशलिटीज एशिया लिमिटेड, मुम्बई

(I) दे अमरीका की सेनेकटेडी इन्टरनेशनल इंक. (एस.आई.आई.) (विश्व में एल्कीलेटेड फिनाल के सर्वाधिक निर्माता) तथा समशील्ड कैमिकल्स लिमिटेड (एस.सी.सी.) संयुक्त उधम वाली कम्पनियाँ हैं जो कि विशेष रसायनों का निर्माण करते हैं तु सूचीबद्ध हैं। वे स्टेट आफ आर्ट तकनीक से अल्कीलेटेड फिनाल की विस्तृत श्रेणियों का निर्माण करते हैं, जिनका प्रयोग विभिन्न महत्वपूर्ण एवं केन्द्रीय क्षेत्रों में किया जाता है।

(II) फिनाल एक मूल कच्चा माल है। इसके 50% माल का प्रयोग अल्कीलेटेड फिनाल के निर्माण में होता है, और इसकी शुद्धता, विश्वसनीय गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक कीमतें उनके अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद के लिए अति महत्वपूर्ण हैं।

(iii) जो फिनाल स्वदेश में उपलब्ध है उसमें 1000 पीपीएम तक नहीं है और नमी एलिकल फिनाल निर्माण के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है।

(iv) फिनाल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर एलिकल फिनाल भारत से बाहर के संघर्षों से अति प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर सरलता से उपलब्ध हैं। बड़े हुए आयात शुल्क के कारण भारत में फिनाल की कीमतों में हुई वृद्धि और परिणामतः स्थानीय निर्माताओं द्वारा फिनाल की कीमतों से बढ़ोत्तरी, भारतीय एलिकल फिनाल निर्माण क्षेत्रों को नष्ट कर देगा। वास्तव में (एफ.आई.सी.ओ.एम.) फिकोम आर्गेनिक्स और हाइको प्रोडक्ट्स प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं सके और एलिकल फिनाल के निष्क्रिय निर्माता बने रहे।

(v) फिनाल के अलावा, हड्डीलिया कैमिकल्स भी एलिकल फिनाल बनाता है और अगर उनको फिनाल की कीमत बढ़ाने का अपसर मिले तो भारत में किसी और के द्वारा एलिकल फिनाल का निर्माण करना व्यावहारिक नहीं रह जाएगा। इस स्थिति में एलिकल फिनाल उद्योग पूरी तारह हड्डीलिया के एकाधिकार में हो जाएगा और लक्षित उत्पाद क्षेत्र यथा सरफेक्टेंट्स, एटिओकसीडैंट्स उद्योग जो कि कृषि, पस्त्र, कीटनाशक, प्लास्टिक, खाद्य क्षेत्र तथा अन्य बहुत से उद्योग जो दिन प्रति दिन भारतीय जनता की दैनिक आवश्यकताओं के लिए उत्पादन कर रहे हैं, वे भी लागत अक्षम हो जाएंगे।

(vi) फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए सरकार को बहुत ही सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। अगर रक्षोपाय शुल्क से स्थानीय निर्माताओं द्वारा निर्मित फिनाल की कीमतें बढ़ती हैं तो वह एलिकल फिनाल उद्योग को नष्ट कर देंगी।

(vii) आयात की कठिनाईयाँ अपने आप में स्थानीय फिनाल निर्माताओं जैसे कि हड्डीलिया और एच.ओ.सी. के लिए लाभकारी हैं जिसके कारण उपयोगकर्ता उद्योग फिनाल की उत्तरार्द्ध के समय की लागत से थोड़ा अधिक देने के लिए तैयार हैं।

(viii) इसका गलांक, समुद्री यात्रा योग्य विशेष टैंकरों की आवश्यकता, उष्ण सङ्कर टैंकर, आयात के पत्तन पर ऊर्ध्व भंडारण टैंकों की आवश्यकता, 100% शुद्ध फिनाल के आयात से बाधाएं हैं।

(ix) उच्च समुद्री माल भाड़ा, भंडारण खर्च, तट से कारखाने के गेट तक के भाड़े के अलावा विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एस.ए.डी.), इसकी उच्च लागत के कारण हैं।

(x) भारतीय निर्माताओं की वर्तमान फिनाल निर्माण की क्षमता लगभग 70,000 टन (45,000 टन एच.ओ.सी. तथा 25,500 टन - हड्डीलिया) है तथा भारत में इसकी लगभग 1,00,000 टन की आवश्यकता है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में फिनाल का आयात बाध्यकर है और वह घरेलू निर्माताओं को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा यदि फिनाल के आयात पर छांचागत लागत के कारण मिले थोड़े और लाभ के साथ वे अस्तराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बनाए रख सकें।

(xi) हड्डीलिया तथा एच.ओ.सी. का 100% ठोस फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क अधिशोध के अनुरोध को स्वीकार नहीं करना चाहिए।

(xii) अगर एशिया, यूरोप और अमेरिका में निर्माता, जिसके पास कम कमता वाले संयंत्र हैं, वे विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं तो मारतीय सरकार, भारत में केवल दो निर्माताओं हरड़ीलिया और एच ओ सी को विशेष रक्षणापात्र शुल्क देकर क्यों संरक्षण दे ?

(त) सुनाइटेड मेटाकेम प्राइवेट लिमिटेड, पुणे

(i) वे लघु उद्योग हैं, जो समस्त भारत में फिनाल-फार्मालीन रेसिन (पी.एफ. रेसिन) और फ्लक्स का निर्माण और इसकी आपूर्ति परिवहन उद्योग, फाउन्ड्री तथा स्टील उद्योगों को करते हैं ।

(ii) वे आवश्यकतामुक्त फिनाल या तो हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड से अथवा हरड़ीलिया कैमिकल्स लिमिटेड से प्राप्त करते हैं । उनका सहभागी प्रतिष्ठान अजय मेटाकेम लिमिटेड निर्यात करता है, तथा अग्रिम लाइसेंस के तहत हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड से फिनाल खरीदा जाता है ।

(iii) आगम पर आयात शुल्क कम होने के परिणाम स्वरूप उन्होंने एच ओ सी और हरड़ीलिया से फिनाल को कीमतें कम करने का अनुरोध किया क्योंकि उनकी इन्पुट लागत कम हो गई थी और उन्हें सूचित किया गया था कि उनकी कीमतें फिनाल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर हैं और उनको आयात शुल्क से कुछ लेना देना नहीं है ।

(iv) दोनों कंपनियों की मूल कीमतें सदैव समान रही हैं ।

(v) एच ओ सी और हरड़ीलिया ने जून और जुलाई में कीमतें बढ़ाया और कांडला तट पर प्राकृतिक आपदाओं का लाभ उठाया । यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जून और जुलाई के दौरान कांडला तट पर, जहाँ कि आयातित फिनाल उतारने की सुविधा है, गुजरात में विनाशकारी बाढ़ आने के कारण संचालन कार्य एक दम उप पड़ गया था ।

(vi) निर्माताओं को पता था कि निकट भविष्य में चक्रवात के विनाशकारी प्रभाव के कारण फिनाल का आयात संभव नहीं हो सकेगा तथा उन्होंने फिनाल का मूल्य बढ़ाकर 40 रु. प्रति किलोग्राम कर दिया, यद्यपि उस समय आयात किए गए फिनाल का उत्तराह्न के समय का मूल्य लगभग 33.50 रु. प्रति कि.ग्रा. था ।

(vii) मारतीय उद्योगों को उसी मूल्य पर माल की आपूर्ति कर सहायता पहुँचाने के बजाय एच.ओ.सी तथा हरड़ीलिया ने बाजार में माल की कमी का फायदा उठाते हुए उसका मूल्य बढ़ा दिया जिसके कारण उनके उद्योगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा ।

(viii) यदि आयातित फिनाल के मूल्य को शुल्क में घटाकर अथवा छन्दिंग घिरोधी प्रभारों को लगाकर, मंहगा कर दिया जाता है तो उसके विदेशी खरीदार परिसाधित उत्पाद के मूल्य में कोई घटाकर नहीं करेंगे जिसके फलस्वरूप निर्यात में रुकावट आ जायेगी । भारत सरकार निर्यात को प्रोत्साहन दे रही है, और यदि निर्यात में रुकावट आती है तो वह भारत सरकार की नीति के विरुद्ध होगा ।

(ix) उन्हें लग है कि यदि एक बार सरकार रक्षोपाय शुल्क लगा देती है तो दोनों ही भारतीय निर्माता पिर से उनकी कीमतों में वृद्धि कर देंगे और उनके लिए फिनाल की लागत में वृद्धि को आत्मसात करना सम्भव नहीं होगा ।

(x) यदि फिनाल के मूल्य में वृद्धि होती है तो आयात किए गए पी.एफ रेसिन की कीमत उनके द्वारा निर्मित किए गये से कम होगी तथा ग्राहक आयात किए गए पी.एफ रेसिन की खरीद को प्राप्यमिकता देंगे तथा उनसे खरीदना बन्द कर देंगे ।

(थ) फार्मसन फार्मस्यूटिकल गुजरात लिंग, बोदरा

(i) ये फिनाल रुट द्वारा भारी भावार में पैरासिटामाल दवा का निर्माण करते हैं । उनके कच्चे माल की लागत में लगभग 30-3.5% हिस्सा फिनाल का होता है । उनके उत्पादन का 40% से अधिक विद्यु में निर्यात होता है और किसी भी तरह के अतिरिक्त शुल्क का अधिरोपण उनके निर्यात को संकट उत्पन्न करेगा ।

(ii) उनकी दीर्घकालीन प्रतिबद्धता है तथा उनके मूल्य, प्रकलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों तथा वर्तमान शुल्क लावे पर आधारित है ।

(iii) उन्हें चीन के साथ तीव्र स्पर्धा का सामना पड़ रहा है तथा ई.ई.सी. द्वारा अनुमोदन के सख्त-मानकों का भारतीय निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा किसी भी तरह की शुल्क बढ़ोत्तरी उनके निर्यात को कठोरता से प्रभावित करेगी । क्षाकाल आधारित लाइसेंस के विरुद्ध एसिटिक एन्हाइड्राइड के आयात पर प्रतिबन्ध के कारण उन्हें डी.ई.पी.डी. योजना के अधीन निर्यात करना पड़ रहा है जिसमें शुल्क मुक्त आयात की अनुमति नहीं है ।

(iv) आवेदकों का नियंत्रित व्यवस्था के समय एकाधिकार था तथा उनका अवसरवादिता का विशेष रिकार्ड रहा है । अतः फिनाल की भारी खरीद करने वाले उपमोक्ता उनके पक्ष में नहीं हैं ।

(v) घरेलू मूल्य उनके व्यावसायिक संघ द्वारा नियंत्रित है तथा उपमोक्ता इससे पूर्व उनके इस एकाधिकारवाद एवं कृत्रिम मूल्य वृद्धि से पीछित रहे हैं ।

(vi) कमोबेश, उनके आयात निर्यातोमुखी हैं । और यदि निर्यात को ध्यान में रखा जा जाता है तो रक्षोपाय संबंधी उपाय अनावश्यक है ।

(vii) विगत में यांत्रिकार्कर्ताओं द्वारा भी मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात के बदले, फिनाल का आयात किया जा रहा था ।

(viii) वे पूरी गिर्जा से भारतीय विनिर्माताओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए प्रयासरत भी है, परन्तु हरकीलिया और एच.ओ.सी के साथ अपने अनुमत के कारण उनके पास फिनाल के आयात के अलावा और कोई विकल्प नहीं हैं । एक तरफ तो देश में फिनाल का आयात किया जा रहा था, जबकि उसी समय एच.ओ.सी.

और हस्तीलिया अस्तराष्ट्रीय बाजार में प्रबलित कीमत से भी कम कीमत पर फिनाल का निर्यात कर रहे थे। डीन्ड निर्यात के आधार पर स्थानीय निर्यातकों को प्रस्तावित कीमतें, कठोर और शर्तों के साथ, बहुत अधिक थीं।

(ix) किसी भी प्रकार के रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण एक गलत परम्परा की शुरूआत होगी और यह सुलेख्यापार के मूल अभिप्राय के विपरीत होगा। विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था में अगर इके रहना है तो अकुशलता को समाप्त करना होगा। उद्योग को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक संसार के अनुकूल बनाना सीखना होगा और केवल कुशल और योग्यतम ही इके रह सकेंगे।

(ट) सी.जे. शाह ऐण्ड कम्पनी, मुम्बई

(i) वे भारत में विभिन्न प्रकार के दिलायकों और रसायनों के थोक मात्रा में आयातकों में से एक हैं और भारत में लगातार फिनाल का आयात कर रहे हैं।

(ii) वे जापान कोरिया, अमरीका इत्यादि से वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए निरंतर फिनाल आयात कर रहे हैं और उनकी कीमतें स्थानीय माल की तुलना में कमोबेश प्रतिस्पर्धात्मक हैं तथा जहाँ तक उनकी जानकारी है, उसके अनुसार कोई भी विदेशी आपूर्तिकर्ता भारत में माल की डम्पिंग नहीं कर रहा है।

(iii) वे महसूस करते हैं कि भारत में फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण एकदम अवांछनीय है और अगर इसे कार्यान्वित कर दिया गया तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा जो पहले ही खराब हालत में है।

(iv) उपयोगकर्ताओं की बढ़ती हुई मौग को पूरा करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध फिनाल अपर्याप्त है जो कि आयातित माल द्वारा पूरी की जाती है जिसकी कीमत स्थानीय रूप से उपलब्ध माल की तुलना में लगभग बराबर है। यदि प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क कार्यान्वित कर दिया जाता है तो आयात करना मितव्यथी नहीं होगा और उत्पादन गतिविधियों एकदम ऊँक जाएगी क्योंकि स्थानीय विनिर्माता, उपयोगकर्ताओं की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेंगे।

(v) यदि प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क कार्यान्वित कर दिया जाता है तो इस वस्तु का आयात किफायती नहीं होगा और देशी माल की कीमतें स्वतः बढ़ जाएंगी जिससे अन्तिम उपयोगकर्ताओं को विवश होकर अपने उत्पाद की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त शोष पड़ेगा।

(vi) यदि स्थानीय विनिर्माताओं के संयंत्र तकनीकी अवधि अन्य कारणों से बन्द होते हैं और यदि फिनाल का भारत में आयात नहीं होता है तो फिनाल के अन्तिम उपयोगकर्ताओं को माल न उपलब्ध होने के कारण अपने संयंत्र बन्द करने पड़ेंगे जिसका अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा जैसा कि पहले ही थुका है।

(थ) मैसस्स कान्सिलाल मणिलाल ऐण्ड कम्पनी, मुम्बई

(i) वे विभिन्न विदेशी स्त्रोतों से भारत में फिनाल का आयात कर रहे हैं और विभिन्न ग्राहकों की सेवा कर-

रहे हैं। इस वर्ष के दौरान प्रबलित अस्तराष्ट्रीय कीमतें लगातार गिर रही हैं जो बैन्जीन/क्यूमिन जैसे मुख्य कच्चे माल की कीमतों में गिरावट के कारण हैं।

(i) ससार में अधिकतर देशों की तुलना में भारतीय आयात शुल्क बहुत अधिक हैं और इस असर के होते हुए भी विदेशी आपूर्ति कर्ताओं द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति के प्रस्तावों के कारण लगातार आयात हो रहा है।

(ii) इन आयातों की रोकथाम करने की स्थिति में, बहुत से उद्योग, जो अपने मुख्य निवेश में फिनाल का उपयोग कर रहे हैं, उनको प्रतिस्पर्धात्मक तौर पर हानि हो सकती है और हो सकता है कि विश्व बाजार को देखते हुए वे अप्रतिस्पर्धात्मक हो जाएं। मॉग और आपूर्ति से यह भी स्पष्ट है कि दोनों स्थानीय विनिर्माता देश की मॉग को 100% पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं। यदि उच्च शुल्क दर अधिरोपित कर दी जाती हैं तो यह निम्न कम के उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता को भी हानि पहुँचाएगा।

(iv) बाजारी शक्तियों को मॉग / आपूर्ति की स्थिति पर ध्यान रखने देना आहिए तथा उपभोक्ता को, प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रों/ आपूर्ति कर्ताओं से कच्चा माल लेने की अनुमति होनी आहिए।

(n) हरेश कुमार ऐण्ड कम्पनी, मुम्बई

(i) फिनाल का उपभोग, दो मुख्य उत्पादकों जैसे हिन्दुस्तान आर्गेणिक कैमिकल्स लिं. तथा हड्डीलिया कैमिकल्स लिं. की घरेलू क्षमता की तुलना में कहीं अधिक है। मॉग और आपूर्ति के बीच की दूरी ने आयात को बढ़ावा दिया है। यह भी ध्यान दिया जाना आहिए कि पिछले वर्ष की तुलना में, 1998-99 में स्थानीय विनिर्माताओं की घरेलू बिक्री कम नहीं हुई है। वास्तव में एवं ओ सी का निर्यात लगभग 7700 मी.टन कम हो गया है, जिसमें उनको उत्पादन कम करने के लिए विवश कर दिया होगा।

(ii) फिनाल से निर्मित तैयार उत्पाद जैसे कि लेसिनेट्स, थोक औषधीय दवाएं जैसे कि पैरासिटामोल, एस्प्रिन, कीटनाशक तथा कृषि उत्पाद आदि का निर्यात बढ़ गया है।

(iii) अधिकांश आयात अभी भी निशुल्क व्यवस्था के अधीन हैं और फिनाल का आयात बढ़ने का यह भी एक कारण है।

(iv) कुछ मुख्य आयातक जिन्होंने अपने खपत के साथ-साथ अग्रिम लाइसेंस के अधीन फिनाल का आयात किया, वे निम्नलिखित हैं:-

मिल्सुइ इंडस्ट्रीज लि. तथा हिन्दुस्तान इक्स एण्ड रेजिन्स लि.	2500 मी.टन
सेन्युरी लेसिनेटिंग कम्पनी लि.	1800 मी.टन
अतुल लिमिटेड	2000 मी.टन
केसर पैट्रोफ्रॉडवट्स लि.	3000 मी.टन
युनाइटेड फासफोरस लि.	300 मी.टन
फार्मसन फार्मस्यूटिकल्स गुजरात लि	1500 मी.टन

अन्य लेमिनेट विनिर्माता जैसाकि मेघदेव	3000 मी.टन
ऐण्ड मिल्टन लेमिनेट्स	
विविध निःशुल्क व्यवस्था के अधीन आयातक	2500 मी.टन

निःशुल्क आयात कुल आयात का 50% से भी अधिक हैं जो कि वार्षिक आधार पर लगभग 23000 मी.टन हैं।

(iv) दोनों विनिर्माताओं द्वारा बढ़ाई गई एकाधिकारिक स्थिति आयात बढ़ने का अन्य मुख्य कारण है। एकाधिकार स्थिति का लाभ उठाते हुए उन्होंने कई बार बिना सूचना के कीमतें बढ़ाई। उदाहरण के लिए जून 1998 में कोडला में वक्रवात के दौरान (कुल जात्रा का लगभग 100% आयात कोडला में होता है) आयात और आपूर्तियाँ अगस्त 1998 तक रोक दी गयी थीं। दोनों विनिर्माताओं ने अपनी कीमतें तेजी से बढ़ा दी थीं जबकि उनके आयातित क्यूमिन की कीमतें बदली जाहीं थी अथवा गिर रही थीं (फिनाल विनिर्माताओं ने अपना कच्चा माल, क्यूमिन, मुख्य/संग्लोर में आयात किया)। जब तक कोडला पर आयात/आपूर्ति प्रारम्भ होती, उन्होंने वक्रवात के दौरान अपनी कीमत को मई, 98 में 35/- रु. प्रति कि.ग्रा. से बढ़ाकर जुलाई, 98 में 40/- रु. प्रति कि.ग्रा. करके अपने एकाधिकार का लाभ उठाया।

(v) कुछ अस्तित्व उपयोगकर्ता जो बिसफिलाल - 'ए' जैसा तैयार उत्पाद निर्यात करते हैं, के लिए फिनाल की गुणवत्ता असराप्तीय स्तर की जाहीं है। उनको आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।

(vi) असंगत आपूर्तियाँ और अवानक बढ़ी हुई कीमतों ने फिनोल उपयोगकर्ताओं को आयात करने के लिए विवश कर दिया क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं रह गया था और देशी विनिर्माताओं से उनका विवाद सुठ गया था। विनिर्माताओं ने माल देने में भी सतत रुप से देरी की और सुपुर्दगी आदेश जारी होने के पश्चात भी कीमतों में वृद्धि की। (सुपुर्दगी के समय कीमतें परिवर्तनीय हैं)। जिसके कारण फिनाल के उपयोगकर्ता कंडिनाई में पड़ जाते थे और फिनाल विनिर्माताओं द्वारा वर्धित कीमत पुनरीक्षण, उनके तैयार उत्पाद की अतिम कीमत पर अनिश्चितता उत्पन्न करती थी।

(vii) आयातित फिनाल में वृद्धि, केवल असराप्तीय कीमतों के कारण नहीं है। वास्तव में फिनाल और इसके कच्चे माल दोनों की कीमतें गिरी हैं। साथ ही फिनाल पर 30% शुल्क, क्यूमिन/बेनजिन पर 15% शुल्क से बहुत अधिक है।

सी. आई. एफ. 97-98	सी. आई. एफ. 98-99	शुल्क
फिनाल	690	400
क्यूमिन	475	275
बेनजिन	280	210

असराप्तीय कीमतों/शुल्क दरों के उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि स्थानीय विनिर्माताओं की अच्छी कीमतें भिल रही हैं और इसलिए आयात से कोई खतरा नहीं है।

(VIII) कच्चे माल की कीमत तथा अन्य लागत के आधार पर वे लगभग 60% मूल्य में वृद्धि प्राप्त कर रहे हैं जो कि साधारण मूल्य वृद्धि से बहुत अधिक है। यहाँ तक कि संसार मर के अधिक क्षमता और कम अनावश्यक लागत वाले मुख्य फिनाल संयंत्र भी इतनी अधिक मूल्य में वृद्धि नहीं प्राप्त कर पाते।

(IX) यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दोनों विनिर्माताओं के फिनाल प्रमाण, पुराने संयंत्र तथा अधिक चालन लागत इत्यादि के बावजूद अच्छी लाम कमा रहे हैं।

(X) घरेलू उत्पादकों के स्टॉक विवरण में उनके पास 2000-3000 मी.टन की सूचीबद्ध स्टॉक है जो कि उनके व्यापिक उत्पाद का 5% और कुल उपभोग का 3% भी नहीं है। स्टॉक स्थिति स्वयं बताती है कि उनको बिकी / मूल्य वसूली में कोई कठिनाई नहीं है और इसलिए आयात से कोई खतरा नहीं है जो कि केवल मांग और आपूर्ति के अन्तर को ही पूरा कर रहा है।

(XI) रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण पूरी तरह से एकाधिकारिक स्थिति की ओर ले जाएगा और बहुत से घरेलू उद्योगों को गम्भीर संकट में डाल देगा।

च. घरेलू उत्पादकों के वृष्टिकाले

घरेलू उत्पादकों ने निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाए हैं :-

(क) मेसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि., कोवीन

(i) उनकी निर्माण यूनिटें (1) रसायनी- 410027, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र (2) अम्बलमुगल- 882302, जिला एरणाकुलम, केरल में हैं तथा फिनाल संयंत्र केवल अम्बलमुगल में स्थित है।

(ii) वे फिनाल भासक मूल आर्गेनिक केमिकल का विनिर्माण करते हैं जो कि कारबोलिक एसिड अथवा हाइड्रोक्सी बेनजीन, एसीटोन, एनिलीन, नाइट्रोटोल्यून्स, नाइट्रोक्लोरोबेनजीन, मोनोक्लोरोबेनजीन, फार्मलिहाइड, नाइट्रोबेनजीन, सलफ्यूरिक एसिड, साइक्लोहेक्सिनमाइन, एसिटेनिजाइड, कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन पैरोक्साइड, ब्यूटीन- 4-डिओल के नाम से भी जाना जाता है।

(iii) उनके द्वारा निर्मित फिनाल, किस्टल और हाइड्रोटेक दोनों, फिनोल फार्मलिहाइड ऐसिन्स, लेमिनेटेस, प्लाईबुड, पार्टिंकल बोर्ड, फार्मास्यूटिकल्स इत्यादि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। लेटर केमिकल, बिस्फेनोल-ए तथा एलिकल फिनाल के विनिर्माण में केवल फिनाल का किस्टल रूप ही इस्तेमाल किया जाता है।

(IV) फिनाल निर्माण में बेनज़ीन तथा प्रोपिलिन मुख्य कच्चा माल हैं जबकि क्यूमिन मध्यवर्ती है। फिनाल बनाने में एसिटोन सह उत्पाद के रूप में तैयार होता है। फिनाल और एसिटोन 1:0.6 के अनुपात में तैयार होता है।

(V) उनके उत्पाद की गुणवत्ता और स्वरूप आयातित उत्पाद के समान है।

(VI) उनकी फिनाल की वर्तमान उत्पादन लागत रु 25,000/- प्रति टन से अधिक है। स्वदेशी बिकी मूल्य आयातित फिनाल के उत्तराई के समय की लागत द्वारा संचालित होती है।

(VII) जहाँ पिछले सालों में फिनाल की घरेलू मांग में सुधार हुआ है, वही असामान्य वर्धित आयात के कारण उनकी उपयोगिता क्षमता में गिरावट आई है, जिसके कारण उनकी यूनिट की क्षमता पहुँची है।

(VIII) सर्व 1998-99 के दौरान आयातित फिनाल की कीमतों में तेजी से गिरावट हुई जिसके कारण घरेलू कीमतें बहुत अधिक गिर गईं।

(IX) वर्तमान केन्द्रीय बजट 1998-2000 के अनुसार फिनाल पर सीमा शुल्क और घटाकर 25% + 5% से 25% + 2.5% कर दिया गया है। इस प्रकार आयातित फिनाल की कीमतें लगभग 420/- रु. प्रति भी.टन सस्ती हो गईं। सीमा शुल्क लगाकर उत्तराई के समय की वर्तमान लागत लगभग 22,000/- रु. प्रति भी.टन पड़ती है।

(X) वर्धित आयात से उपयोगिता क्षमता कम होगी जिसके फलस्वरूप उत्पादन लागत अधिक होने और बिकी से कम उगाही के कारण हानि होगी। जो यूनिट एक लम्बे समय तक स्वत्थ इकाई रही हो और उपमोक्ता उद्योग को नियंत्रण फिनाल की आपूर्ति करती रही हो, वह हानिवाली इकाई में परिवर्तित होकर अव्याख्यातिक हो जाएगी।

(XI) समय के साथ-साथ जहाँ उत्पादन लागत कमोबेश बढ़ रही है, घरेलू कीमतें (जो कि अस्तराष्ट्रीय कीमतों, (सी.आई.एफ. भारत) आयात शुल्क और विनियम दर का कार्य है) लगभग स्थिर रही हैं अथवा बाजार शेयर बनाए रखने के लिए बहुत अधिक कम हुई है (जैसा कि पूर्व में किया गया) क्योंकि यदि एक बार बाजार समाप्त हो गया तो इसे फिर से प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। इससे लाभ में दबाव पड़ेगा।

(XII) फिनाल की सी.आई.एफ. इंडिया की जो कीमतें संसार के अन्य भागों की कीमतों के बराबर रहती थीं वे संसार के अन्य भागों जैसे कि अमरीका, यूरोप तथा सुदूर पूर्व की अपेक्षा बहुत गिर गई हैं। जहाँ यू.एस.जी.सी. (यू.एस.गल्फ टट) की कीमतें सितम्बर, 1998 के अन्त तक 110 अमरीकी डालर प्रति टन तक (जगवरी 1998 में 716 अमरीकी डालर प्रति टन से सितम्बर 1998 में 606 अमरीकी डालर प्रति टन, 15.36% की गिरावट) गिरी, सी.आई.एफ. इंडिया की कीमतें तो और भी अधिक, 275 अमरीकी डालर प्रति टन, गिरी (715 अमरीकी डालर प्रति टन से 440 अमरीकी डालर प्रति टन, 38.46% गिरावट थी) दिसम्बर के अंत तक सी.आई.एफ. इंडिया की कीमतें फिर से 395 अमरीकी डालर प्रति टन गिरी (कुल गिरावट 44.75%)

(XIII) एशिया के अन्य भागों में आर्थिक संकट देखते हुए विदेशी फिनाल उत्पादकों ने सारतीय विच्छसनीय बैंकिंग प्रणाली और तदनुसार सुरक्षित अदायगी के कारण सारतीय बाजार को लाभप्रद और सुरक्षित लक्ष्य पाया। फलस्वरूप वे भारत को बहुत कम कीमतों पर फिनाल देने को तैयार हैं।

(XIV) दिसम्बर, 1998 में भारत के लिए कीमतें यू.एस.जी.सी. की कीमतों के मुकाबले 70 अमरीकी डालर प्रति टन की छूट पर हैं। यह भारतीय उद्योग को भारी क्षति पहुँचा रही है, जिसे आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर बचाने की आवश्यकता है। पिछले पाँच वर्षों में सी.आई.एफ. भारत की कीमतों में अब तक की अधिकतम गिरावट को देखते हुए, पिछले तीन सालों में औसतन आयात 18500 टी.पी.ए. से बढ़ा है जिससे उनके लाभ में गिरावट आई है।

(XV) गत वर्षों के कुल आयात के 1.63 गुण के बराबर आयात पिछले 9 माह की अव्याधि में हुआ जिसमें से पिछले वर्ष के 80% आयात के तुल्य आयात 1998-99 की तीसरी तिमाही में हुआ। इन अत्यधिक कम कीमत वाले आयात के कारण भारतीय विनिर्माताओं को भी अपनी कीमतें, आयात की उत्तराई के समय की लागत, लगभग 24/- रु. किलो शुद्ध सी वी डी प्रतिकर के बराबर करने के लिए कम करनी पड़ेगी (जो कि पहले ही जनवरी, 1998 में 37/- रु. प्रति किलोग्राम से अक्टूबर, 1998 में 29/- रु. प्रति किलोग्राम और वर्तमान मूल्य स्तर 28/- रु. प्रति किलोग्राम तक कम की जा सकती है, सभी कीमतें मूल्य सूची की हैं)। अभी तक जनवरी 1998 के 37 रुपये प्रति किं० ग्रा० के सूचित मूल्य स्तर से 9 रु० प्रति किं० ग्रा० की गिरावट है।

(XVI) कच्चे माल की कीमतों में कोई भी अनुकूल कमी नहीं आई है। इस कारण उत्पादन लागत अधिक रहती है और लाभ में दबाव रहता है। बस्तुती और जाम में अत्यधिक कम। उनकी यूनिटों को निम्नलिखित क्षेत्रों में क्षति पहुँचा रही है (क) एथ ओ सी की शेयर कीमतें कम हो गई और (ख) सी आर आई एस आई एल द्वारा लम्बी अवधि में क्रेफिट रेटिंग ए ए (-) से ए (-) तथा कम अवधि के क्षेत्रों पर पी 1 (+) से पी 2 (+) कर दी गई है, कम कर दी गयी।

(XVII) कम कीमत पर वर्धित आयात के कारण अगस्त, 1998 से थोक फिनाल की बिक्री पर लाभ में तेजी से गिरावट आई और दिसम्बर, 1998 में 1,198/- रु. प्रति टन तक की हानि हुई जिससे केवल घार महीने की अवधि में सकल लाभ में 83% की कुल गिरावट हुई।

(XVIII) वर्धित आयात केवल कम कीमतों पर ही नहीं हुआ बल्कि व्यापारियों के लिए लम्बी अवधि के ऋण पर भी था। इस आयात पर हुए अतिरिक्त लाभ से, घरेलू उद्यमियों के उपभोक्ताओं द्वारा भी ऐसी ही सांग की गयी। फिनाल कर्जदारों ने जुलाई, 1998 में बिक्री के 62 दिनों को बढ़ाकर दिसम्बर, 1998 में 69 दिन कर दिए। घटता हुआ कुल लामाश, बढ़ता भंडार / सामान - सूची तथा ऋण की बढ़ी अवधि के कारण नकदी प्रवाह कम हो गया और सामान्य संचालन जारी रखने के लिए धन की उपलब्धता में कमी आई।

(XIX) मूल्य बस्तुती में सितम्बर, 98 में 30,420/- रु. प्रति भी.टन से दिसम्बर, 1998 में 24,620/- रु. प्रति भी.टन (19% की गिरावट) की कमी हुई और यह वही समय था जब फिनाल भारी मात्रा में कम कीमतों पर आयात किया गया था।

(XX) उच्छोने डीम्ड निर्यात योजना के तहत फिनाल के विभिन्न अस्तिम उपयोगकर्ताओं को अप्रैल-दिसम्बर, 1998 के दौरान 3,137 भी. टन फिनाल बेचा और यह प्रमाणित करेगा कि वे निर्यात प्रतिस्पर्धी थे।

(XXI) आगामी सप्ताह और महीनों में वास्तविक क्षति होने वाली है। फिनाल उद्योग के उभ्यूलन के रूप में होने वाली क्षति का दूरगामी प्रभाव निम्न कम के उद्योगों पर पड़ेगा और परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ेगी।

(XXII) अधिकांश क्षेत्रों द्वारा घरेलू सांग में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए वे प्रति यूनिट संचालन लागत कम करने तथा प्रभावी क्षमता को बढ़ाने के लिए वे अपनी तकनीक में सुधार ला रहे हैं तथा विनिर्माण की समस्याओं को दूर करते रहे हैं। हाल ही में उच्छोने अपनी 40000 टी.पी.ए से 45000 टी.पी.ए. प्रभावी क्षमता बढ़ाई है। विद्युत लागत कम करने के लिए उच्छोने कैप्टिव पावर जनरेशन संयंत्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं जो वर्तमान वित्तीय वर्ष 1998-99 से लाभ देना आरम्भ कर देगा। वे गुजरात प्रदेश या महाराष्ट्र के

दामोदर में 100000 टी.पी.ए अथवा 150000 टी.पी.ए की विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। एच.ओ.सी और एच. सी एल के बीच सहकारी प्रयास की समावेश है। तकनीकी आपूर्तिकर्त्ताओं तथा सलाहकारों की मदद से अपनी क्षमता बढ़ाकर तथा तकनीक आधुनिक बनाकर उनका अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बनने का प्रयास है।

(ख) हरछीलिया केमिकल्स लि. मुम्बई

- (i) वे मूल आर्मिक रसायनों तथा विशिष्ट वस्तुओं जैसे फिनाल, एसिटोन, थोलिक एनडोइंड, डायएसिटोन अल्कोहल, डोकिसिल फिनाल, नोमिल फिनाल, डाईफिनायल आक्साइड, आइसोब्यूटिल बैर्जीन, आइसोफोरोन, हीट ड्राईफर मीठिया, एसिटोफिनोन इत्यादि का निर्माण करते हैं।
- (ii) वे दो प्रकार के फिनाल किस्टेलाइन तथा हाइड्रोटेक बनाते हैं। जहाँ किस्टेलाइन फिनाल दोस रवेदार फिनाल है, वहीं हाइड्रोटेक फिनाल, फिनाल और पानी का मिश्रण है, जिसमें 10% से कम पानी होता है। इसी कारण फिनाल परिवेशी या ढंड में द्रवित रूप में रहता है और अस्सिम उपयोगकर्त्ताओं द्वारा उत्तराई के दौरान सामग्री समालने की प्रक्रिया को सरल बना देता है। वजन के अनुसार किस्टेलाइन फिनाल की शुद्धता कम से कम 99.5% है। परन्तु हाइड्रोटेक फिनाल का बीजक वस्तु में फिनाल की वास्तविक भात्रा के आधार पर बनाया जाता है।
- (iii) फिनाल का प्रयोग फिनाल फार्मलाइहाइड रेसिन, लेमिनेटो, प्लाइसुल, पार्टिकल बोर्ड, बिस्फिनाल-ए, एलिकल फिनाल, फार्मास्पूटिकल्स, डोकिसिल आक्साइड इत्यादि को बनाने में होता है। लैदर केमिकल्स तथा बिसफिनाल-ए में प्रयोग के लिए अधिकांशतः केवल किस्टालिन फिनाल की आवश्यकता होती है।
- (iv) आयतित फिनाल और उसके द्वारा निर्मित फिनाल हर प्रकार से एक समान है।
- (v) वर्तमान वित्त वर्ष के पहले नौ महीने की तथा पिछले तीन वित्त वर्षों के उत्पादन की लागत औसतन रु. 33,900 प्रति मी. दृज है।
- (vi) 10,000 टी.पी.ए क्षमता की फिनाल सुविधा 1960 के दशक में स्थापित की गयी थी और 1968 में संचालन योग्य हुई। फिनाल विनिर्माण सुविधा में शुरूआती निवेश रु. 3.31 करोड़ था। समय के साथ - साथ पूर्णतः आन्तरिक जमा के साध्यम से वित्त पोषित साध्यमों में पूँजी निवेश करके छित्तीय वर्ष 1996-97 के अंत तक क्षमता लगभग 20,000 टी.पी.ए से अधिक बढ़ा ली गयी थी। संयंत्र की वर्तमान क्षमता 30000 टी.पी.ए है।
- (vii) वर्ष 1995-96 के लिए फिनाल की पैकिंग लागत लगभग 3 रु. 50 पैसे प्रति किलोग्राम, वर्ष 1996-97 के लिए (औसतन) 3 रु. 75 पैसे और वर्ष 1997-98 के लिए 4/रु. प्रति किलोग्राम थी। थोक और पैक किए हुए फिनाल की बिक्री वसूली में लगभग यही अन्तर है। फिनाल का बिक्री मूल्य उत्तराई के समय की लागत में समानता के आधार पर होता है जो कि लागत जमा के आधार पर। फलस्वरूप कच्चे माल की कीमत और बिक्री मूल्य का आपस में कोई संबंध नहीं है।

(viii) जहाँ उत्पादन लागत स्थिर रही अथवा समय के साथ बढ़ती रही, बाजार शेयर बचाने के लिए (जो कि अक्षराष्ट्रीय कीमतों, (सी आई एफ मारत) , आयात शुल्क और विभिन्न दर से संबंधित है) घरेलू कीमतों को या तो स्थिर रखना पड़ा या फिर बहुत तेजी से कम करनी पड़ी (जैसा कि बाद में भी किया गया) क्योंकि यदि एक बार बाजार हाथ से गिरकल जाए तो उसे फिर से वापस पाना बहुत कठिन होता है ।

(ix) सी.आई.एफ. इण्डिया फिनाल की कीमतें जो कि विश्व के अन्य क्षेत्रों की कीमतों के समान होती थी, वे विश्व के अन्य क्षेत्रों जैसे कि अमरीका, यूरोप तथा सुदूर पूर्व के मुकाबले अत्यधिक तेजी से कम हो गई हैं।

(x) जहाँ यू.एस.जी.सी (अमरीकी गल्फ टट) की कीमतों में सितम्बर, 98 के अंत तक 110 अमरीकी डालर प्रति टन की गिरावट आई, (जनवरी 1998 में 716 अमरीकी डालर प्रति टन से सितम्बर, 98 में 606 अमरीकी डालर प्रति टन, 15.36% की गिरावट) सी.आई.एफ. इण्डिया की कीमतें और भी अधिक तेजी से 275 अमरीकी डालर प्रति टन गिरी (715 अमरीकी डालर प्रति टन से 440 अमरीकी डालर प्रति टन, एक ही समय में 38.46% की गिरावट) । दिसम्बर के अंत तक सी.आई.एफ. इण्डिया की कीमतें 395 अमरीकी डालर प्रति टन और गिर गई (कुल गिरावट 44.75%) ।

(xi) एशिया के अन्य भागों में आर्थिक संकट होने के कारण रिटेली फिनाल उत्पादक, विश्वस्त भारतीय बैंकिंग प्रणाली और उसके परिणामस्वरूप अदायगी की सुरक्षा के कारण भारतीय बाजार को सुरक्षित और लाभप्रद लक्ष्य मानने लगे । परिणामस्वरूप वे भारत को बहुत कम कीमतों पर फिनाल बेचने को तैयार थे ।

(xii) दिसम्बर, 1998 के लिए यू.एस.जी.सी की कीमतों से भारत के लिए कीमतें लगभग 70 अमरीकी डालर प्रति टन की छूट पर थीं । यह भारतीय उद्योग को भारी क्षति पहुँचा रही है, जिससे आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाकर बचाने की आवश्यकता है ।

(xiii) पिछले पांच वर्षों में सी.आई.एफ. इण्डिया की कीमतों में अब तक की सर्वाधिक गिरावट के कारण पिछले तीन वर्षों के औसतन आयात 18500 डी.पी.ए से भी अधिक बढ़ोत्तरी मूर्झ है, जिससे आयात के उत्तराई के समय की लागत में कमी के बराबर लाभ और कम हो जाएगा ।

(xiv) पिछले वर्ष में जितना भी आयात हुआ है, उसका 1.63 गुना आयात 9 माह के कम समय में हुआ और पिछले वर्ष के आयात के 60% आयात के बराबर आयात 1998-99 की तीसरी. तिमाही में हुआ ।

(xv) कम कीमत वाले इन आयातों के कारण हरडीलिया को अपनी कीमतें जनवरी, 98 में 37/- रु. प्रति किलोग्राम से घटाकर अन्तृष्ट, 1998 में 29/-रु० प्रति किलोग्राम करनी पड़ी, जो वर्तमान में 28/- रु. प्रति किलोग्राम है तथा सभी कीमतें मूल्य सूची की हैं । अतः आयातित सामग्री की उत्तराई के समय की लागत की बराबरी करने हेतु वास्तविक कीमत पर छूट देने की आवश्यकता है । परिणामस्वरूप, हरडीलिया का लाभांश गंभीर रूप से दबाव में है ।

(xvi) उच्चोंसे फिनाल की उपलब्धता सुनिश्चित करके निम्नक्रम के उद्योगों के विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जिनमें से अधिकतर निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ थीं ।

(xvii) उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में फिनाल की आपूर्ति जारी रखने के लिए मई-जून, 1998 के दौरान उन्होंने फिनाल का अपना कैप्टिव उपभोग कम करके उच्च मूल्य के फिनाल व्युत्पन्नों का उत्पादन त्याग दिया।

(xviii) 1998-99 की पहली तीन तिमाहियों में फिनाल का आयात दो गुना से भी अधिक हो गया और सितम्बर 1998 से दिसम्बर, 1998 के दौरान हुआ आयात पूरे 1997-98 के दौरान हुए आयात से भी कहीं अधिक था। 1998-99 में प्रमाणी आयात हड्डीलिया के फिनाल के बाजार शेयर से भी अधिक था।

(xix) फिनाल के लिए मूल्य वसूली (थोक) जो अप्रैल, 1998 में 35,772/- रुपये प्रति मीट्रिक टन थी, वह दिसम्बर, 1998 में घटकर 24,934/- रुपये प्रति मीट्रिक टन हो गई। अगस्त, 1998 से फिनाल की थोक बिक्री पर लाम तेजी से गिर गया और दिसम्बर, 1998 में 3,298/- रुपये प्रति टन की हाँगि हुई।

(xx) क्षमता की उपयोगिता में कमी होने से हड्डीलिया के लिए प्रति टन फिनाल की कीमतों की स्थिर लागत में महत्वपूर्ण बढ़ि होने से लाम और कम होगा।

(xxi) अत्यधिक कम कीमत पर भारी मात्रा में फिनाल के आयात और लम्बी अवधि के कैप्टिव से भारतीय बाजारों में फिनाल का बड़ी मात्रा में आयात होने के कारण घरेलू विनिर्माताओं को हालात मजबूर कर रहे हैं कि वे अपने ग्राहकों को और अधिक कैप्टिव अवधि दें। पिछले कुछ महीनों से कर्जदारों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी हो गई है जिससे सक्रिय पैंजी का कम लम्बा हो गया है और अन्तोतगत्वा नकदी गंभीर रूप से असरमार्गी है। फलस्वरूप हड्डीलिया को आपूर्तिकर्ताओं को समय पर अदायगी करने से कठिनाई हो रही है। उनको बाजार में चल रही वर्तमान दरों से भी अधिक दरों पर इंटर कॉर्पोरेट डिपोजिट के रूप में फण्ड उधार लेना पड़ रहा है जिसके कारण लाम और कम हो रहा है।

(xxii) फिनाल की कम कीमतों के कारण, कैप्टिव रेटिंग के लिए हड्डीलिया का कार्य निष्पादन का मापदण्ड भी बिगड़ गया जिसने उसित कीमत पर निधि को प्राप्त करना और अधिक कठिन कर दिया।

(xxiii) नकदीकरण की बिगड़ती स्थिति के कारण (और फिर लाभांश में कमी से) हड्डीलिया को वित्तीय संस्थानों से निधि प्राप्त करने से बहुत अधिक कठिनाई हो रही है। इससे 100,000 टी.पी.ए. क्षमता वाले ग्रीनफील्ड फिनाल संयंत्र के निर्माण के लिए दीर्घ अवधि की योजनाओं को कार्यान्वित करने में भी यह अधिक विलम्ब करेगा। दूसरी तरफ वित्ती व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) से भारतीय व्यवसायद्वाता के फलस्वरूप उभरती हुई आर्थिक परिस्थिति में हड्डीलिया के भविष्य में व्यावर के लिए इस परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन आवश्यक है।

(xxiv) पिछले कुछ वर्षों में फिनाल पर आयात शुल्क बहुत कम कर दिया गया है जब कि इसके कच्चे माल पर आयात शुल्क से अल्प मात्रा में कमी की गई है। फिनाल पर आयात शुल्क और इसके काल्पनिक बेर्जीन तथा प्रोपिलीन के आयात शुल्क में अन्तर तेजी से कम होता जा रहा है। वायुमण्डलीय परिस्थितियों के अधीन प्रोपिलीन एक गैस होने के कारण इस पर माल ढुलाई भाड़ा बहुत अधिक है (एफ.ओ.बी कीमत का एक महत्वपूर्ण %)। इसके अलावा, डमारे तटों पर इसके रख रखाव के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध न होने के कारण प्रोपिलीन का आयात नहीं किया जा सकता। हड्डीलिया के लिए प्रोपिलीन की कीमतें और जगहों जैसे अमरीका, यूरोप या नद्य पूर्व, के मुकाबले अत्यधिक ऊची हैं जिससे उनकी कठिनाइयां और बढ़ गयी हैं।

(xxv) प्राप्त सूचना के अनुसार यह महसूस किया जा रहा है कि अगले पाँच वर्षों में फिनाल की क्षमता में वृद्धि आपूर्ति को बहुत पीछे छोड़ देगी। वास्तव में इसके सह उत्पाद एसिटोन की भी भविष्य में मौंग और पूर्ति के बीच संतुलन के बारे में भी चिंता है। फिनाल के वर्तमान और विनिर्माताओं की विस्तारीकरण योजनाओं तथा नयी योजनाओं के आधार पर 40% अतिरिक्त क्षमता बढ़ने की समावना है। वर्तमान और निकट भविष्य के विस्तारीकरण से ग्लैडबैक में फिनालकेमी के 70,000 टी.पी.ए. कैपरोल्यूम के (70,000 टी.पी.ए.) (इरटिसा, स्पेन के 1,50,000 टी.पी.ए. को छोड़कर) तथा डी एस एम के (20,000 टी.पी.ए.) को मिलाकर यूरोप के बहुत से उद्यम सम्मिलित हैं, जैसा कि एक प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय बाजार एजेंसी द्वारा रिपोर्ट दी गयी है।

(xxvi) मुख्य अमरीकी परियोजनाओं को अभी प्रवाह से आना है। जैसा कि ख्याति प्राप्त एक अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा रिपोर्ट दी गई है। फिनालकेमी का सोबिल अलबामा संयंत्र एवं शेल के निवेश का वर्ष 1999 में आरंभ होना अभी विद्यारथीन है। कुम्हो और मिल्सुई द्वारा एशिया में अपनी योजनाओं पर कियाशील होने के बारे में रिपोर्ट हैं जिससे कि हमारे क्षेत्र में अन्य देशों/ क्षेत्रों से आयात की आशंका साथ-साथ अतिरिक्त क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी होगी। एशियाई फिनाल क्षमता, मिल्सुई केमिकल्स के 200000 टी.पी.ए क्षमता के संयंत्र हेतु योजना की घोषणा के साथ बढ़ने के लिए तैयार है। भव्य पूर्व से फीडरस्टाक की उपलब्धता की तुलना में भविष्य में मौंग में वृद्धि की तीव्र समावना और अपनी सामरिक स्थिति के साथ केवल भारतीय उपमहाद्वीप ही मिल्सुई परियोजना आरंभ करने की तुलना में ग्रीष्मफील्ड फिनाल सुविधा हेतु बेहतर अवसर प्रदान करता है।

(xxvii) विश्वस्तरीय फिनाल क्षमता में प्रस्तावित विस्तार अपने रास्ते पर है। एशियाई अर्थव्यवस्था में संकट के रहते क्षमता में वृद्धि के साथ कदम मिला कर न चल पाने के बजाय मौंग के बारे में चिंता की दृष्टि से यह स्पष्ट रूप से न्यायसंगत नहीं है। फिनाल के परिदृश्य को देखते हुए एक विश्वस्तरीय अग्रणी एजेंसी का पूर्वानुमान है कि 1999 से 2005 के बीच बाजार बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। मूल्यों के बहुत कम स्तरों पर रुके रहने की समावना है।

(xxviii) निर्यात के लिए लाईफिनायल के विनिर्माण हेतु हरणीलिया फिनाल का बहुत कम मात्रा में शुल्क मुक्त आयात करता है।

(xxix) आयातित फिनाल की तुलना में अपने उत्पाद की मात्रित्वात्मकता में सुधार लाने के लिए जनकारात्मक समायोजन हेतु उच्चोने कई कदम उठाए हैं।

(xxx) उनके द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़े प्रामाणिक हैं जो कि विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं।

(xxxi) अंतशेष मंडार का उल्लेख करने में कुछ लिपिकीय शुटि हो गई है। याचिका में उल्लेख किए गए अंतशेष आंकड़े ठीक हैं।

(ग) नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन, नेवेली

(i) फिनाल, जिसे कि कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, उनके द्वारा लिकेटिंग और कार्बनीकरण संयंत्र में लिग्नाइट लिकेट की कार्बनीकरण प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में विनिर्मित किया जाता है।

(ii) वर्ष 1995-96 और उससे आगामी वर्षों के दौरान फिनाल की उनकी स्थापित क्षमता, उत्पादन, बिक्री और अंतर्राष्ट्रीय निम्नानुसार है :-

(मी० टन)

वर्ष	स्थापित क्षमता	उत्पादन	बिक्री	अंतर्राष्ट्रीय
1995-96	800	504.210	541.611	109.846
1996-97	800	352.597	419.206	48.805
1997-98	800	835.215	571.007	307.445
1998-99	800	529.002	541.222	295.245

(iii) उनके द्वारा विभिन्न फिनाल विभिन्न केमिकल उत्पाद यथा पोलीमर्स, बैकलाइट लेसिनेट्स, रेसिन्स, विस्फोटक, परफ्यूमरी डिसइन्फेक्टेंट, विद्युतीय इन्सुलेशन आदि के विनिर्माण में प्रयुक्त होता है।

(iv) वर्ष 1997-98 के दौरान 835 टन के उत्पादन की तुलना में 1998-99 में उत्पादन केवल 529 टन था और उत्पादन में 308 टन की कमी थी। क्षमता उपयोगिता में गिरावट लगभग 35% थी।

(v) 31.3.99 तक 309 टन के अंतर्राष्ट्रीय के कारण उन्हें लगभग एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। गत वर्ष (अर्थात् 1997-98) की तुलना में 1998-99 के दौरान 308 टन के उत्पादन में कमी के कारण बिक्री प्राप्ति में कमी लगभग एक करोड़ रुपये है।

(vi) 34000 रु० प्रति टन के वर्तमान मूल्य पर उन्हें लगभग 2500 रु० प्रति टन की हानि हो रही है। यदि 24000 रु० प्रति टन की आयातित लागत से बिक्री मूल्य की तुलना की जाती है तो 10000 रु० प्रति टन की अतिरिक्त हानि बढ़ जाएगी। 800 टन के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में अतिरिक्त हानि लगभग 80 लाख रु० होगी।

(vii) निष्कर्ष :

1. मैंने मामले के रिकार्ड एवं घरेलू उत्पादकों, उपयोगकर्ताओं/ आयातकों, निर्यातकों और निर्यातक सरकारों द्वारा प्रस्तुत जवाबों को ध्यान से पढ़ा है। विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत जवाबों एवं उनसे उठाने वाले मुद्दों पर भीचे दिए गए विष्कर्षों में यथोचित स्थान पर विचार किया गया है। तथापि, मामले की अच्छाइयों पर चर्चा शुरू करने से पूर्व जॉच शुरू करने के नोटिस को भेजने से संबंधित आरम्भिक मुद्दों पर विचार करना आवश्यक समझा गया है।

(viii) जाव शुरू करने का नोटिस भेजना :

यह आरोप लगाया गया है कि जॉच शुरू करने का नोटिस सभी इच्छुक पक्षों को नहीं भेजा गया था। इस संबंध में यह महसूस किया जाता है कि दिनांक 2.2.99 का नोटिस भारत सरकार के शासकीय गजट से

दिनांक 8.2.99 को प्रकाशित किया गया था और जॉच शुल्क करने से संबंधित नोटिस की प्रति उन सभी ज्ञात इच्छुक पक्षों को भेजी गई थी जिनके नाम एवं पते याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। जॉच के लिए कोई भी पक्ष जो कि इच्छुक पक्ष के रूप में समझे जाने के इच्छुक हों, अपना अस्यावेदन महानिदेशक को प्रस्तुत करने के लिए नोटिस के पैराग्राफ 10 में विशेष रूप से प्राप्तधान किया गया था। कुछ पक्षों ने जिनका नाम याचिका से शुल्क में नहीं था, महानिदेशक को अस्यावेदन किया और उन्हें भी जॉच में इच्छुक पक्ष के रूप में शामिल कर लिया गया था। इसलिए यह महसूस किया जाता है कि सभी इच्छुक पक्षों को अधिसूचित करने की आवश्यकता को विधि के अनुसार पूरा कर लिया गया है।

2. जॉच के अधीन उत्पाद :

(i) जॉच के अधीन उत्पाद फिनाल है जो एक मूल आर्गेनिक केमिकल है और उसका केमिकल फार्मूला सी 6 एवं 5 ओ एवं है और जिसे कार्बोलिक एसिल के रूप में भी जाना जाता है।

(ii) फिनाल, उत्तर तापमान और दबाव पर धायु का प्रयोग करके क्यूमिन के आक्सीडेशन द्वारा या लिमाइट / कोल के विध्यंसक आसेन द्वारा प्राप्त तारकोल से निर्मित होता है। कम सांकेतिकरण पर उत्पाद क्यूमीन हाइड्रोपेराक्साइड है जो कि अल्कली से धोया जाता है और उच्च शक्ति तक सांकेतिक रूप से उत्पादित किया जाता है। तब यह एवं 2 ओ 4 के साथ मिलाया जाता है जिसके कारण वलीवेज रिएक्शन होता है जो फिनाल और एसीटोन देता है। इसे अम्लता दूर करने हेतु धोया जाता है और अनरिएक्टेड क्यूमीन फिनाल देने हेतु आसवन कालम की श्रेणी में डिस्टिल्ड किया जाता है (जो कि फिनाल और एसीटोन में परिवर्तन के लिए रिसाइकिल किया जाता है) इस प्रकार प्रोपिलीन और ब्ल्यूजीन के बीच प्रतिक्रिया द्वारा क्यूमीन का उत्पादन किया जाता है।

(iii) फिनाल दो रूपों में यथा क्रिस्टल और हाइड्रोटेड रूप में विभिन्नित किया जाता है। फिनाल का गलनांक 43 डिग्री सेलिसियस है और जब तक आसपास का तापमान उच्च नहीं होता है यह क्रिस्टलिन रूप में रहता है। हाइड्रोटेड फिनाल में फिनाल को तरल अवस्था में रखने हेतु पानी की धोड़ी मात्रा मिलायी जाती है। तथापि हाइड्रोटेड फिनाल की बिक्री वास्तविक फिनाल घटक अर्थात् 100% फिनाल घटक के आधार पर आधारित है।

(iv) फिनाल फार्मल्डाइहाइड रेसिन्स, लेसिनेट्स, प्लाईवुड, प्लास्टिक बोर्ड, बिसफिनोल-ए, अल्कायल फिनाल, फार्मास्युटिकल आदि के विनिर्माण में प्रयुक्त होता है।

(v) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के उपशीर्ष 2907.11 एवं (हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्काउन ऐण्ड कोडिंग सिस्टम) पर आधारित भारतीय व्यापार वर्गीकरण के 29071102 के अधीन फिनाल को वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अधीन फिनाल का यह वर्गीकरण सुविधा के प्रयोजन से दर्शाया गया है और किसी भी रूप में जॉच के अधीन उत्पाद को सम्मिलित करने के कार्यक्षेत्र को सीमित नहीं करता है।

(vi) फिनाल के गलनांक के कारण एवं आयत के पत्तन पर समुद्र के धोय विशेष टैकर, गरम रोड टैकर और गर्म भंडारण टैक की आवश्यकता के कारण 100% शुद्ध फिनाल अर्थात् क्रिस्टल रूप में फिनाल की अलग करने का दावा किया गया है। तथापि इस दावे को इन तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण की आवश्यकता है कि

फिनाल को तरल अवस्था में रखने के लिए शुद्ध फिनाल में पानी की थोड़ी मात्रा मिला कर हाइड्रोटेड रूप में फिनाल प्राप्त किया जाता है। इसनिए 100% शुद्ध फिनाल को अलग करने के पक्ष में जो तथ्य बताए गए हैं वे 100% शुद्ध फिनाल एवं हाइड्रोटेड फिनाल में विभेद नहीं करते हैं लेकिन वे केवल अतिरिक्त संखरणाव की आवश्यकता और/या हाइड्रोटेड फिनाल की तुलना में 100% शुद्ध फिनाल के आयात में सम्मिलित अतिरिक्त लागत की ओर इशारा करते हैं। इसलिए इस दावे में कोई मजबूती नहीं है। इसलिए वर्तमान जाँच के दायरे में किस्टलिन फिनाल एवं हाइड्रोटेड फिनाल, दोनों ही सम्मिलित हैं।

3. घरेलू उद्योग

मैं हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिंग, मुम्बई (एच ओ सी) और मैं हरडीलिया केमिकल्स लिंग मुम्बई (एच सी एल) द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया है जो कि सिंधेटिक रूट अर्थात् क्यूमिन रूट से फिनाल के विनिर्माण करने वाले केवल दो विनिर्माता हैं। उनके पास फिनाल उत्पादन की 75000 मी. टन (1998-99) की संयुक्त क्षमता है। 1997-98 के दौरान उन्होंने 69281 मी.टन (71,500) मी. टन क्षमता फिनाल का उत्पादन किया और 1998-99 के प्रथम तीन महीने के दौरान उन्होंने 48703 मी. टन फिनाल का उत्पादन किया। मैं नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिंग (एम एल सी) भी लिग्नाइट/ कोल के विध्वंसक आसवन से प्राप्त तार से फिनाल का विनिर्माण करते हैं लेकिन उनकी उत्पादन क्षमता केवल 800 मी.टन की है। इसीलिए एच ओ सी और एच सी एल द्वारा उत्पादन के एक बड़े माग का उत्पादन करते हैं। हालांकि आवेदन प्रस्तुत करने में एन एल सी याचिकाकर्ताओं के साथ नहीं थे परन्तु उन्होंने जाँच ने माग लिया है और फिनाल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु अपना समर्थन दिया है। इसलिए एच ओ सी और एच सी एल द्वारा प्रस्तुत आवेदन को ही घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत आवेदन माना गया है।

4. बड़ा हुआ आयात :

(i) भारत में फिनाल का आयात चीन, चीनी ताइपेई, फ्रास, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, ची पी.आर कोरिया, आर पी कुवैत, मलेशिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका से होता है। वर्तमान में भारत में फिनाल के मुख्य निर्यातक दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान हैं। फिनाल पर आयात शुल्क, जो कि 1993-94 में 85% था, वह 1994-95 में 65%, 1995-96 में 40% एवं 1996-97 में 30% तक कम कर दिया गया। 1997-98 के अंत में फिनाल पर आयात शुल्क 25% + 2% था, लेकिन बाद में फिनाल के आयात पर 3% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया गया था। वर्तमान में, सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क और सीमा शुल्क के विशेष अतिरिक्त शुल्क को छोड़कर फिनाल पर 25% + 2.5% के यथामूल्य की दर पर आयात शुल्क देय है।

(ii) 1994-95 में भारत में कुल 6664 मी. टन फिनाल मुख्यतः जापान (2002 मी.टन) जर्मनी (1225 मी.टन) यू.एस.ए (968 मी.टन) दक्षिण अफ्रीका (1263 मी.टन) से आया। 1995-96 में फिनाल का आयात असाधारण रूप से 21752 मी.टन तक पहुँच गया जो कि मुख्यतः जापान (4767 मी.टन) ताइवान (1048 मी.टन) जर्मनी (838 मी.टन) नीदरलैंड (8731 मी.टन), फ्रास (1075 मी.टन) यू.एस.ए (4539 मी.टन), दक्षिण अफ्रीका (1871 मी.टन) और न्यूजीलैंड (539 मी.टन) से आयात किया गया। आगामी दो वर्षों के दौरान आयात कमश्व 1995-96 में 21752 मी.टन से 1996-97 में 19545 और 1997-98

में 15352 मी.टन तक गिर गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा 1998-99 के प्रथम नौ महीनों (अप्रैल 1998 से दिसम्बर 1998) में 25048 मी.टन के फिनाल के आयात का दावा किया गया है जिसमें फिनाल का शुल्क मुक्त आयात भी शामिल है। मैं० केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स ने तर्क दिया है कि निर्यात उत्पादन में प्रयोग हेतु फिनाल के आयात से याचिकाकर्ताओं का प्रभावित होने का दावा नहीं किया जा सकता। मैं० केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स का यह तर्क सुनिःसंगत नहीं है क्योंकि चाहे घरेलू उत्पादन या निर्यात उत्पादन, जिस किसी के लिए फिनाल प्रयोग होता है, उससे घरेलू उत्पादकों के लिए बाजार की स्थापना होती है। इसलिए निर्यात उत्पादन में प्रयोग हेतु आयातित फिनाल की मात्रा को कुल आयात में शामिल करने की आवश्यकता है।

(iii) आठेंद्रकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़ों की प्रामाणिकता के बारे में विशेषत अप्रैल-दिसम्बर 1998 की अवधि के आंकड़ों के बारे में कुछ पक्षों द्वारा सदेह व्यक्त किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू उत्पादक, जिन्होंने 8 जनवरी, 1999 को फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए आवेदन किया था, के पास दिसम्बर, 1998 तक के आयात के प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सकते थे। और जबकि घरेलू उत्पादकों ने दावा किया है कि गोवा पत्तन से फिनाल का कुछ आयात किया गया, गोवा पत्तन पर कोई आयात हुआ ही नहीं। इस सम्बन्ध में घरेलू उत्पादकों ने प्रस्तुत किया है कि 1997-98 तक के आंकड़े डी जी सी आई एस कलकत्ता से प्राप्त किए गए हैं। 1998-99 की प्रथम तीन तिमाहियों के डी जी सी आई एस के आंकड़ों के प्रकाशन से बिलम्ब होने के कारण उन्होंने बाजार आसूचना स्त्रोतों पर आधारित आंकड़े लिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि वे विभिन्न बाजार आसूचना स्त्रोतों गया व्यापारियों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय), पत्तन पर टैक आपरेटरों, आयातकों और निर्यातकों आदि के जरिए आंकड़ों की मासिक आधार पर भारीटरिंग करते हैं और यह कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात के आंकड़े पर्याप्त विवरण के साथ हैं। आयात आंकड़ों की प्रामाणिकता के संबंध में यह महसूस किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत 1994-95 से 1997-98 तक की अवधि के आंकड़े डी जी सी आई एस के आंकड़ों पर आधारित हैं और ये प्रमाणित हैं। जहाँ तक 1998-99 (अप्रैल-दिसम्बर) के आंकड़ों का प्रश्न है, यह महसूस किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं ने जहाजों के नाम, पहुंचने की तिथि, मात्रा लादने का पत्तन और 23348 मी.टन के संबंध में मूल्य, कांडला पत्तन पर आयातित 22348 मी.टन और कलकत्ता पत्तन पर आयातित 1000 मी.टन आदि दर्शाते हुए आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने पैक स्थिति में 1700 मी.टन फिनाल के आयात का भी दावा किया है। जहाँ तक गोवा पत्तन के माध्यम से आयात का संबंध है, उन्होंने स्पष्ट रूप में उल्लेख किया है कि मैं० केसर पेट्रोप्रोडक्ट लिं० मुम्बई, जिन्होंने गोवा पत्तन के माध्यम से आयात के बारे में सदेह व्यक्त किया है उन्होंने ही गोवा/ मार्मांगोआ पत्तन के माध्यम से आयात किया है और उन्हें एवं सी एल ने विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराई थी। यह भी महसूस किया जाता है कि किसी भी पक्ष द्वारा अप्रैल-दिसम्बर 1998 की अवधि के आयात आंकड़ों में किसी विशिष्ट विसंगति की ओर संकेत नहीं किया है। तथापि, फिनाल के आयात आंकड़े सत्यापन के अधीन थे। कांडला सीमा शुल्क गृह ने अप्रैल-दिसम्बर 1998 के दौरान 22028.414 मी.टन फिनाल के आयात की पुष्टि की है। 1000 मी.टन फिनाल का आयात कलकत्ता पत्तन पर एवं 1521.943 मी.टन फिनाल का आयात पैक अवस्था में विभिन्न पत्तनों पर किया गया। कांडला सीमा शुल्क पत्तन के माध्यम से 22348 मी.टन आयात एवं कांडला सीमा शुल्क द्वारा पुष्ट किए 22028.414 मी.टन के आयात के आंकड़ों के बीच जो थोड़ा अन्तर है वह लदान मात्रा के बिल (याचिकाकर्ताओं पर आश्रित) और मात्रा में कमी (सीमा शुल्क गृह कांडला के माध्यम से आयात के रूप में मात्रा गया) के बीच अन्तर के कारण है। मैं० कुम्हों पी एंड बी केमिकल्स इन्क, कोरिया की ओर से मैं० सैमसंग कारपोरेशन ने 1996 से 2099 मी.टन एवं 1997 से 4351 मी.टन की तुलना में 1998 में 9801 मी.टन फिनाल के भारत में निर्यात की पुष्टि की है। कुछ आयातकों के सत्यापन से प्रकट होता है कि अप्रैल से दिसम्बर 1998 के दौरान मैं० केसर पेट्रोप्रोडक्ट ने

1683 मी.टन फिनाल, मैं० सी.जे.शाह एवं कम्पनी ने 2487 मी.टन फिनाल एवं मैं० कोष्टीलाल मणिलाल ने 289 मी.टन फिनाल का आयात किया ।

(iv) उपरोक्त चर्चाओं के परिप्रेक्ष्य में यह महसूस किया जाता है कि 1998-99 (अप्रैल-दिसम्बर) से भारत में फिनाल का आयात 24550 मी.टन था । नीचे सारणी 1. 1994-95 से 1998-99 (दिसम्बर तक) के आंकड़े प्रदर्शित करती है :-

सारणी 1

वर्ष	मात्रा (मी.टन)	आयात	
		मूल्य (रु० एम.एन)	
1994-95	6663.963	130.707	
1995- 96	21752.174	450.512	
1996-97	19545.737	443.566	
1997-98	15312.373	380.512	
1998-99(अप्रैल-दिसम्बर)	24550.357	-	

(v) इस प्रकार आयात 1994-95 में 6664 मी.टन से बढ़कर 1995-96 में 21752 मी.टन हो गया । आयात 1995-96 की तुलना में गिर कर 1996-97 में 19546 मी.टन और 1997-98 में 15312 मी.टन तक गिर गया है । इस अवधि अर्थात् 1995-96 से 1997-98 के दौरान भारत में फिनाल के आयात की औसत मात्रा 18870 मी.टन प्रतिवर्ष (एम टी पी ए) थी । तथापि 1998-99 के प्रथम नौ महीनों में, आयात में 24550 मी.टन अर्थात् आनुपातिक आधार पर 1995-98 के औसत आयात से 73.5% की वृद्धि हुई अर्थात् तात्कालिक वर्ष 1997-98 की तुलना में, 1998-99 के प्रथम नौ महीने में आयात आनुपातिक आधार पर 113.8% तक बढ़ा । तुलनात्मक मद्दों में आयात घरेलू उत्पादन का 1994-95 में 11.53%, 1995-96 में 34.14%, 1996-97 में 34.01%, 1997-98 में 22.1% और 1998-99 (अप्रैल-दिसम्बर) में 50.4% था । घरेलू उत्पादन, आयात के आंकड़े और घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात नीचे सारणी 2 में दिया गया है ।

सारणी 2

वर्ष	घरेलू उत्पादन (मी.टन)	आयात (मी.टन)	घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में आयात
1994-95	57780	6664	11.53
1995-96	63719	21752	34.14
1996-97	57466	19546	34.01
1997-98	69281	15312	22.1
1998-99	48703	24550	50.4
(अप्रैल-दिसम्बर)			

(vi) इस प्रकार कुल मिलाकर एवं घरेलू उत्पाद की तुलना में आयात में वृद्धि हुई है।

(vii) मैं० केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स द्वारा एक मुद्दा उठाया गया है कि जॉच आरैम करने की अधिसूचना एक समान अवधि का अनुसरण नहीं करती। वर्धित आयात स्पष्टतया पिछले 1994-95 से माना गया है क्योंकि उस वर्ष आयात बहुत कम था और आगामी वर्षों में तुलनात्मक रूप में इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई है। बाजार शेयर भी 1995-96 से माना गया है और घरेलू उद्योगों का उत्पादन 1996-97 से माना गया है। इस संबंध में यह महसूस किया जाता है कि रक्षोपाय शुरू करने के लिए एक मूलमूल आवश्यकता यह है कि बढ़ा हुआ आयात घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने का कारण होना चाहिए। इसलिए वर्धित आयात का यह तथ्य या तो पहले घटित हो या घरेलू उत्पादकों को गम्भीर क्षति या गम्भीर क्षति होने की आशंका के साथ विद्यमान होना चाहिए। इसलिए वर्धित आयात के तथ्य का समुचित मूल्यांकन करने हेतु किसी एक अवधि के आयात आकड़ों का परीक्षण करना आवश्यक है। इस मामले में, 1994-95 में फिनाल के आयात को ध्यान में रखते हुए आदेदकों वो कोई अनुचित लाभ प्रदत्त नहीं किया गया है जो कि अनुवर्ती वर्षों की तुलना में आयात की कम मात्रा दर्शाता है। वास्तव में, अगले वर्ष के दौरान फिनाल का आयात असाधारण रूप में 21,752 मी.टन तक बढ़ा परन्तु उसके पश्चात 1998-99 में प्रथम तौ महीनों में 24550 मी.टन तक पहुँचने से पूर्व यह 1997-98 में 15,312 मी.टन तक गिर गया था। जैसा कि पूर्ववर्ती वर्षों में महसूस किया गया है कि 1995-98 के दौरान हुए औसत आयात से 1998-99 के प्रथम तौ महीनों में आयात 73.5% अनुपातिक आधार पर 1997-98 की तुलना में 113.8% अधिक हुआ। इससे 1994-95 में हुए आयात की मात्रा के किसी संदर्भ के बिना वर्धित आयात के तथ्य की स्पष्टत: पुष्टि होती है। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग को गम्भीर क्षति की आशंका की विद्यमानता पर विचार किया जाना है, अतः यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को अपने मामले की वर्तमान स्थिति की तुलना हाल के ही पूर्व समय में प्रबलन के साथ करके, घरेलू उद्योग को क्षति की आशंका को दर्शाना आवश्यक होगा। इसलिए मैं० केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स द्वारा उठाए गए मुद्दों में कोई आधार नहीं है।

(viii) मैं० केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स ने वर्धित आयात के संदर्भ में अच्युत मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि इस बारे में वैधानिक प्राक्षण खामोश है कि व्यापक रूप में आयात में वृद्धि किसे माना जाता है और 100 से 103 यूनिट की वृद्धि को व्यापक रूप में प्रतिपादित नहीं किया जा सकता है। यह निर्धारण करने हेतु कि क्या व्यापक रूप में आयात में वृद्धि हुई है या नहीं, इसके लिए वे केवल अधिक आयात अर्थात् आयात में वृद्धि, घरेलू मांग और घरेलू उत्पादन में कमी के कारण को ही वे विचारणीय मानने के लिए सुझाव देने की तैयार प्रतीत होते हैं। वर्धित आयात के संदर्भ में सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली 1997 के नियम 2 (सी), वर्धित मात्रा को आयात में वृद्धि चाहे सम्पूर्ण रूप में या घरेलू उत्पादक के सापेक्ष में, को शामिल करना पारिभाषित करता है। दो वाक्यांश 'सम्पूर्ण रूप से' या 'घरेलू उत्पादन के सापेक्ष' इसके सामिक्षण में प्रयुक्त किए गए हैं और साधारण कथन से इनके अर्थ निकल आते हैं ऐसोल्यूट टर्म में शब्द आयात में वृद्धि जैसे मात्रा/ इकाइयों की संख्या में वृद्धि को स्पष्ट रूप से संदर्भित करता है। 100 यूनिट से बढ़कर 103 यूनिट का आयात निःसन्देह रूप से ऐसोल्यूट टर्म में आयात में वृद्धि का मामला है। ऐसोल्यूट टर्म में आयात में वृद्धि हुई या नहीं, यह निर्धारण करने के लिए जैसा मैं० केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स द्वारा तकँ दिया गया है कि कानून में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, वास्तव में बिना किसी प्रतिबंध के आयात करने की अनुमति देने के परिप्रेक्ष्य में ऐसी कल्पना करना अव्यावहारिक होगा कि जितना आवश्यक है कोई उससे अधिक आयात करना चाहेगा अर्थात् अत्यधिक आयात से सूची तालिका ही बढ़ेगी। इसलिए कानून की अपेक्षा है कि ऐसोल्यूट टर्म में एवं घरेलू उत्पादन के सापेक्ष आयात पर विचार किया जाए। क्या मांग को पूरा करने के लिए आयातों की

आवश्यकता हुई है, इस प्रकार के आयात द्वारा हुई क्षति के निर्धारण के लिए संगत हो सकते हैं लेकिन यह वर्षित आयात के तथ्य का निर्धारण करने हेतु संगत नहीं है। वर्तमान मासले में जैसा कि सारणी 2 में दर्शाया गया है, आयात में ऐसोल्यूट टर्म में साथ ही साथ घरेलू उत्पादन के सापेक्ष में वृद्धि हुई है।

5. गंभीर क्षति की आशका :

(क) घरेलू उत्पादन :

घरेलू उत्पादन की वर्तमान स्थिति संबंधी विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण दर्शाता है कि 1996-97 से घरेलू उत्पादन 57466 मी.टन था। 1994-95 से 1996-97 की अवधि के दौरान घरेलू उत्पादन औसतन लगभग 59655 मी.टन प्रति वर्ष था जो कि 1997-98 में 69,281 मी.टन तक बढ़ गया लेकिन 1998-99 के प्रथम 9 महीनों में 48,703 मी.टन तक गिर गया। वार्षिक आधार पर 1998-99 के लिए घरेलू उत्पादन लगभग 64937 मी.टन हुआ। इस प्रकार घरेलू उत्पादन जिसमें कि 1997-98 में, 1994-97 के औसत उत्पादन से लगभग 16.1% की वृद्धि और 1996-97 से 20.6% की वृद्धि दर्ज की गयी। 1997-98 की तुलना में 1998-99 में उत्पादन में 6.89% की गिरावट दर्ज की गयी।

(ख) क्षमता उपयोगिता

(i) घरेलू उत्पादकों ने फिनाल उत्पादन की अपनी क्षमता में लगातार सुधार किया है। एवं ओ सी अपनी क्षमता, जो कि 1994-97 में 40,000 मी.टन प्रतिवर्ष थी, को 1997-99 में 45,000 मी.टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाया है। एवं सी एल ने अपनी क्षमता में 1994-95 में 20,000 मी.टन प्रतिवर्ष से 1995-96 में 24,000 मी.टन प्रतिवर्ष, 1996-98 में 26,500 मी.टन प्रतिवर्ष और 1998-99 में 30,000 मी.टन प्रतिवर्ष तक सुधार किया। इस प्रकार दोनों घरेलू उत्पादकों ने 1994-95 में अपनी संयुक्त क्षमता 60,000 मी.टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1998-99 में 75,000 मी.टन प्रतिवर्ष तक अर्थात् 25% की वृद्धि की, तथापि क्षमता उपयोगिता में 1997-98 के दौरान 96.89% से घटकर् 98-99 में 86.58% हो गयी अर्थात् 10.31% प्याइट की गिरावट हुई।

(ii) कुछ इच्छुक पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यांत्रिकाकर्त्ताओं में से एक ने सर्वोच्च क्षमता उपयोगिता और बिक्री मात्रा दर्शाया है जैसा कि कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। यह संदर्भ एवं ओ सी के प्रसग में दिखाया गया प्रतीत होता है। वास्तव में प्रेस ड्रस्ट ऑफ इण्डिया द्वारा प्रकाशित एवं ओ सी की दिनांक 4 अप्रैल, 1998 और 16 अप्रैल, 1999 की अधिकृत प्रेस रिलीज को मैं मित्तुई केमिकल्स द्वारा विशेष रूप से सदर्भित किया है। क्षमता उपयोगिता के संदर्भ में दिनांक 6 अप्रैल, 1998 की प्रेस रिलीज उल्लेख करती है कि क्षमता उपयोगिता पिछले वर्ष में 99% की तुलना में 94% थी। तथापि यह क्षमता उपयोगिता फिनाल संयंत्र की क्षमता उपयोगिता को संदर्भित नहीं करती, बल्कि एवं ओ सी, जो एक विविध उत्पादन, विविध संयंत्र वाला उच्चम है, की क्षमता उपयोगिता को पूर्ण रूप में संदर्भित करती है। पूर्व वर्ष में 2.69 लाख टन उत्पादन और 1.85 लाख टन के बिक्री मात्रा की तुलना में 1998-99 में एवं ओ सी, की कुल फिनाल उत्पादन क्षमता 45,000 मी.टन और क्षमता उपयोगिता 271 लाख टन का उत्पादन केवल फिनाल के उत्पादन और बिक्री के रूप में संदर्भित नहीं करता है, यथापि फिनाल के उत्पादन और बिक्री को इन आकड़ों में शामिल किया जा सकता है। इसलिए वर्तमान

जाँच के प्रयोजन हेतु यह तर्क जो केवल फिनाल के संबंध में है, असंगत है। घरेलू उद्योग के कार्यों की स्थिति के निर्धारण के प्रयोजन हेतु फिनाल संयंत्र के कार्य निष्पादन पर विचार करना आवश्यक है।

(iii) कुछ पक्षों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू मौंग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादकों की क्षमता उपयोगिता लगभग 86% पर स्थिर बनी हुई है और केवल घरेलू मौंग के लिए क्षमता उपयोगिता पर विचार करने के बजाए उत्पादन के सभी क्षेत्रों में क्षमता उपयोगिता पर विचार करने की आवश्यकता है। इस संबंध में यह महसूस किया जाता है कि केवल घरेलू मौंग के लिए क्षमता उपयोगिता पर विचार नहीं किया जा सकता, क्योंकि घरेलू उत्पादन की मौंग के साथ-साथ निर्यात उत्पादन के लिए भी उसी संयंत्र का प्रयोग होता है। तदनुसार घरेलू मौंग और निर्यात उत्पादन, दोनों के लिए क्षमता उपयोगिता पर विचार करना आवश्यक होगा। इस आधार पर घरेलू मौंग को पूरा करने के लिए 61,606 मी.टन और निर्यात के लिए 7,675 मी.टन को सम्मिलित करते हुए 1997-98 में कुल उत्पादन 69,281 मी.टन हुआ और 1998-99 (अप्रैल - दिसम्बर) में 48703 मी.टन का उत्पादन हुआ जिसमें घरेलू मौंग के लिए 48372 मी.टन और निर्यात के लिए 52 मी.टन शामिल हैं। इस प्रकार घरेलू उत्पादकों ने तर्ब 1997-98 में 96.89% और 1998-99 की प्रथम तीन तिमाहियों में 86.58% की क्षमता उपयोगिता प्राप्त की थी, इस प्रकार उन्हें क्षमता उपयोगिता में 10.31% प्लाइट की हानि उठानी पड़ी।

(ग) विक्री: -

घरेलू उत्पादकों ने 1994-95 में 51,538 मी.टन ($3172+57780-3448-5244-722=51538$) 1995-96 में 61490 मी.टन, 1996-97 में 56535 मी.टन, 1997-98 में 62390 मी.टन और अप्रैल - दिसम्बर, 1998 में 48372 मी.टन की कुल घरेलू विक्री की। 1997-98 की तुलना में, आनुपातिक आधार पर, 1998-99 (अप्रैल - दिसम्बर) में घरेलू उत्पादकों ने 3.38% अधिक बिक्री की। तथापि बिक्री में इस वृद्धि को कुल स्पष्ट खपत में वृद्धि को जो कि 1994-95 में 58,202 मी.टन, 1995-96 में 83242 मी.टन, 1996-97 में 76081 मी.टन, 1997-98 में 77742 मी.टन और अप्रैल - दिसम्बर, 1998 की अवधि में 73922 मी.टन थी, की पृष्ठभूमि में देखा जाना है। 1997-98 की तुलना में 1998-99 (अप्रैल - दिसम्बर) में स्पष्ट क्षपत में वृद्धि अनुपातिक आधार पर 25.1% थी जब कि घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री में वृद्धि केवल 3.38% थी। घरेलू उत्पादक केवल अपनी औसत बिक्री मूल्य में तीव्र कमी करने के कारण ही इस थोड़ी वृद्धि को प्राप्त कर सके जो कि जनवरी - मार्च, 1998 में 37 रु० प्रति किलोग्राम से घटाकर दिसम्बर, 1998 में 28/-रु० प्रति किलोग्राम कर दी गई थी।

(घ) मंडारण :

घरेलू उत्पादकों का अंतर्शेष मंडारण जो कि 1996-97 में 3248 मी.टन से घटकर 1997-98 में 2464 मी.टन तक आ गया था, वह 1997-98 की तुलना में दिसम्बर, 1998 के अंत तक बढ़कर 2743 मी.टन अर्थात् 10.2% तक बढ़ गया।

(ङ) सोजगार

घरेलू उत्पादकों ने प्रस्तुत किया है कि उनके प्रतिनाशाली, अनुमती और सहयोगी कर्मचारियों ने कम्पनियों की सेवाओं से इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं जिससे कि घरेलू उद्योग अपनी योग्यता एवं कुशलता के

मंडार में अपूरणीय क्षति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उन्हें नई नियुक्तियाँ करने में भी परेशानी हो रही है क्योंकि उन्हें क्षतिग्रस्त फिनाल उद्योग में विकास के अवसरों में कमी दिखाई देती है। इस संबंध में यह महसूस किया जाता है कि घरेलू उद्योगों के साथ जुड़े कर्मचारियों की संख्या लगभग पहले की तरह ही है।

(c) उत्पादकता

चूंकि घरेलू उद्योगों ने उत्पादन (1997-98 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 1998 में 8.69%) और क्षमता उपयोगिता (1997-98 की तुलना में अप्रैल-दिसम्बर 1998 में 10.31% प्लाइट तक) खोयी है, घरेलू उद्योगों में स्पष्ट रूप में उत्पादकता अर्थात् घरेलू उद्योग द्वारा नियुक्त किए गए प्रति कर्मचारी उत्पादन की मात्रा में कमी हुई है।

(d) लाभप्रद स्थिति

घरेलू उत्पादकों को अपने ग्राहकों को पूर्णतः आयात की ओर बढ़ाने से बचाने हेतु फिनाल के सूची मूल्य को कम करना पड़ा एवं विभिन्न अतिरिक्त छूट देनी पड़ी। औसतन उन्होंने मार्च 1998 में 37 रु. प्रति किलोग्राम से अपने बिकी मूल्य घटाकर दिसम्बर 98 में 28 रु. प्रति किलोग्राम अर्थात् सूची मूल्य में लगभग 24.3% की कमी कर दी। एवं सी एल की फिनाल (थोक) की कुल वसूली, जो कि अप्रैल 1998 के दौरान 35772 रु. प्रति मीटन थी वह दिसम्बर 1998 में घटकर 24934 रु. प्रति मीटन हो गई। एवं ओ सी के मामले में, उनकी आगस्त 1998 में कुल वसूली 32820 रु. प्रति मीटन से घटकर दिसम्बर 1998 में 24620 रु. प्रति मीटन हो गई। कुल वसूली में कमी ने घरेलू उद्योगों के लाभ पर गम्भीर प्रभाव ढाला है। एवं ओ सी और एवं सी एल दोनों को हानि होनी शुल्क हो गई है। एवं ओ सी के मामले में, उन्हें दिसम्बर 1998 में 1198 रु. प्रति मीटन और एवं सी एल के मामले में उन्हें 3298 रु. प्रति मीटन की हानि हुई थी। इससे दोनों कम्पनियों के शेयर मूल्यों में निशाजनक प्रभाव पड़ा था। अप्रैल 1998 में एवं ओ सी का शेयर मूल्य 18 रु. प्रति शेयर से गिरकर दिसम्बर 1998 में 9 रु. प्रति शेयर रह गया तथा एवं सी एल का शेयर मूल्य उसी अवधि में 23.50 रु. से गिरकर 18.70 रु. प्रति शेयर रह गया।

(ii) मैं० केसर पेट्रो प्रोडक्ट्स ने दावा किया है कि कम से कम घरेलू उत्पादकों ने लाभ प्राप्त किया और चूंकि उन्हें पहले लाभ प्राप्त हुआ है इसलिए ऐसा होना मुश्किल है कि उन्हें कोई क्षति हुई है। इस संबंध में यह महसूस किया जाता है कि 28 रु. प्रति किलोग्राम की सूची मूल्य के साथ घरेलू उत्पादकों एवं ओ सी को 1198 रु. प्रति मीटन और एवं सी एल को 3298 रु. प्रति मीटन की हानि हुई है। इसलिए घरेलू उत्पादक लाभ प्राप्त नहीं कर सके जब तक सूची मूल्य ($28+1.198$) कम से कम था अर्थात् एवं ओ सी के मामले में रु. 29.20 प्रति किलोग्राम और ($28+3.298$) अर्थात् एवं सी एल के मामले में रु. 31.30 प्रति किलोग्राम के न्यूनतम पर था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने छूट आदि का एक ही स्तर बनाए रखा। तथापि आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से देखा गया है कि अक्टूबर 98 और नवम्बर 98 में एवं ओ सी और एवं सी एल दोनों का सूची मूल्य 29 रु. प्रति किलोग्राम था। इसलिए मैं० केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स का दावा प्रश्नगत तथ्यों से उत्पन्न प्रतीत नहीं होता। जहाँ तक पिछले लाभों के परिप्रेक्ष्य में क्षति से सबधित उनके तक का प्रश्न है, यह महसूस किया जाता है कि क्षति के निर्धारण के लिए विभिन्न कारकों का वस्तुपरक मूल्यांकन किया जाना है। यदि ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग कुल मिलाकर महत्वपूर्ण क्षति का सामना कर रहे हैं तो गम्भीर क्षति के

अस्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है। यह भी ध्यान में रखा जा सकता है कि वर्तमान जांच गम्भीर क्षति की आशंका के अस्तित्व के निर्धारण से संबंधित है, अर्थात् एक स्थिति जहाँ गम्भीर क्षति स्पष्ट है। इसलिए लाभ की हानि में बदलने को उपरोक्त पृष्ठभूमि में देखा जाना है।

(ज) गम्भीर क्षति की आशंका

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 बी की उपधारा 8(डी) पारिभाषित करती है कि गम्भीर क्षति की आशंका का अर्थ है, गम्भीर क्षति का स्पष्ट एवं आसन्न खतरा। इस धारा की उपधारा 6 (सी) पारिभाषित करती है कि गम्भीर क्षति का अर्थ है कि ऐसी क्षति जो घरेलू उद्योग की स्थिति में कुल मिलाकर महत्वपूर्ण क्षति पहुँचाए। विभिन्न मानदण्डों जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 1998-99 की प्रथम तीन तिमाहियों में घरेलू उद्योगों को गम्भीर रूप से हताश कार्य संचालन का सामना करना पड़ा है। 1997-98 की तुलना में उत्पादन, क्षमता, उपयोगिता, बिक्री से वसूली, लाभ और उत्पादकता के कारण इन्हें मुक्तसान हुआ और इनकी वस्तु सूची बढ़ती चली गयी। इसने बिक्री में थोड़ी वृद्धि प्राप्त की परन्तु वह स्पष्ट खपत में वृद्धि की तुलना में बहुत ही कम थी और वह भी बिक्री मूल्य में तीव्र गिरावट की कीमत पर थी। इस प्रकार घरेलू उद्योगों को गम्भीर क्षति स्पष्ट रूप से संकेत है। इसलिए यह महसूस किया जाता है कि घरेलू उद्योग गम्भीर क्षति की आशंका से पीड़ित हैं।

6. क्षति का कारण

(क) मांग पूर्ति में अन्तर

(i) कुछ पक्षों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योगों को क्षति का कारण, बढ़े हुए आयात नहीं थे क्योंकि आयात की आवश्यकता घरेलू मांग और घरेलू पूर्ति के अस्तर को पूरा करने के लिए हुई थी। यहाँ पर शुरू में ही यह बताना उमित होगा कि एच सी एल जो कि भारत में फिनाल का उत्पादन करने वाली सर्वप्रथम ईकाई थी की स्थापना सन् 1968 में की गई थी तथा उसकी फिनाल उत्पादन की क्षमता 10000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी। सन् 1979 में उसने अपनी क्षमता 20000 मी.टन करने के लिए अनुरोध किया था किन्तु तत्कालीन कानूनों के तहत कम्पनी के अनुरोध को यह महसूस करते हुए सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया कि भारतीय बाजार में एच.सी.एल की प्रमाणी उपस्थिति है फिर भी घरेलू उद्योग जिसकी फिनाल उत्पादन क्षमता 1994-95 में 60,000 मी.टन प्रतिवर्ष थी, कमशः बढ़ते हुए 1995-96 में 64,000 मी.टन प्रति वर्ष, 1996-97 में 66,500 मी.टन प्रति वर्ष, 1997-98 में 71,500 मी.टन प्रति वर्ष तथा वर्तमान 1998-99 में बढ़कर 75,000 प्रति मी.टन हो गई। घरेलू बाजार में कुल स्पष्ट खपत (अर्थात् घरेलू बिक्री + आयात) 1994-95 में 58,202 मी.टन से बढ़कर 1995-96 में 83242 मी.टन हो गई। उसके बाद 1998-99 की प्रथम तीन तिमाहियों में 72,922 मी.टन पुनः बढ़ने के पहले घटकर 1996-97 में 76,081 मी.टन तथा 1997-98 में 77,742 मी.टन हो गई। औसतन प्रत्यक्ष घरेलू उपभोग पिछले तीन वर्षों में अर्थात् 1995-96 से 1997-98 में 79,022 मी.टन प्रति वर्ष रहा। इन प्रत्येक वर्षों के प्रत्यक्ष उपभोग आंकड़ों की अलग-अलग तुलना करने पर इस अवधि में औसतन प्रत्यक्ष उपभोग अथवा इसके पूर्व वर्ष के औसतन प्रत्यक्ष उपभोग से यह दिखता है कि इस अवधि में कुल घरेलू मांग 80,000 मी.टन प्रति वर्ष के आसपास स्थिर रही। वर्ष 1995-96 में कुल स्पष्ट घरेलू उपभोग में एकटम बढ़ोतरी हुई पर उसके बाद प्रत्यक्ष घरेलू उपभोग में 1996-97 तथा 1997-98 में गिरावट आकर 76,000-78000 मी.टन प्रति

वर्ष रह गया। कुछ पार्टीयों द्वारा यह दावा किया गया है कि वर्तमान में घरेलू मांग 1,00,000 मी.टन प्रति वर्ष है जो कि पिछले तीन वर्षों के औसतन उपभोग का लगभग 25% अधिक बनता है। 1998-99 में फिनाल की मांग में बढ़त के बारे में किसी भी पार्टी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, न ही किसी पार्टी द्वारा वर्तमान वर्ष में कुल स्पष्ट उपभोग में इस 25% बढ़ोत्तरी के बारे में कोई स्पष्टीकरण ही दिया गया है जो कि पर्याप्त बढ़त है और इसे बिना किसी तर्कसंगत आधार के स्वीकार करना कठिन प्रतीत होता है। अतः आबू वर्ष का कुल प्रत्यक्ष उपभोग घरेलू बाजार में मांग का सकेत नहीं देता है कि घरेलू बाजार में फिनाल की वास्तविक मांग है। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले कुछ वर्षों में घरेलू मांग 80,000 मी.टन के कम में रही है तथा 1998-99 की प्रथम तीन तिमाहियों में सस्ते मूल्यों का लाभ उठाने के लिए आयात में वृद्धि हुई, इस समावना से इकार नहीं किया जा सकता है।

(ii) जैसा कि ऊपर बताया गया है कि घरेलू उत्पादकों ने अपनी उत्पादन क्षमता कमशः 1994-95 में 60,000 मी.टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1998-99 में 75,000 मी.टन प्रति वर्ष कर दी, अर्थात् 1994-95 से 1998-99 में 25% का सुधार हुआ, तथापि वे अपनी उत्पादन क्षमता को पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला सके तथा अप्रैल-दिसम्बर 1998 में छह कठिनाई से केवल 48,703 मी.टन का उत्पादन कर सके। पहले उत्पादकों ने 1995-96 में लगभग 99.56% और 1997-98 में 98.89% क्षमता उपयोगिता प्राप्त की। इतनी ही क्षमता उपयोगिता वे 1998-99 में भी प्राप्त कर सकते थे। इस प्रकार आनुपातिक आधार पर इस अवधि के दौरान वे लगभग 56,250 मी.टन (75,000x0.75) का उत्पादन कर सकते थे। इस प्रकार घरेलू उत्पादकों को उत्पादन में 7,545 मी.टन की हाँचि हुई। दिसम्बर 1998 के अंत तक उनके पास भी 2743 मी.टन का मंडारण जमा हो गया। मैं नेवेली लिनाइट कारपोरेशन भी अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं कर सका और उनके पास पर्याप्त माल एकत्र ही गया। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि जो भी आयात हुआ वह घरेलू मांग को पूरा करने की घरेलू उत्पादकों की अक्षमता के कारण हुआ। इसके विपरीत सस्ते आयात ने घरेलू उत्पादकों को अपनी पूरी क्षमता उपयोगिता प्राप्त करने से रोका और इससे मूल्यों में कमी हुई एवं मंडारण बढ़ा।

(ए) संयंत्र बंद करना :

यह तर्क दिया गया है कि 1998-99 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान एवं सी एल ने 15 दिनों की अवधि के लिए एवं एच ओ सी ने 40 दिनों के लिए अपने संयंत्र बंद कर दिए, इसलिए वर्ष के 15% समय में वे बाजार में नहीं थे, जिस अवधि के दौरान घरेलू मांग फिनाल के आयात द्वारा पूरी की गई। इस सबव्य से यह महसूस किया जाता है कि यह एक सच्चाई है कि एच ओ सी ने 1.4.98 से 9.5.98 एवं एच सी एल ने 1998-99 के शुरू में 22.4.1998 से 8.5.98 तक अपने संयंत्र बंद रखे। इसलिए दोनों इकाइयों द्वारा संयंत्र बंद करने की कुल अवधि एच ओ सी के मामले में 39 दिन और एच सी एल के मामले में 17 दिन थी, जो कि वर्ष के 15% समय को नहीं दर्शाता है। दोनों कम्पनियों की संयंत्र बंद करने की कुछ अवधि परस्पर आछादित हो गयी, तथापि किसी रसायन संयंत्र के लिए संयंत्र बंद होना एक सामान्य बात है और इन्हें सामान्य संयंत्र क्षमता के विर्धारण हेतु ध्यान में रखा जाता है। 15 दिनों के लिए एच सी एल के संयंत्र का बंद होना अपनी क्षमता में वृद्धि करने तथा उसके पश्चात अपनी आपूर्ति में सुधार करने के लिए थी। संयंत्र बंद होने से पूर्व एच ओ सी ने 2180 मी.टन फिनाल का भडारण कर लिया था। इसके अतिरिक्त संयंत्र बंद होने की अवधि के दौरान एवं सी एल ने उपभोक्ताओं को पर्याप्त आपूर्ति बरकरार रखने हेतु उच्च मूल्य वाले व्युत्पन्नों के उत्पादन में कमी करके फिनाल के कैप्टिव उपभोग में कमी कर दी। जुलाई - सितम्बर 1998 की तिमाही में, संयंत्र बंद होने के बाद

घरेलू उत्पादकों ने 19751 मी.टन फिनाल को उत्पादन किया जो कि आनुपातिक आधार पर लगभग 79000 मी.टन प्रतिवर्ष होता है। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए 1998-99 की प्रथम तीन तिमाहियों में भारत में फिनाल आयात के आंकड़ों से यह भी देखा गया है कि इस अवधि के दौरान फिनाल की केवल तीन परेषण आयात की गई। दक्षिण अफ्रीका से बाउ फोर्ट्स जहाज में प्रथम परेषण 1,105.152 मी.टन की आयात की गयी जो कि 3 अप्रैल, 1998 को पहुँची तथा जापान से लोडस्टार स्प्रिट जहाज में द्वितीय परेषण 1045.499 मी.टन की आयी जो कि 9 अप्रैल 1998 को पहुँची और दक्षिण अफ्रीका से बो स्प्रिंग जहाज में तृतीय परेषण 1,262.846 मी.टन की आयी जो कि 8 मई, 1998 को पहुँची। कुल 3413 मी.टन की यह परेषण अप्रैल-दिसम्बर में आयातित 24550 मी.टन का 15% भी नहीं है, यदि पूरे 1998-99 के आयात को अलग भी कर दें। उपरोक्त घर्षणों की रोशनी में यह प्रतीत नहीं होता कि 1998-99 के शुरू में कुछ अवधि हेतु एक सी एल और एक ओ सी के संयंत्र बद्द होने से 1998-99 के प्रथम तीन तिमाहियों में आयात में वृद्धि पर कोई प्रभाव पड़ा।

(ग) निर्यात की हानि :

यह भी दावा किया गया है कि घरेलू उत्थोग की परेशानी का कारण इसके निर्यात बाजार का खोना है जो 1997-98 में 7675 मी.टन की तुलना में 1998-99 में घटकर 52 मी.टन हो गया, जो कि फिनाल का आयात। इस संबंध में यह महसूस किया जाता है कि अपने आवेदन में घरेलू उत्पादकों ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि माल भाड़ा संबंधी असुविधा के बावजूद भारतीय विनिर्माताओं को 1997-98 में विशेष होकर कम प्राप्ति पर फिनाल निर्यात के लिए बाध्य होना पड़ा। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि घरेलू उपभोग और निर्यात बाजार दोनों के लिए फिनाल के उत्पादन का रास्ता एक ही है। घरेलू उत्थोग जो कि घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा हेतु योग्य नहीं था, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा हेतु उससे आशा नहीं की जा सकती थी, वह भी उन परिस्थितियों में जब घरेलू आपूर्ति ही, घरेलू उत्थोग और निर्यात हेतु मुख्य बाजार थी और निर्यात इसके बाजार के केवल एक अंश भर था। इसलिए वर्धित आयात से घरेलू उत्पादकों को हुई क्षति ने घरेलू उत्पादकों को भी निर्यात प्रदर्शन पर अपना प्रभाव डाला। फिर भी डीएल निर्यात योजना के अधीन 1998-99 में अप्रैल - दिसम्बर 1998 के दौरान घरेलू उत्पादकों ने 3137 मी.टन फिनाल की आपूर्ति की, जिसे कि भारतीय तट से वस्तुओं के जाये बिना ही निर्यात के रूप में माना जाता है।

(घ) आयात छारा बाजार शेयर को अपने अधिकार में लेना

(i) घरेलू उत्पादकों के पास 1994-95 में कुल स्पष्ट खपत में 51,538 मी.टन अर्थात् 88.52% का बाजार शेयर था। 1997-98 में 80.25% तक वृद्धि होने से पूर्व 1995-96 में उनका बाजार शेयर 73.86% तक एवं 1996-97 में 74.3% तक गिर गया। तथापि 1998-99 की प्रथम तीन तिमाहियों में घरेलू उत्पादकों ने अपना बाजार शेयर खोया जो कि केवल 66.3% रह गया। स्पष्ट खपत में आयात का शेयर 1998-99 के प्रथम तीन तिमाहियों में 33.7% तक बढ़ने से पहले 1994-95 में 11.48% से बढ़कर 1995-96 में 26.14% तक बढ़ा जो कि 1996-97 में 25.7% तक और 1997-98 में 19.75% तक था। तुलनात्मक आधार पर आयात का शेयर 1997-98 से 1998-99 (अप्रैल - दिसम्बर) में 70.6% तक बढ़ा। जीवे की सारणी में 1994-95 से आगे घरेलू उत्पादकों के बाजार शेयर दर्शाए गए हैं।

सारणी -3

वर्ष	ओ. बी. मी. टन	उत्पादन मी. टन	सी.बी. मी.टन	नियांत मी.टन	घरेलू बिक्री (2)+(3)- (4)-(5) मी.टन	कुल स्पष्ट से घरेलू बिक्री स्पष्ट खपत का शेयर मी.टन	स्पष्ट खपत का शेयर मी.टन	स्पष्ट खपत का शेयर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1994-95	3172	57780	3448	5966	51538	58202	88.52	11.48
1995-96	3448	63719	3323	2354	61490	83242	73.86	26.14
1996-97	3323	57466	3248	1006	56535	76081	74.3	25.7
1997-98	3248	69281	2464	7675	62390	77742	80.25	19.75
1998-99	2464	48703	2743	52	48372	72922	66.33	33.67
(अप्रैल-दिसम्बर)								

(ii) 1997-98 में कुल (स्पष्ट खपत 77742 मी. टन थी जो कि अनुपातिक आधार पर 1998-99 के प्रथम नौ महीनों (अप्रैल - दिसम्बर) में 72922 मी. टन अर्थात् 25.1% तक बढ़ी । फिर भी घरेलू बिक्री उसी गति के साथ नहीं बढ़ सकी । इस अवधि के दौरान घरेलू उत्पादकों को 58537 मी. टन ($62390/12 \times 9 \times 125.1\%$) की बिक्री प्राप्त करनी चाहिए थी, जब कि वे घरेलू बाजार में केवल 48372 मी. टन फिनाल की ही बिक्री कर सके (जिसमें एच.ओ.सी. द्वारा डीम्ड नियांत के आधार पर आपूर्ति किया गया 3137 मी.टन शामिल है) । इस प्रकार घरेलू उत्पादकों को 10165 मी.टन की बिक्री की हासि हुई, जिसे वर्धित आयात ने अपने अधिकार में कर लिया था, जिसने कि स्पष्ट खपत में 25.1% की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 10184 मी. टन { $24550 - (15312/12 \times 9 \times 125.1\%)$ } के अतिरिक्त बाजार पर कर्जा कर लिया । इस अवधि के दौरान आनुपातिक आधार पर मात्रा के अनुसार आयात में वृद्धि 13086 मी. टन थी ।

(iii) घरेलू उत्पादकों ने प्रस्तुत किया है कि घरेलू मूल्यों के फिनाल की उत्तराई के समय की अनुमानित लागत के साथ समानता रखने की दृष्टि से उन्हें मूल्यों में विभिन्न समायोजन करने पड़े थे । फिनाल के सूची मूल्य कम करने के अतिरिक्त घरेलू उत्पादकों को अपने ग्राहकों को आयात की ओर पूर्णतः मुड़ने से रोकने के लिए विभिन्न अतिरिक्त छूट भी देनी पड़ी थी । यहाँ यह नोट करना संगत होगा कि मध्य 1994 से मार्च, 1998 के दौरान के फिनाल के सी.आई.एफ.(भारतीय) मूल्य मार्फ, 1998 के बाद देखे गये मूल्यों से प्रतिरूप में विभिन्नता दर्शाते हैं जैसा कि नीचे सारणी 4 में दर्शाया गया है ।

सारणी - 4

मास	यू.एस. लोटों के सी.आई.एफ	यूरोप लोटों के के सी.आई.एफ	एशिया प्रशान्त सी.आई.एफ	सी.आई.एफ भारत
जुलाई 94	780	780		540
नवम्बर 94	780	820		750
मई 95	790	855		780
जुलाई 95	790	870		685
अक्टूबर 95	850	920		530
मार्च 96	814	945		530
मई 96	792	820		640
अगस्त 96	726	670		710
नवम्बर 96	605	630		710
मार्च 97	583	603		720
मई 97	720	760	710	720
जून 97	730	795	685	700
सितम्बर 97	730	810	665	680
नवम्बर 97	790	860	700	680
मार्च 98	754	885	700	670
जून 98	732	760	600	560
सितम्बर 98	666	610	555	440
अक्टूबर 98	545	570	470	420
नवम्बर 98	523	543	445	405
दिसम्बर 98	422	515	440	395

ऊपर सारणी 4 में उपलब्ध कराई गयी सूचना से यह स्पष्ट है कि सी.आई.एफ. भारतीय मूल्य नवम्बर- 94, मई, 95 में लगभग 750-780 डालर के स्तर से मार्च, 96 में 530 डालर तक गिरने प्रारंभ हुए और उसके बाद मई, 1997 में 720 डालर तक बढ़ गए। सी.आई.एफ. भारतीय मूल्य जून, 97 में 700 डालर से धीरे-धीरे सितम्बर/नवम्बर, 97 में 680 डालर तक और मार्च, 98 में 670 डालर तक गिरने शुरू हुए। तथापि मार्च, 98 के पश्चात जून, 98 में 560 डालर, सितम्बर, 98 में 440 डालर और नवम्बर/दिसम्बर, 98 में लगभग 400 डालर के स्तर तक सी.आई.एफ. भारत मूल्य तेजी से गिरे। कम होते आयत मूल्यों ने घरेलू उद्योग पर अपना प्रभाव डाला। अप्रैल - मई, 1998 में संयंत्र बंद होने के पश्चात घरेलू उत्पादकों ने अपनी बड़ी हुई क्षमता के साथ जुलाई - सितम्बर, 98 की तिमाही से 19751 मी. टन का उत्पादन दर्ज किया, परन्तु उन्हें अक्टूबर, 98 में 6138 मी. टन, नवम्बर, 98 में 6080 मी. टन और दिसम्बर, 98 में 5167 मी.टन उत्पादन कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

(iv) मैं० भित्तुई केमिकल्स इन्ड्यूज़िट, ने प्रस्तुत किया है कि दिसम्बर, 1998 में किए गए तीन पोत लदान 395 अमरीकी डालर प्रति मी. टन से अधिक मूल्यों पर किए गए थे जैसा कि घरेलू उत्पादकों द्वारा दावा किया गया है जो कि एक अपवाद है और सामान्य विचार हेतु इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। दिसम्बर, 98 में आयात मूल्यों के बारे में कोडला सीमा शुल्क गृह ने पुष्टि की है कि अप्रैल, 1998 में 617-675 अमरीकी डालर प्रति मी. टन की तुलना में दिसम्बर, 98 में आयात 408-430 अमरीकी डालर प्रति मी. टन की दरों पर पहुँच गया। भारी मात्रा में फिनाल को अधिकांश आयात कोडला पतण से हुआ। सीमा शुल्क गृह कोडला से प्राप्त सूचना से यह महसूस किया जाता है कि 1998-99 की प्रथम तिमाही में जब फिनाल के सी.आई.एफ. मूल्य 530-675 अमरीकी डालर प्रति मी. टन थे, आयात की मात्रा 3989.505 मी. टन थीं जो कि अप्रैल - मई, 1998 में दोनों घरेलू उत्पादकों द्वारा संयंत्र बंद कर दिए जाने के बावजूद आनुपातिक आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा सा अधिक था। सी.आई.एफ. आयात मूल्यों के 480-555 अमरीकी डालर प्रति मी. टन तक गिरते ही दूसरी तिमाही में आयात में 8888.534 मी. टन तक दुगना हो गया एवं तीसरी तिमाही में सी.आई.एफ. मूल्यों के 408-475 अमरीकी डालर प्रति मी. टन तक गिरते ही आयात में 9152.375 मी. टन तक की वृद्धि हुई। इसलिए इस अवधि के दौरान भारत में आयात होने वाले फिनाल के सी.आई.एफ. आयात मूल्यों में भारी गिरावट रही है जो कि इस अवधि के दौरान आयात में वृद्धि होने का सुख्य कारण था। कम कीमतों पर होने वाले वर्धित आयात ने घरेलू उत्पादकों को अपना उत्पादन एवं अपने सूची मूल्य मार्फ, 98 में 37 रु० प्रति किलो से जून, 98 में 36.5 रु० प्रति किलो, सितम्बर, 98 में (एच.सी.एल./एच.ओ.सी.) 31.5/33 रु० प्रति किलोग्राम, अक्टूबर - नवम्बर, 1998 में 29 रु० प्रति किलोग्राम और दिसम्बर, 98 में 28 रु० प्रति किलोग्राम तक हानि होने के बावजूद कम करने के लिए बाध्य कर दिया।

(v) कुछ पक्षों ने दावा किया है कि रसायन उद्योग बड़े पैमाने पर विश्वव्यापी मंटी के दौर से गुजर रहा है और भारतीय रसायन उद्योगों ने भी इस असर को महसूस किया है। इसलिए व्यापार में और मूल्यों में कमी भारत के लिए आश्चर्यजनक नहीं है। इस तर्क में भी कोई तथ्य दिखाई नहीं देता क्योंकि 1998-99 की प्रथम तीन तिमाहियों में एक ओर आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर घरेलू बाजार की स्पष्ट खपत में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस प्रकार घरेलू फिनाल उद्योग की यह गिरावाजनक दशा घरेलू मौंग की कमी के कारण या सामान्य मंटी, यदि कोई हो, अलिंक यह कम कीमतों पर बढ़े हुए आयात के कारण है।

(7) अन्य मुद्दे

(क) फिनाल की डिपिंग

मैं० केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स ने प्रस्तुत किया है कि आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से यह प्रमाणित होता है कि चूंकि भारतीय बाजार में फिनाल की स्पष्ट डिपिंग है, जिससे महो निदेशक इस विषय में आगे की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं हैं। इसके समर्थन में उन्होंने याचिका में से उद्धृत किया है कि “सी.आई.एफ. भारत फिनाल की कीमतें जो कि विश्व के अन्य भागों की कीमतों के बराबर होती थी, वे विश्व के अन्य भागों जैसे कि अमरीका, यूरोप तथा सुदूर पूर्व के मुकाबले अत्यधिक तेजी से गिरी हैं,” और यह कि जब सितम्बर, 1998 के अस्त तक यू.एस.जी.सी. की कीमतों में गिरावट 110 अमरीकी डालर प्रति मी. टन तक थी तब सी.आई.एफ. भारत की कीमतें और भी अधिक तेजी से 275 अमरीकी डालर प्रति मी. टन की दर से गिरी। इस विषय में यह पाया गया है कि अन्य बाजारों की तुलना में भारतीय बाजार के लिए कम कीमतें अपने आप में भारत के बाजारों में

फिनाल उम्म्य करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि किसी उत्पाद को तभी उम्म्य किया हुआ माना जाता है, जब इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर इसे किसी अन्य देश के व्यापिज्य में प्रवेश कराया जाए, जब एक देश से दूसरे देश को निर्यात किए गए उत्पाद का निर्यात मूल्य, एक समान उत्पाद के लिए सामान्य रूप से व्यापार में जब निर्यातक देश में उपभोग के लिए नियत किया गया हो, तुलनात्मक क्षमता से कम हो। किसी भी पक्ष द्वारा सामान्य मूल्य के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है और यह सूचना भी नहीं दी गयी है कि घरेलू उद्योग को किसी स्त्रोत से किसी प्रकार के उम्म्यिंग द्वारा किसी भी प्रकार की क्षति हुई है, इसलिए मैसर्स केसर पेट्रोप्रोडक्ट का दावा अप्रमाणित है और विचारणीय नहीं है।

(ख) फिनाल की कैप्टिव खपत :

यह तर्क दिया गया है कि आवेदक फिनाल का कुछ सीमा तक कैप्टिव उपभोग भी करते हैं उनके पास उपलब्ध सुविधाएँ व्यापार बाजार के पास प्राप्त नहीं हैं और देश की मांग को पूरा करने के लिए आवेदकों की क्षमताओं से उसे अलग कर देना चाहिए। यह तर्क यहाँ तक गलत है कि यदि घरेलू मांग में घरेलू उत्पादकों की कैप्टिव आवश्यकता को सम्मिलित कर लिया जाए तो आवेदकों की उस सीमा तक सुविधाएँ विवाराधीन में से अलग नहीं की जा सकती। इस समस्त जौच में आवेदकों के कैप्टिव उपभोग को सम्मिलित करते हुए घरेलू मांग को लिया गया है, इसलिए इस तर्क में कोई दम नहीं है।

(ग) संयुक्त उत्पाद मूल्यांकन :

यह तर्क दिया गया है कि फिनाल और एसिटोन संयुक्त उत्पाद हैं, इसलिए एसिटोन की स्थिति का मूल्यांकन किए बाहर केवल फिनाल के संबंध में घरेलू उद्योग को हानि का मूल्यांकन करना ठीक नहीं होगा। इस विषय में यह महसूस किया गया है कि दोनों घरेलू उत्पादक सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (जी ए ए पी) के अनुसार अपने रिकार्ड को रखते हैं और संयुक्त उत्पादों के लिए फिनाल की क्षति का मूल्यांकन जी ए ए पी के अनुसार किया गया है। इसलिए एसिटोन के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति का निर्धारण वर्तमान जौच के लिए संगत नहीं है।

(घ) घरेलू उत्पादकों का एकाधिकार/ युगल अधिकार :

(i) कुछ पक्षों ने तर्क दिया है कि फिनाल के घरेलू उत्पादकों ने एकाधिकार स्थिति का लाभ उठाया है क्योंकि फिनाल के घरेलू उपभोग का 91% उत्पादन उनका है तथा शिकायतकर्ता की वर्तमान शिकायत भारतीय बाजार में युगल अधिकार को प्राप्त करने और बाहर रखने के लिए है, जिससे वे भारतीय बाजार का शोषण जारी रख सके। इस विषय में यह महसूस किया जाता है कि किसी भी प्रकार का एकाधिकार स्थितः गैरकानूनी नहीं समझा जा सकता, लेकिन एकाधिकारिकता अथवा प्रतिबन्धित व्यापार व्यवहार और उनसे प्राप्त लाभों के संदर्भ में औद्योगिक विवरण की आवश्यकता है। फिनाल के तीन घरेलू उत्पादक हैं, एवं सी एल, एवं ओ सी तथा मैसर्स नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड। जहाँ एवं सी एल निजी क्षेत्र में हैं, शेष दोनों अर्थात् एवं ओ सी और मैसर्स नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड, सार्वजनिक क्षेत्र के हैं, जो फिनाल उत्पाद क्षमता के 50% से अधिक का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा फिनाल का आयात युले सामान्य लाइसेंस के अधीन है। लगभग कुल स्पष्ट उपभोग का एक तिहाई हिस्सा आयात द्वारा पूरा किया गया है। आवेदकों द्वारा फिनाल के आयात पर

प्रतिबंध लगाने का अनुरोध नहीं किया गया है, बल्कि कानून के अनुसार फिनाल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए अनुरोध किया गया है, ताकि वे अपने आपको फिनाल के वर्धित आयात से उत्पन्न नई प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के साथ समायोजन करने में वे समर्थ हो सकें। फिनाल की घरेलू उपलब्धता को सुभिशिक्षित करके घरेलू फिनाल उद्योग ने निम्न क्रम उद्योगों के समूह को बढ़ाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया है। एच सी एल ने फिनाल के विभिन्न उपयोगों जैसे कि प्लाईवुड में प्रयोग किए जाने वाले फिनाल फारमलडिहाइड रेसिस्ट, लेसिनेट्स फारमलडिहाइड रेसिस्ट तथा पी एफ मोल्डिंग पाउडर, सेलिसिलिक एसिल तथा औषधीय प्रयोग के लिए रेसिन और पैरासिटामोल, एग्रो कैमिकल्स में प्रयोग के लिए 2, 4-डी (हरबिसाइड) तथा चमड़ा उद्योग में प्रयोग के लिए सिर्फीटिक ट्रेनिंग एजेंट्स आदि को बढ़ाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इससे निम्न क्रम उद्योगों के विकास को गति मिली है और क्योंकि भारतीय उद्योग में मांग में वृद्धि हुई, स्टेट-आफ-दी-आर्ट तकनीक का प्रयोग करके एच सी एल ने 1988 में उत्पादन शुरू किया। तब से एच सी और एच सी एल ने निम्न क्रम उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति की है जिनमें से बहुत सी निर्यातोमुखी हैं और एच सी ने उनको अच्छी मात्रा में डीस्ट्रिब्युटरी निर्यात आधार पर फिनाल की बिक्री की। यहाँ पर यह ज कहना भी सही नहीं होगा कि यह स्थिति केवल भारत के लिए ही असामान्य नहीं है। भारत को फिनाल के वर्तमान बड़े आपूर्तिकर्ता जैसे दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया दोनों के पास केवल एक-एक संयंत्र हैं तथा जापान से तीन उद्योग समूह जापान की क्षमता के 70% पर अपना नियन्त्रण रखते हैं।

(ii) कुछ पक्षों ने घरेलू उद्योगों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने घरेलू बाजार का शोषण किया है। सीमा शुल्कों में अत्यधिक गिरावट के बावजूद आवेदकों के बिक्री मूल्य लगभग अपरिवर्तित रहे, कच्चे माल की कीमतों में कभी ग्राहकों तक नहीं पहुँचाई गई तथा उनके बिक्री मूल्य आयात मूल्यों के आधार पर नहीं थे। इस संबंध में घरेलू उत्पादकों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर यह महसूस किया गया है कि जुलाई, 1994 से दिसम्बर 1998 के दौरान आयातित फिनाल की उत्तराई के समय की लागत तथा एच सी एल और एच सी के सूची मूल्य उस प्रकार थे जैसा सारणी - 5 में नीचे दिया गया है :-

सारणी- 5

अवधि	आयातित फिनाल की उत्तराई के समय की लागत	सूची मूल्य - मूल- ई एक्स कार्य रु० प्रति किलो (थोक)	एच सी एल	एच सी एल
जुलाई, 94	28687	29	27	
नवम्बर, 94	39844	32	32	
मई, 95	35569	34	34	
जुलाई, 95	31327	34	34	
अक्टूबर, 95	26981	32	32	
मार्च, 96	28121	29	29	
मई, 96	31663	31	33	
अगस्त, 96	34588	35	35	

नवम्बर, ९६	34588	38	38
मार्च, ९७	33825	36.5	36.5
मई, ९७	33616	36.5	36.5
सितम्बर, ९७	32298	35.5	35
नवम्बर, ९७	34037	35	35
मार्च, ९८	35340	37	37
जून, ९८	33705	36.5	36.5
सितम्बर, ९८	26346	31.5	33
अक्टूबर, ९८	25376	29	29
नवम्बर, ९८	24205	29	29
दिसम्बर, ९८	23648	28	28

उपरोक्त लालिका की सूचना से यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि घरेलू कीमतें अपरिवर्तित रहीं अथवा घरेलू उत्पादकों ने कीमतें कम नहीं की अथवा उन्होंने आयातित फिनाल की उत्तराई के समय की लागत से समानता नहीं की, सही नहीं है। घरेलू कीमतें ने आयातित फिनाल की उत्तराई के समय की लागत की रुक्कान का अनुसरण किया है। अतः यह आरोप, जिसके समर्थन में कोई लक्ष्य नहीं है, अस्वीकार किया जाता है।

(iii) यह भी आरोप लगाया गया है कि कांडला तट पर तूफान के समय जब आयात नहीं हो सकता था, घरेलू उत्पादकों ने अत्याधिक कीमतें बढ़ा दी थी। इस विषय में यह नहसूस किया जाता है कि घरेलू उत्पादकों ने स्पष्ट किया है कि जब फिनाल भी थोक में कलकत्ता, बेंगलुर, गोवा, मैगलूर, तटों से आयात किया जा सकता था, कीमतों में 40/- लाख प्रति किलो तक वृद्धि का कारण कांडला पत्तन का बन्द होना ही नहीं था। वास्तव में फिनाल उपमोक्ता जो समान्यतया फिनाल का आयात कांडला तट से करते हैं, उन्हें वहाँ से उत्पाद की प्राप्ति नहीं हुई और उन्हें खुले बाजार से क्रय करना प्रयत्न जिसने मांग की बढ़ा दिया, जिसके कारण कीमतों में वृद्धि हुई। शुल्क में यह लगा था कि कांडला तट की अस्त्यास्तला लगभग तीन माह तक रहेगी और कुछ हद तक खरीदारी के लिए भगदड़ मध्य गई थी। उसी अवधि के दौशाख बैंग्जील की कीमतें (फिनाल का मुख्य कच्छा माल) भी 10% बढ़ गई थी। इसी समय अन्य बहुत से उत्पादों की कीमतें भी बढ़ गई थीं। घरेलू फिनाल उत्पादकों ने तटगुरार कीमतें समायोजित कीं। यह केवल साधारण बाजार कियाविधि थी, जो कार्य कर रही थी। इस प्रक्रिया में दोनों फिनाल विभिन्नता अपने शेषर धारकों की कीमत पर बाजार के विद्युलियों को लाभ न कराने देने में सफल हुए। एवं सी एल और एवं ओ सी दोनों भारतीय केमिकल विभिन्नता एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य हैं, जिसने गुलसान का मूल्यांकन करने के लिए एक दल कांडला भेजा था। इसके अलावा, एवं सी एल ने प्राकृतिक आपदा के एकदम बाद सुरक्षा अधिकारियों, तकनीशियों इत्यादि का एक दल भेजा और इस दल द्वारा किए गए कार्य की कांडला पोर्ट द्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा सराहना की गई।

(iv) अन्य आरोप जो घरेलू उत्पादकों पर लगाया गया है, वह यह है कि उस बन्द उन्होंने अमाव उत्पन्न करने के लिए काम बन्द कर दिया था। इस विषय में घरेलू उत्पादकों ने कहा है कि यह दलील तक संगत तथा व्यापारिक दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि साथ- साथ संयंत्र बन्द करके अमाव उत्पन्न करके उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। यह महसूस किया जाता है कि एवं सी एल और एवं ओ सी ने 1998 के अलावा जब लगभग 15 दिनों

का आव्यादन था, और किसी समय एक साथ काम बन्द नहीं किया। फिर भी काम बन्दी के दौरान, काम बन्द होने से पहले, एच ओ सी के पास 2,180 मीटर का भड़ार था और अप्रैल 1998 में फिनाल की कीमत 37,000/- रु० प्रति मीटर से घटाकर 36,000/- रु० प्रति मीटर कम कर दी गई थी और मई, 1998 में फिर से 35,000/- रु० प्रति मीटर कर दी गई थी। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस तरफ का कोई अर्थ नहीं है।

(उ.) भारत में आयात शुल्क का ढाँचा

कुछ पक्षों ने कहा है कि उदारीकरण की बक्ती हुई नीति के अनुरूप फिनाल का आयात शुल्क पिछले वर्षों में कम किया गया है लेकिन अभी इस क्षेत्र में यह सबसे अधिक है, इसलिए भारत में फिनाल विनिर्माताओं के लिए एक अस्तित्वमिति सुरक्षा तथा प्रतिस्पर्धात्मक समाजता प्रदान करती है। फिर भी यह तरफ रक्षोपाय शुल्क के संदर्भ में असंगत समझा जाता है, क्योंकि एक विशेष उत्पाद पर आयात शुल्क का स्तर बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जिनमें से कुछ तुलनात्मक और प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादों पर आयात शुल्क के स्तर तथा राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता और असररक्षीय उत्पादकों की तुलना में घरेलू उत्पादकों द्वारा उठाया गया चुक्सान आदि है। इसलिए हर देश अपनी आवश्यकतानुसार आयात शुल्क के स्तर का निर्धारण करता है, जिसे दूसरों के लिए संदर्भ के रूप में नहीं देखा जा सकता। यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि फिनाल और इसके कच्चे माल के शुल्क में अन्तर 1993-94 में 55% से घटकर इस समय 11.5% हो गया है।

(ए) गुणवत्ता

(i) कुछ पक्षों द्वारा घरेलू फिनाल उत्पाद की गुणवत्ता के विषय में विष्टा व्यक्त की गयी है। इस विषय में यह कहा जाएगा कि घरेलू उत्पादकों ने कहा है कि दोनों भारतीय फिनाल विनिर्माता सिव्येटिक लॉट की आई एस और 9002 प्रदत्त इकाइयाँ हैं। एच सी एल से आई एस और 14001 प्रमाणन प्राप्त कर लिया है तथा एच ओ सी इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। एच सी एल और एच ओ सी दोनों उत्तरदायित्वपूर्ण सावधानी गतिविधि के हस्ताक्षरकर्ता हैं। गुणवत्ता के आधासान के लिए विस्तृत प्रणाली चल रही है। गुणवत्ता की शिकायतों का रिकार्ड (यदि कोई है) रखा अनिवार्य है। पूरे वित्त वर्ष 1998-99 के दौरान एच सी एल ने केवल एक शिकायत प्राप्त की और वह भी जांच के पश्चात पायी गयी कि एच सी एल कारखाने के परिसर से बाहर उपभोक्ता फैक्टरी तक के रास्ते में परिवहन के दौरान हुई मिलावट के कारण थी। एच ओ सी द्वारा कोई गुणवत्ता संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं की गई। दूसरी तरफ, उच्च गुणवत्ता बाहर रखने के लिए एच ओ सी की सराहना की गई।

(ii) यहाँ तक पालीकाबॉनेट श्रेणी के बिस्फेनाल-ए ग्रेड के विनिर्माण के लिए फिनाल की गुणवत्ता का संबंध है, घरेलू उत्पादकों द्वारा यह कहा गया है कि पालीकाबॉनेट का भारत में उत्पादन नहीं किया जाता। अतः भारत में पालीकाबॉनेट श्रेणी के फिनाल की कोई घरेलू आवश्यकता नहीं है। बिस्फेनाल-ए के विनिर्माता मैसर्स केसर पैट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड ने एच सी एल या एच ओ सी से किसी भी उच्च गुणवत्ता के फिनाल की मांग नहीं की है। फिर भी, यदि केसर प्रोडक्ट्स लिमिटेड विनिर्माण की स्थिति में आती है, और पालीकाबॉनेट ग्रेड के बिस्फेनाल-ए का निशात करता है, और अगर उसको उसके लिए विशेष श्रेणी के फिनाल की आवश्यकता ठोकी है तो घरेलू उत्पादक दावा करते हैं कि वे मैसर्स केसर पैट्रोप्रोडक्ट्स की आवश्यकतानुसार गुणवत्ता का फिनाल दे सकते हैं।

अब तक बिस्फेनाल-ए के उत्पादकों अपनी आवश्यकता को अधिकांश भाग घरेलू उत्पादकों द्वारा प्राप्त किया हैं और प्राप्त कर रहे हैं।

(iii) यह सी उल्लेख किया गया है कि घरेलू फिनाल अपनी उच्च भमी वाले अंश के कारण अल्काइल फिनाल के विनिर्माण हेतु उपयुक्त नहीं हैं। इस संबंध में यह महसूस किया जाता है कि घरेलू उद्योगों ने कई वर्षों तक बिना किसी गुणवत्ता संबंधी शिकायत के सफलतापूर्वक अल्काइल फिनाल के विनिर्माताओं को फिनाल की आपूर्ति की है। वास्तव में एवं सी एल स्वयं अल्काइल फिनाल का एक विनिर्माता है और अपने स्वयं निर्मित फिनाल से बिना किसी तकनीकी परेशानी के अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता वाले अल्काइल फिनाल का विनिर्माण करता है। एवं सी एल अपनी स्वयं निर्मित तकनीक के आधार पर अल्काइल फिनाल का विनिर्माण कर रहा है जिसके विकास हेतु उन्हें प्रतिष्ठित आवार्य सर पी. सी. राश पुरस्कार मिला है। भारत में अल्काइल फिनाल के लिए बहुत कठोर विनिर्देशन परफ्यूमरी केमिकल उद्योग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जिसे पी.टी.बी.पी. के रूप में जाना जाता है। एवं सी एल के पास मैं नायकनशारे केमिकल्स का एक पत्र है, जिसमें एवं सी एल के फिनाल से पी.टी.बी.पी. के परफ्यूमरी श्रेणी का विनिर्माण किया है। एवं ओ सी को सेनेकटेडी का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने घट्ट किया है कि उनके द्वारा आपूर्ति किए गए फिनाल की गुणवत्ता सेनेकटेडी के विनिर्देशन और स्तर से पूर्णतः मेल खाती है।

8. समायोजन योजना :

(i) घरेलू उद्योगों की समायोजन योजना के संबंध में कुछ पक्षों ने प्रस्तुत किया है कि आवेदकों में से एक अपनी क्षमता को आगामी 2-2.5 वर्षों में 65000 मी.टन तक बढ़ाने का दावा करते हैं। यह समझ में नहीं आता कि दो वर्षों के समय में आवेदक प्रतिस्पर्धी कैसे हो जाएंगे, जबकि यदि यह मान लिया जाए कि यह कम्पनी 2.5 वर्षों में अपनी क्षमता 65000 मी.टन तक बढ़ायेगी, तिशेषतः जब कि आवेदकों ने रु० 16000 प्रति मी.टन की छूट की मांग की है, और उनके द्वारा प्रस्तावित उपायों से उनकी क्षमता अधिकतम रु० 1500 प्रति मी.टन तक ही बढ़ जाकी। आवेदकों द्वारा स्पष्ट रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि आगामी दो वर्षों में, वे प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे किन्तु उनको, ब्याज की दर या अन्य ढाँचागत अडघनों के संबंध में भारत सरकार की नीतियों की ओर ध्यान नहीं है। घरेलू उद्योगों द्वारा प्रस्तुत किया गया यह वक्तव्य कि 650 करोड़ रु० की लागत पर 100000 मी.टन की क्षमता का एक ग्रीनफील्ड विद्युतरीय संयंत्र की स्थापना करने हेतु एक भिवेश हेतु विद्युत किया जा रहा है, आर्थिक रूप में व्यवहार्य नहीं है और सीधे-सीधे अस्तीकृत करने के योग्य है। वास्तव में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत केवल यह तक ही यह मानने के लिए पर्याप्त है कि आवेदक अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए गंभीर नहीं है। आवेदकों द्वारा प्रस्तावित सकारात्मक समायोजन योजना व्यवहार्य नहीं है, यह सामान्य तथा इस बात से सामने आता है कि ब्याज की लागत, अवमूल्यन तथा 650 करोड़ रु० के भिवेश पर उधित वापसी 27,000/- रु० प्रति टन आती है, यदि संवालन के प्रथम वर्ष में ही घरेलू उद्योग परियोजनाएं अपनी 100% उपयोगिता क्षमता को प्राप्त कर लेती हैं। रक्षोपाय शुल्क का सम्पूर्ण उद्देश्य घरेलू उद्योगों द्वारा सकारात्मक समायोजन को सुविधाजनक बनाना है। यह महा-निदेशक का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करें कि घरेलू उद्योग द्वारा सकारात्मक समायोजन के लिए प्रस्तावित प्रयास तकनीकी और व्यापारिक तौर पर व्यावहारिक हों।

(ii) आयात प्रतिस्पर्धा में सकारात्मक समायोजन बनाने के विषय में दोनों उत्पादकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे यह सन्तुत हैं कि रक्षोपाय शुल्क के रूप में स्थीकृत की गयी राहत अल्पकालीन उपाय है। एवं सी.एल. ने

कहा है कि वर्तमान सुविधाएं उदारीकरण से एम.आर.टी.पी. के समय तैयार की गई थीं, तथा उद्योग में आर्थिक मंदी उच्च निर्धारित लागत की ओर ले जाती है। फिर भी भारतीय उद्योग निर्दल अपनी तकनीक का स्तर उठा रहे हैं तथा अपनी विनिर्माण सुविधाओं को विस्तृत कर रहे हैं, ताकि प्रति यूनिट संचालन लागत कम हो जाए और अनेक क्षेत्रों द्वारा बढ़ती घरेलू सांग को पूरा करने के लिए अपनी प्रभावी क्षमता बढ़ा रहे हैं। क्षमता बढ़िये के क्षेत्र में (विनिर्माण की निश्चित लागत में अनुवर्ती कमी से), एवं सी.एल. जिसने डाल ही में अपनी क्षमता 26,500 टी.पी.ए से बढ़ा कर 30,000 टी.पी.ए की है, के पास 40,000 टी.पी.ए तक क्षमता बढ़ाने की ठोस योजना है। विद्युत लागत कम करने के लिए सह-विद्युत उत्पादन के रास्ते में कैप्टिव विद्युत उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। यह सुविधा पहले ही स्थापित की जा चुकी है तथा यह 1999 तक स्थिर हो जाएगी। इसके अलावा (एवं सी.एल. में) लागत कम करने के तरीकों के सुझावों के लिए बाहरी परामर्शदाता नियुक्त किए गए हैं। फिनाल उत्पाद की लागत कम करने के कुछ सुझाव (उदाहरण के लिए पीड स्टाल (क्यूमीन) की गुणवत्ता फिनाल के विनिर्माण की लागत को घटाने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है)। ये सब घलती रहने वाली प्रक्रियाएँ हैं, जो कि घलती रहेंगी। उद्योग द्वारा नई सुविधाओं के जरिए, जो मुख्य के पास जे.एन.पी.टी. जैसे पत्तनों से (जिसको उन्नत करने वालों में से एवं.सी.एल. एक है और जिसको भू-तल परिवहन मंत्रालय तथा पर्यावरण मंत्रालय द्वारा अनुमति प्राप्त हो चुकी है) तथा डाहेज के पास जी.सी.पी.टी.एल. पत्तनों से प्रोपिलिन का आयात किया जाएगा। पानीपत में आई.ओ.सी. रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाई जा रही है और यह प्रक्रिया मध्य 1999 तक पूरी हो जाएगी। 1999 में जामनगर के पास रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की विश्व स्तरीय आकार की रिफाइनरी स्थापित होने की आशा है। गेल और हुलडिंग की कैप्टर काम्प्लेक्स के साथ निकट भविष्य में इसके आरंभ होने की आशा है और वर्तमान सुविधाएं बढ़ा होने से घरेलू प्रोपिलिन की उपलब्धता सुलभ हो सकेगी तथा कीमते कुछ कम हो सकेंगी और नये स्त्रोतों से और स्त्रोत बन सकेंगे। एवं.सी.एल. विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड फिनाल विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने की योजना बना रहा है (100,000 टी.पी.ए या 150,000 टी.पी.ए)। एवं.सी.एल. सुविधा की योजना गुजरात राज्य के डाहेज हेतु बनायी जा रही है। तकनीक भी निश्चित कर ली गई है। क्यूमीन के लिए स्टेट-आफ टी-आर्ट जिओलाइट तकनीक अमरीका की यू.ओ.पी. के साथ मिलकर तैयार की गई है। इसी प्रकार फिनाल विनिर्माण के लिए नवीनतम उत्पादन तकनीक अमरीका की ए.बी.बी.ल्यूमस ग्लोबल के साथ मिलकर तैयार की गई है। दोनों तकनीक वातावरण के अनुकूल हैं और यह एवं.सी.एल. को निश्चित रूप से संचालन और लागत में ज्ञापदायक होगी। कच्चा माल या तो आयात किया जाएगा अथवा नई सुविधाओं से प्राप्त किया जाएगा जैसा कि ऊपर कहा गया है। एवं.सी.एल. परियोजना के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। पर्यावरण प्रभाव निर्धारण का अध्ययन पूरा किया जा चुका है। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस परियोजना को अनापत्ति प्रमाण पत्र स्थीकृत किया जा चुका है। एवं.सी.एल. की जल आवश्यकता डाहेज में जी.आई.टी.सी. की सामान्य जल आपूर्ति योजना में सम्मिलित की जा चुकी है और इसके लिए उन्होंने आरंभिक अदायगी भी कर दी है। विद्युत सह-उत्पत्ति रूट द्वारा उत्पन्न करने की योजना बनाई गई है। धन के लिए एवं.सी.एल. पहले ही वित्तीय संस्थानों से बात कर चुके हैं। एवं.सी.एल. परियोजना का कच्चा माल और तैयार उत्पाद ट्रैफिक के आंकड़े डाहेज में बनने वाले गुजरात कैमिकल पोर्ट टर्मिनल काम्प्लेक्स के आंकड़ों में सम्मिलित किए जा चुके हैं। इस पत्तन के 1999 के अंत तक संचालित होने की उम्मीद है। यह भी संभावना है कि एवं.सी.एल. और एवं.सी.एल. के क्षेत्र में मिल कर प्रयास करें। तथापि, नकदी की कमी के कारण (और परिणामस्वरूप लाभांश में कमी) एवं.सी.एल. को वित्तीय संगठनों से धन लेने में अत्यधिक परेशानी हो रही है। इससे 100,000 टी.पी.ए क्षमता वाले ग्रीनफील्ड फिनाल संयंत्र के निर्माण के लिए लम्बी अवधि लम्बी योजना को कार्यान्वित करने में विवर्ष हो रहा है। दूसरी ओर भविष्य के लिए हमारे संगठन को बचाने के लिए इस परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन होना अति आवश्यक है।

(iii) इस विषय में एवं ओ सी ने कहा है कि क्षमता बढ़ाने के क्षेत्र में (विनिर्माण की निर्धारित लागत में कमी से) एवं ओ सी ने हाल ही में अपनी प्रभावी क्षमता 40,000 टी पी ए से 45,000 टी पी ए बढ़ाई है । विद्युत लागत कम करने के लिए एवं ओ सी द्वारा सह-उत्पत्ति रूट द्वारा कैप्टिव विद्युत उत्पादन सुविधाएं आरंभ करने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं । यह सुविधा पहले ही स्थापित की जा चुकी है, जिसका लाभ वर्तमान वित्त वर्ष से प्राप्त होना चूस्त हो जाएगा । यह सब प्रक्रियाएं घलती रहने वाली हैं, और घलती रहेंगी । एवं ओ सी, रिफाइनरी के साथ संयुक्त उद्यम रूप से 100,000 टी पी ए की विश्व स्तरीय ग्रीन फील्ड फिलाल विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने की योजना बना रहा है । एवं ओ सी सुविधा तटीय स्थानों पर महाराष्ट्र अथवा गुजरात राज्य में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है । तकनीक प्राप्त करने के लिए कार्यवाही चल रही है । एयूमिन के लिए स्टेट-आफ टी-आर्ट जिओलाइट तकनीक तथा फिलाल विनिर्माण के लिए जवीनतम तकनीक प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है । दोनों तकनीक पर्यावरण के लिए अनुकूल होगी तथा एवं ओ सी को संचालन और लागत में निश्चित रूप से फायदा देगी । यह भी समावना है कि इस क्षेत्र में दोनों विनिर्माता एवं ओ सी और एवं सी एल दोनों संयुक्त रूप से प्रयास करें ।

(iv) इस प्रकार घरेलू उद्योग का आयात प्रतिस्पर्धा के साथ समायोजन की योजना काल्पनिक नहीं है । वर्धित आयात द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा से वे क्यों नहीं सुकाबला कर सकते इसके लिए भी उन्होंने कारण दिए हैं । उनमें से एक कारण उन्होंने स्तरीय अर्थव्यवस्था की कमी बताया है । घरेलू उत्पादक लगातार अपनी उत्पाद सुविधाओं को बढ़ा रहा है । पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपनी क्षमता धीरे-धीरे बढ़ा कर 1994-95 में 80,000 मी.टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1998-99 में 75,000 मी.टन प्रति वर्ष की, जो कि क्षमता में 25% की वृद्धि है । घरेलू उत्पादकों ने लागत कम करने की योजना के लिए आवश्यक विवरण प्रस्तुत किए हैं और प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में उससे लागत में कमी की सम्भावना है । यह एक अव्यवहार्य समायोजन योजना प्रतीत होती है, जो अभी लागू होने वाली है और दो साल के समय में परिणाम देगी । घरेलू उद्योग ने हालांकि अपनी यांत्रिकी में तीन साल के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण करने के लिए अनुरोध किया था लेकिन उनके नियोजित प्रयासों को देखते हुए आरंभ करने वाली नोटिस में यह दो साल के लिए सीमित कर दिया गया । लम्बी अवधि की योजना के विषय में तथ्यों को देखते हुए यह प्रस्तावित किया गया कि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण पर केवल दो वर्ष के लिए विवार किया जाए, और घरेलू उत्पादकों द्वारा नियोजित लम्बी अवधि के प्रयासों के विषय में चर्चा आवश्यक नहीं है । किन्तु भी तकीं की रक्षा के लिए, यह महसूस किया जाता है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा 100,000 - 150,000 टी पी ए का उंची लागत पर ग्रीन फील्ड फिलाल विनिर्माण सुविधा स्थापित करना, एवं ओ सी एल के भास्तव में कोई अपवाह नहीं है, क्योंकि ऐसे फिलाल संयंत्र विश्व भर में अत्यधिक पूँजी लगाने वाले संयंत्र हैं । इसके अलावा ये संयंत्र केवल एक उत्पाद फिलाल का ही उत्पादन नहीं करते, इसलिए अन्य उत्पादों की लागत को भी आपस में बोंटाना पड़ेगा । यदि संसार भर में ये संयंत्र पर्याप्त फिलाल उत्पाद कर सकते हैं, यह समझ ने नहीं आता कि समान परिस्थितियों में वे भारत में कुशलतापूर्वक फिलाल क्यों नहीं उत्पादित कर सकते । अतः यह महसूस किया जाता है कि घरेलू उद्योग, आयातों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सकाशत्वक समायोजन बनाने की प्रक्रिया में हैं और उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए दो वर्षों की आवश्यकता है ।

(9) सार्वजनिक हित

(i) कुछ पक्षों ने तर्क दिया है कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से सार्वजनिक हित में कोई लाभ नहीं पहुँचेगा । इसके विपरीत, रक्षोपाय शुल्क को अधिरोपण गमीर रूप से सार्वजनिक हितों के प्रतिकूल होगा, क्योंकि

कई अस्त उपनोक्ता उद्योग बंद हो सकते हैं। इस संबंध में यह महसूस किया जाता है कि मट "सार्वजनिक हित" अपनी परिधि में केवल उपनोक्ता हितों को ही नहीं लेती। यह एक आधिक वृहत्तर मट है जो वृहत्तर सामुदायिक हितों को व्याप्त में रखते हुए सामान्य सामाजिक कल्याण को अपनी परिधि में लेता है। जब रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से आयातित फिनाल की लागत में वृद्धि होगी तो यह फिनाल से विभिन्न होने वाले अतिम उत्पाद को भी प्रभावित करेगी, इसलिए रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के उद्देश्यों को व्याप्त में रखना आवश्यक है। रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का उद्देश्य घरेलू उद्योगों को वर्धित आयात से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा की नई स्थिति के साथ सकारात्मक समायोजन करने के लिए समय उपलब्ध कराना है। इसलिए कुछ अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण न केवल ग्राहकों पर होने वाले प्रतिकूल असर, यदि कोई हो, को कम करेगा बल्कि उन्हें प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर अपनी भाँग पूरी करने के लिए एक व्यापक विकल्प भी प्रदान करेगा। वे घरेलू उत्पादक, जिन्होंने बड़ी सार्वजनिक पूजी के साथ संयंत्रों की स्थापना की है, उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मूल्यवान योगदान दिया है। इसलिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण न केवल वर्धित आयात के द्वारा उत्पन्न प्रतिस्पर्धा में उनके टिके रहने में सहायक होगा, बल्कि फिनाल के खरीदारों के साथ-साथ फिनाल से विभिन्न होने वाले उत्पादों के खरीदारों के भी दीर्घकालीन हित में होगा। इसलिए यह महसूस किया जाता है कि फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण सार्वजनिक हित में होगा।

(ii) यह भी प्रस्तुत किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण देश के नियात पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा क्योंकि नियात उत्पादन में प्रयोग होने वाला आयातित फिनाल मंहगा हो जाएगा। इस संबंध में यह महसूस किया जाता है कि नियात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शुल्क और करों के बांगे हैं, अर्थात् रक्षोपाय शुल्क सहित वे सभी शुल्क और कर जिन्हें कि नियात उत्पादन के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त इन्पुट्स पर भुगतान किया गया, वे शुल्क वापसी आदि के रूप में वापस करने के योग्य हैं। इसलिए नियात उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले आयातित फिनाल पर भुगतान किए गए शुल्क और कर जिनमें रक्षोपाय शुल्क भी शामिल हैं, भी वापसी के योग्य होंगे। रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बनाना है। इसलिए घरेलू विभिन्न फिनाल यदि नियात उत्पादन में प्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी नहीं होता तो रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण इसके अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बनने में सहायक होना चाहिए, जो कि नियातकों के दूरगमी हितों में होगा। जहां तक नियात उत्पादन में प्रयोग हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत फिनाल के शुल्क मुक्त आयात का प्रश्न है, वहीं भी ऊपर उल्लेख किए गए सिद्धान्त लागू होते हैं, अर्थात् या तो इस प्रकार का आयात रक्षोपाय शुल्क के उदाग्रहण पर अधारित नहीं हो सकता या, यदि रक्षोपाय शुल्क एकत्रित किया जाता है तो विद्यमान विधि के अनुसार, अतिम उत्पाद के नियात पर यह वापसी के योग्य होना चाहिए। इसलिए यह महसूस किया जाता है कि फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण न तो नियात उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला है और न ही यह सार्वजनिक हितों के विरुद्ध होगा।

10. अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क

इस तथ्य के परिप्रेक्ष्य में कि विषम परिस्थितियाँ, जो यह सकेत कर रही हैं कि यदि जाव पूरी होने तक रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण में देरी की गयी तो घरेलू उद्योगों को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, विद्यमान नहीं थी, अतः किसी अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की संस्तुति नहीं की गई थी।

11. भारत को नियात में देशों के शेयर

अप्रैल - दिसम्बर, 1998 की अवधि के दौरान भारत में फिनाल के आयात के संबंध में सूचना के आधार पर यह महसूस किया जाता है कि इस अवधि के दौरान केवल 8 देशों ने भारत में फिनाल नियात किया । लदान के बिल के आधार पर इस अवधि के दौरान भारत के आयात में उनका अंश निम्नानुसार था:-

देश/क्षेत्र	आयात भी. टर्ण	प्रतिशत शेयर
फ्रांस	31.20	0.125
जापान	3932.46	15.81
नीदरलैंड	31.20	0.125
दक्षिण अफ्रीका	8063.41	32.42
दक्षिण कोरिया	11813.03	47.50
ताईवान	999.01	4.02
कुल	24870.31	100

(ज) निष्कर्ष एवं सम्पत्ति

1. उपरोक्त परिणामों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में फिनाल के संबंधित आयात से फिनाल के घरेलू उद्योगों को गमीर क्षति की आशंका है और भारत में फिनाल के आयात पर दो वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण सार्वजनिक हित में होगा ।

2. उस रक्षोपाय शुल्क की मात्रा का निर्धारण करने में, जो कि घरेलू उत्पादकों को गमीर क्षति होने से रोकने के लिए पर्याप्त होगी एवं उन्हें सकारात्मक समायोजन करने में मददगार होगी, एच.सी.एल एवं एच.ओ.सी. की अप्रैल - दिसम्बर, 1998 के उत्पादन की भारित औसत लागत को ध्यान में रखा गया है । घरेलू उत्पादकों ने, निर्वैश्वन पूँजी आदि पर संभावित वापसी के आधार पर लाभ की कुछ राशि के लिए दावा किया है जिसको अणिक माना गया है । इसलिए उत्पादन की भारित औसत लागत पर आधारित लाभ की उत्तरी कम मात्रा (गोपनीय) को उचित माना गया है और इसकी अनुमति दी गई है । इसी प्रकार फिनाल के सी.आई.एफ. आयात मूल्यों पर भी पिछले छः महीनों अर्थात् जुलाई - दिसम्बर, 1998 की अवधि के लिए भारित औसत लागत के आधार पर विचार किया गया है । केफिट शर्तों एवं औसत आधार पर हैबलिंग चार्ज के लिए, सी.आई.एफ. आयात मूल्यों में समायोजन किया गया है । आयातित फिनाल की उत्तराई के समय की लागत को निर्धारित करने हेतु सीमा शुल्क की लागू दरों में परिवर्तन को ध्यान में रखा गया है । आतंरिक माल माड़े के लिए आयातित फिनाल की उत्तराई के समय की कीमत एवं कोडला पत्तन पर भंडारण पर लागत के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है क्योंकि घरेलू मूल्यों को भी एक्सवर्कर्स माना गया है व कोडला पत्तन पर आयातकों को, सहवर्ती लागत और लाभों के साथ आयातित फिनाल का भंडारण एक विकल्प मात्र है ।

3. घरेलू उत्पादकों द्वारा सकारात्मक समायोजन को सुगम बनाने की दृष्टि से रक्षोपाय शुल्क को प्रगामी उदासीकृत करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संस्तुति की जाती है कि फिनाल के वर्धित आयात से घरेलू उत्पादकों द्वारा सुगम बनाने की अवधि को बढ़ाने वाली गंभीर क्षति की आशंका से उसे बचाने हेतु दो वर्ष की अवधि के लिए भारत में होने वाले फिनाल के आयात पर गथामूल्य के आधार पर निम्नानुसार रक्षोपाय शुल्क लगाया जाए।

अवधि	संस्तुत कुल संरक्षण का स्तर %	विद्यमान संरक्षण	संस्तुत रक्षोपाय शुल्क % (3) - (2)
(1)	(2)	(3)	(4)
प्रथम वर्ष	27.5+22	27.5	22
द्वितीय वर्ष	27.5+15		15

[फा. सं.एस. जी./आई.एम.जी./2/98]

आर. के. गुप्ता, महानिदेशक

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 1999

Subject : Safeguard investigation concerning import of Phenol into India—final findings

G.S.R. 430(E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 thereof.

A PROCEDURE

1. The Notice of Initiation of safeguard investigation concerning imports of Phenol into India was issued on 2.2.1999 and was published in the Gazette of India, Extraordinary on 8.2.99. A copy of the Notice was sent to all known interested parties, namely:-

Domestic Producers

- (i) Hindustan Organic Chemicals Ltd (HOC), Mumbai
- (ii) Herdillia Chemicals Ltd. (HCL), Mumbai
- (iii) Neyveli Lignite Corporation, Tamilnadu.

Importers

- (i) C.J.Shah & Company, Mumbai
- (ii) Haresh Kumar & Company, Mumbai
- (iii) PCL Industries, New Delhi.
- (iv) Kantilal Manilal & Company, Mumbai
- (v) Vinmar International India Pvt. Ltd., Mumbai

User Industries

- (i) Xpro India, Mumbai
- (ii) Bakelite Hylam Ltd., Hyderabad
- (iii) Greenply Industries Ltd., Distt. Ratnagiri, Maharashtra
- (iv) Gargi Huttenes Albertus Private Limited, Mumbai
- (v) Alta Laboratories Ltd., Dadar, Mumbai
- (vi) United Phosphorus Limited, Mumbai
- (vii) Colour Chem Limited, Balkum, Thane

Exporters

- (i) Phenolchemie GmbH, Germany
- (ii) Enichem, Italy
- (iii) Georgia Gulf Corporation, U S A
- (iv) Mitsui Chemicals, Tokyo
- (v) Kumho Chemical Company, Seoul, Korea
- (vi) Taiwan Prosperity Chemical Company, Taiwan
- (vii) Merisol, South Africa
- (viii) Kolmar Petrochemicals AG, Switzerland.
- (ix) ICC Chemical Corporation, New York,
- (x) Verband der Chemischen Industrie - VCI Germany

Overseas Associations

- (i) Chemical Safety Management Centre, Japan Chemical Industry Association-JCIA, Tokyo 100, Japan
- (ii) Chemical and Allied Industries Association -(CAIA) Auckland Park 2006, South Africa.
- (iii) Korean Petrochemical Industry Association -(KPIA) Chongno-ku, Seoul, Korea.
- (iv) Petrochemical Industry Association of Taiwan (PIAT) Section 4, Chutung, Hsinchu, Taiwan.
- (v) Chemical Manufacturers Association (CMA) Virginia-22209, USA

Indian Associations

- (i) Society of Thermosetting Industries, Mumbai
- (ii) Indian Laminates Manufacturers Association, Mumbai
- (iii) Indian Chemical Manufacturers Association, Mumbai

2. A copy of the notice alongwith the application and questionnaire was also sent to the governments of exporting countries through their High Commissions/Embassies in New Delhi namely China, Chinese Taipei, Germany, Indonesia, Italy, Japan, Korea DPR, Korea RP, Kuwait, Malaysia, the Netherlands, New Zealand, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, U.K. and USA.

3. Questionnaires were also sent on the same day to all known domestic producers, exporters and importers who were asked to submit their response by 12.3.1999.

4. Request for extension of time to submit their reply was made by the following parties:

- (i) Hindustan Organic Chemicals Ltd., Mumbai
- (ii) Herdillia Chemicals Ltd., Mumbai
- (iii) Mitsui Chemicals Inc., Japan
- (iv) Kumho P&B Chemicals Inc., Seoul, Korea
- (v) Haresh Kumar & Co., Mumbai

Keeping their request in mind and the need to complete the investigation within the statutory period, extension upto 19.3.99 was allowed and parties concerned were accordingly informed.

5 Replies to the Notice dated 2.2.1999 and to the questionnaire were received from the following parties:-

Domestic Producers

- (i) Hindustan Organic Chemicals Ltd., Mumbai
- (ii) Herdillia Chemicals Ltd., Mumbai
- (iii) Neyveli Lignite Corporation Ltd., Neyveli

Importers

- (i) C J Shah & Compay, Mumbai
- (ii) Haresh Kumar & Co., Mumbai
- (iii) Kantilal Manilal & Co., Mumbai

User Industries

- (i) Gargi Huttenes Albertus Private Limited, Mumbai
- (ii) Alta Laboratories Ltd., Dadar, Mumbai

Exporters

- (i) Phenolchemie GMBH & Co., Germany
- (ii) Enichem, Italy
- (iii) Mitsui Chemicals Inc., Japan
- (iv) Kumho Chemical Company, Seoul, Korea
- (v) Merisol, South Africa
- (vi) Taiwan Prosperity Chemical Corporation, Taiwan.

The European Union/Delegation of the European Commission in India also requested the Director General (Safeguards) to consider them as an interested party in the investigations. Their request as an interested party was taken on record and the European Union/Delegation of the European Commission in India was informed accordingly.

Indian Associations

- (i) Indian Chemical Manufacturers Association, Mumbai

6. Response to the notice has also been filed by the following parties.

- (i) Laghu-Udyog Bharti, Faridabad
- (ii) Indian Core Oils Pvt. Ltd , Faridabad
- (iii) Kesar Petroproducts Ltd., Mumbai
- (iv) Marvel Thermosets Pvt Ltd., Mumbai
- (v) The Institute of Indian Foundrymen, Calcutta
- (vi) Romit Resins Pvt. Ltd., Panvel-410206
- (vii) Foseco India Ltd., Pune
- (viii) Atul Ltd., Gujarat
- (ix) Schenectady Specialities Asia Ltd., Mumbai

- (x) Century Laminating Co. Ltd., Calcutta
- (xi) ABC Products Ltd., Calcutta
- (xii) Kitply Industries Ltd., Calcutta
- (xiii) Winlam Industries Ltd., Calcutta
- (xiv) Andamans Timber Industries Ltd., Calcutta
- (xv) Wonder Laminates Pvt. Ltd., Calcutta
- (xvi) Kiran Trading Co., Calcutta
- (xvii) United Metachem Private Ltd., Pune
- (xviii) Farmson Pharmaceutical Gujarat Ltd., Vadodara

7 Verification of the information considered necessary for the investigation was done and to this end a team of officers visited the premises of M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd., Cochin; M/s. Herdillia Chemicals Ltd., Mumbai; M/s. Kesar Petroproducts Ltd., Mumbai; M/s. C.J.Shah & Co., Mumbai and M/s. Kantilal Manilal & Co. Mumbai. The outcome of investigations was conveyed to the concerned parties and a copy of the investigation report was also placed in the Public File.

8 A Public Hearing was given to all interested parties on 16.4.99, notice for which was sent on 19.3.99. During the Public Hearing the interested parties were requested to file their written submission of oral arguments made by them by 23rd April 1999; collect replies filed by others on 26th April 1999 and to file rebuttals if any, by 7th May 1999. The following parties attended the public hearing:

- (i) Hindustan Organic Chemicals, Mumbai
- (ii) Herdillia Chemicals Ltd., Mumbai
- (iii) Neyveli Lignite Corporation, Neyveli
- (iv) Deguisse Huls India Pvt. Ltd., representing Phenol Chemie, Germany
- (v) Samsung Corporation, Mumbai representing Kumho P & B Chemicals, Korea
- (vi) Schenectady Specialities Asia Ltd., Mumbai
- (vii) Kanoria Petroproducts Ltd., New Delhi.
- (viii) Merichem-Sasol RSA (Pty) Ltd., South Africa through their Delhi representative.
- (ix) Embassy of Korea, New Delhi
- (x) Embassy of Japan, New Delhi.
- (xi) European Union, Delegation of the European Commission in India, New Delhi.
- (xii) Sumitomo Corporation, Japan.
- (xiii) Mitsui Chemicals/Mitsui & Co., Japan (through counsel)
- (xiv) United Metachem Ltd., Pune.
- (xv) Foseco India Ltd., Pune.
- (xvi) Andhra Sugars Ltd., New Delhi.
- (xvii) Haresh Kumar & Company, Mumbai.
- (xviii) Kesar Petroproducts Ltd., Mumbai (through counsel)
- (xix) Farmson Pharmaceuticals, Vadodara
- (xx) Gargi Hutteness Albertus, Mumbai.
- (xxi) Atul Ltd., Gujrat.
- (xxii) ABC Products Ltd., Calcutta

- (xxiii) Allied Resins and Chemicals Ltd., Calcutta
- (xxiv) Century Laminating Co. Ltd., New Delhi.
- (xxv) Bakelite Hylam Ltd., Hyderabad.
- (xxvi) Institute of Indian Foundrymen and Laghu Udyog Bharti, Faridabad (through its President)
- (xxvii) Alta Laboratories, Mumbai.

B VIEWS OF EXPORTERS

The following main points have been made by the exporters:

(a) M/s. Phenol Chemie GMBH and Co., Germany

- (i) They have thoroughly checked their records of export sales of Phenol going back to 1995 and have not been able to find any direct sales effected by them to India.
- (ii) Phenol Chemie sporadically sells Phenol to international trading companies & they are not aware of the final destination of such quantities. This perhaps has led to imports being shown from Germany.
- (iii) During the last fifteen months or so all regional phenol markets (Europe, North America, Asia) have shown a price erosion of upto 50% due to a growing imbalance of supply and demand and also due to almost historically low raw material costs (Cumene, Benzene, Propylene). It was, therefore, no surprise to find a similar development in India. This development was enhanced by continuous technology improvements making existing phenol plants substantially more cost effective as well as the addition of new, modern world scale phenol plants with capacities of upto 4,00,000/- Mt/year.
- (iv) During the next 24 months a total of approximate 80000 MT/year capacity will be added worldwide. These new plants will apply state-of-the-art-technology and further improve the cost effectiveness of making phenol. Under prevailing market circumstances most of the benefits of such a development will be resting with phenol consumers world wide and improve their economics.
- (v) All phenol consumers in India would welcome the opportunity to participate in the benefits a modern, globally competitive phenol industry is able to offer.

(b) Mitsui Chemicals Inc., Japan

- (i) The applicant Indian manufacturers of Phenol are in a monopolistic position in India (as per their own claim they control upto 91% of the domestic market) and it appears that the present application is being used as an instrument to secure and perpetuate that monopolistic position. Several of the issues currently complained of, have also existed in earlier years, in which years the applicants achieved a capacity utilization in excess of 94%, clearly indicating that these factors did not affect them significantly. It is apparent that the sharp decrease in exports which indicate that the Applicants have become internationally uncompetitive is the reason for the current application with a view to secure and sustain the Applicants monopolistic dominance of the Indian market.

(ii) The quantum of the levy claimed effectively also indicates that the Applicants are trying to secure for themselves a level of profitability wholly unconnected with the current trend in the international market. This would clearly be at the cost of the Indian Domestic User Industry. The action indicated appears to be detrimental to the Indian Industry as a whole and with a very narrow perspective to secure market dominance and unrealistic price/profit realization for the two Applicants.

(iii) The Application fails to indicate "serious injury" and in particular fails to establish any causal link between the claimed injury and the imports.

(iv) The Application fails to establish "critical circumstances" and more particularly, "irreparable damage" consequently the request for imposition of provisional duty does not appear sustainable.

(v) The application sets out information on certain critical issues in a selective and improper manner. One such instance is regarding the information as to the Production Capacity Utilization for which the figures have been set out in relation to "Utilization of capacity to satisfy domestic demand". It is submitted that what was required to be indicated is the figures as to entire Production Capacity Utilization for all streams of production and not only information relevant to capacity utilization for domestic demand. A consideration of this issue is vital to a determination of the injury claimed and the sort of selective information offered must be construed as a conscious act of the Applicants with a view to not disclosing the information required which presumably is adverse to them.

(vi) On the issue of injury, various important issues, *inter alia* employment, etc. have not been referred to, indicating that information on these issues is not supportive of the Applicant's case.

(vii) The source of information in support of various submissions of the Applicants have not been indicated or indicated as Market Information Sources. Such Market Information Sources are clearly nebulous and are not capable of sustainable verification and this vitiates the Application.

(viii) Various figures such as the domestic demand figures are not absolute figures and have been derived by using mathematical formulae and therefore such figures are not reflective of the true position.

(ix) Certain figures set out regarding a drop in the percentage of profitability do not seem to accurately reflect the position as set out in certain published audited accounts of the Applicant Company. It is submitted that this is a matter of some serious concern as to the credibility of the Application.

(x) With regard to decrease of production, although Hindustan Organic Chemicals Ltd. (HOC) and Herdillia Chemicals Ltd. (HERDILLIA) state that domestic production of Phenol is decreasing from 1997-98 to 1998-99, domestic production to meet with the domestic Phenol demand has increased as shown in the following table. Decrease of total production should be attributed to the decrease of export which is in the control of HOC and HERDILLIA, but not to the increase of imports.

Period	(Metric Tonnes)				Difference (C-A)
	1997-98	1998 upto Dec (B)	1998-99 (estimate)	Difference (Bx4/3=C)	
Total Domestic Production (X)	69,281	48,703	64,937	-4,344	
Exports (Y)	7,675	52	69	-7,606	
Domestic production to meet with Domestic Demand (X-Y)	61,606	48,651	64,868	3,262	

(xi) HOC and HERDILLIA could have raised their total production (for both domestic demand and exports) by exporting their Phenol to other countries as they did in the previous years. The levy of Safeguard Duty in India has no effect on HOC and HERDILLIA's exportation of Phenol into other countries, which depends on their own international competitiveness in price and quality of their products.

(xii) With regard to Capacity Utilization, the capacity utilization rate of HOC and HERDILLIA to meet with the domestic demand remains stable at 86%, as would be evident from the table below:

Period	1997-98	1998-99 (Up to Dec.)
Production Capacity	71,500	56,250
Production to Meet with Domestic Demand	61,606	48,651
Capacity Utilization to Meet with Domestic Demand	86.2%	86.5%

(xiii) The figures set out in the Application are the figures of capacity utilization for the domestic demand, which is not an appropriate basis of reference as capacity utilization in all streams of production is required to be considered. An analysis of capacity utilization indicates that capacity utilization in earlier periods after accounting for domestic sales and exports was extremely high e.g. for the year 1995-96 the capacity utilization is 99.56%. It is clear from the figures on record that there has been a significant decrease in the export markets for the Applicants and any decrease in the capacity utilization is directly attributable, inter alia to the factor that the Applicants have ceased to remain internationally competitive.

(xiv) The applicants have stated that Phenol price on CIF India basis has more drastically fallen than prices in other areas comparing the prices in January 1998 and those in September 1998. However, comparison in other period will give a different view. Phenol is a commodity product sold worldwide and its price is dropping due to overall decline of international market prices. Rate of decline in India is at the same level as other areas.

(xv) Although HOC and HERDILLIA show the import price of each shipment in their Application, they are of the opinion USD 395/MT is an exceptional case and should not be used for general consideration.

(xvi) In the present phase of globalization, local prices are also reflective of international prices. The expectation of the Applicants as indicated from the Application is that they should be able to sustain within India, (at the cost of the Indian Domestic User Industry), profit as they were making in the past, which wholly fails to recognize the impact of international prices. The applicants appeared to be using these proceedings as an instrument to try and secure an unrealistic level of profitability, which they can exploit in view of their monopolistic dominance of the Indian market.

(xvii) An examination of the sales figures of both the Applicants indicates that the sales figures of HERDILLIA have consistently shown an increase, which pattern of increase is sustained even on the basis of the annualized figures set out for year 1998-99. As regards HOC, the figures set out clearly indicate a fluctuating trend of sale from 1991-92 and thereafter. The projective sales for 1998-99 are also reflective of this fluctuating trend of sale which has earlier existed for HOC. The imports in question therefore, appear not to have caused any serious injury to the Applicants in respect of their sales.

(xviii) As to the issue of the stocks built up an examination of HOC's stock position clearly indicates that this has also shown a fluctuating pattern, which pattern is likely to sustain in 1998-99 and thereafter. As regards HERDILLIA, their figures as to closing stock when examined in the context of the factor that as compared to their earlier exports, they have had no exports in the years 1997-98 and 1998-99 clearly indicate any stock built up is directly attributable to their failure to sustain their competitiveness in the international market. The imports in question therefore, have had no adverse impact on the stock position of the Applicants.

(xix) The various published documents and returns of the Applicants clearly indicate that they have made specific statements on various issues critical to these proceedings, where elaborate reasons have been set out as to lower profitability. In such statements, there are in fact, specific averments made as to higher sales volume. The various reasons set out are levy of indirect taxes; Imposition of local taxes; Power failures, Inadequate infrastructure facilities at ports, etc. Therefore, that the injury, if any, to the Applicants is factors and issues other than the imports in question.

(xx) It is pertinent that as distinguished from other such proceedings which require the establishment of injury, safeguard proceedings specifically require the establishment of "serious injury". In the present case, serious injury as required, or for that matter, even injury, has not been established. An appraisal of injury is required to be made in the context of the interested domestic industry and on a balance of the interest of such domestic industry. The present proceeding is merely to secure the

narrow interest of the Applicant at the cost of the larger interest of the Domestic User Industry. They believe that the supplies of the Applicants are not of a commensurate quality and require further processing, that the Applicants are unable to maintain delivery schedule and have adopted distribution and pricing strategies which are not entirely acceptable to local Indian consumers.

(xxi) The domestic consumption of Phenol (including imports) has highly increased from 1997-98 to 1998-99. Although HOC and HERDILLIA increased their production to meet with domestic demand they could not satisfy such increased consumption to fill in the gap between domestic demand and supply. Therefore, Phenol users in India had to import Phenol to keep their production. Decline of share of HOC and HERDILLIA in domestic consumption is caused by their failure to produce more Phenol though they have enough nameplate production capacity, and not caused by increase of imports.

(xxii) HOC and HERDILLIA's calculation of requested Safeguard Duty rate of 72% is based on their asserted minimum fair price using 12% as reasonable return on employed capital. This rate of 12% is unfairly high for manufacturers of commodity chemicals today and even higher than the profitability rates realized by HOC or HERDILLIA in the past. In 1995-96, HOC realized profitability of 14.20%, but during that period, prices of chemical products were exceptionally high and those prices went down in 1997.

(xxiii) Demand of Phenol in India is rapidly increasing. Phenol is one of the most important basic chemicals to produce many kinds of phenol derivatives. These phenol derivatives are used in various industries, from plywood industry to electrical equipment industry or pharmaceutical industry which are in a severe international competition. Imposition of Safeguard Duty on Phenol would benefit 2 domestic Phenol producers at the expense of many manufacturers demanding Phenol. Delay of growth of such manufacturers would cause irreparable adverse effect on general economy of India. They admit that the domestic Phenol producers are experiencing difficulty to decrease import duty rate on Phenol. However, import duty rate on Phenol in India is still considerably higher than other countries.

(xxiv) As production capacity of domestic Phenol producers cannot satisfy the total demand of Phenol in India, Phenol user will have to purchase imported Phenol even after imposition of Safeguard Duty. Procurement of Phenol at higher than international market price would severely deteriorate competitiveness of those users. They have been requested by Phenol users in India to supply them Phenol at competitive price with high quality which domestic Phenol producers are unable to attain and hope to cooperate with them by continuous supply of Phenol manufactured by Mitsui.

(c) Merisol, South Africa

(i) Merichem-Sasol RSA (Pty) Ltd. (Mersol RSA) and its antecedent Sasol Phenolics, has been a long standing supplier of Phenol to the Indian market through its distributing agent M/s Kanoria Petroproducts Ltd as well as ICC Chemical Corporation's representative office in India.

(ii) Mersol RSA is a supplier of natural phenol, opposed to synthetic phenol as produced by the major producers in India, accounting for less than 1% of total

world production capacity. Producing in excess of the domestic South African demand, Merisol RSA follows a strategy of exporting its phenol to markets on a widespread global basis. As a small producer Merisol RSA is not in a position to determine prices but rather adopts a strategy of adjusting its prices as dictated by domestic and international market conditions.

(iii) Phenol prices in the Indian market are related to world prices with discrepancies attributable to freight differentials. Prices for the various world regions, as reported by ICIS-LOR in Quarter I of 1999, ranged from USD 410-450/mt CFR(SE Asia), USD 400-430/mt CRF (China) to USD 430-470/mt FD at customer (Europe). In their experience prices reported by ICIS-LOR are always higher than actual prices realized in the market. According to their information, prices achieved in the Indian market during the same period ranged from USD 400-420/mt. CIF

(iv) World phenol prices result from equilibrium established in balancing demand and supply of phenol worldwide. Being a commodity product, phenol prices across the globe follow similar trends as consumers and producers thereof establish price levels based on this principle. This is evident in the price levels quoted above as well as in high price levels observed during First Quarter of 1998, USD 660-710/mt CFR (SE Asia), USD 670-700/mt (China) and USD 780-820/mt FD at customer (Europe). According to their general information, phenol traded at price levels of USD 670-700/mt (CIF) in India during the same period.

(v) As a net importer of phenol, India's consumers would continue to depend on imports thereof to satisfy demand with expectations of economic growth in the country, the deficit will almost certainly continue to increase.

(vi) The introduction of safeguard duties against imports on phenol will undoubtedly create imbalances in the supply and demand thereof not only in India, but in the region and world markets as well. The result will be detrimental to consumers of phenol and its derivative products in India, creating market conditions that may take a long time to correct.

(vii) As a company committed to continue doing business in India, Merisol RSA therefore wishes to express its concern over the introduction of safeguard duties on the imports of phenol, even for limited periods of time.

(d) **Enichem, Italy**

(i) Their exports to India have been decreasing all over the years accounting a minimum of 0.08% in quantity and 1% in value of all imports in the fiscal year 1996-97.

(ii) Enichem sell products of their own production both directly and through Enichem branch offices. Very seldom, marginal quantity of Phenol was sold to International Traders for the rest of the world. The main outlet market is Europe with marginal quantity (around 1% of total sales) shipped to rest of the world.

(iii) Enichem's strategic marketing policy is to serve the Italian market keeping the domestic market share as highest as possible (over 70%). Second priority is to follow increasing consumption of main European Accounts, i.e. producers of Bisphenol-A and to keep a presence in the European markets. Enichem normally have around 50% of phenol production consumed for captive use.

(iv) Details of their capacity, production, domestic selling price, export price to India, quantum of exports were as under :-

Year	Capacity (KT)	Production (KT)	Price in US \$ Domestic Export (Budget)	Quantity Exported to India(MT) (Budget)
1996	390	373	648	850
1997	390	373	560	738
1998	395	343	525	--
1999	395	345	450	--
			(Budget)	(Budget)

(e) Kumho P & B Chemical Inc., Seoul, Korea

(i) The company has submitted certain details relating to their capacity, production, cost of production, selling price in domestic market, and export price per unit in India during the year 1998-99 which is as under -

	1998	1999
Capacity	1,20,000	1,20,000
Production	1,24,248	1,24,000
Cost of production	416 US \$	411 US \$
Selling price in domestic industry	450 US \$	450 US \$
Export price	437.06 US \$	--
		FOB Korea

(ii) The company has also stated that they exported Phenol as under during the last 3 years.

1996	2009 MT
1997	4351 MT
1998	9801 MT
1999	NIL

(f) Taiwan Prosperity Chemical Corporation

(i) Their exports of phenol to India from 1996 to 1998 were 3069 MT, 3519 MT & 999 MT respectively. Their orders are only shipped a few times per year, and that

the total quantity of phenol shipped in 1998 has significantly decreased, from 3519 MT in 1997 to only 999 MT in 1998 and that they have no agent in India.

(ii) They started producing Cyclohexanone, which required phenol. Because their own phenol production is sometimes inadequate to meet this new demand, they need to import phenol. Since their own production is currently insufficient for their needs, they cannot aggressively export phenol.

(iii) Taiwan Prosperity Chemical Corporation has always operated with high ethical standards and has earned a good reputation in Taiwan. The management of the company strongly believes that a moral integrity is required in all aspects of business. As a result, their company has always respected and obeyed laws and regulations of the authorities in Taiwan. In dealing with foreign companies they also fully comply with the laws and regulations set by the foreign authorities. During the course of doing business with companies trading in phenol in India, they have abided by the relevant laws set by government.

C. VIEWS OF THE EXPORTING GOVERNMENTS

(a) U.K.

The Department of Trade & Industry, London through the British High Commission, New Delhi had stated that there was currently no British interest in the Phenol market in India and they have no official objection to make, to the initiation of Safeguard investigation against increased imports of Phenol into India.

(b) Japan

Recent increase in the import of Phenol to India is due to the increase in domestic demand which exceeds domestic product capability. The domestic consignment from domestic producers has not experienced major change. A sharp decline in the export by Indian domestic producers can be understood to have been caused by their lack of price competitiveness after the recent drastic drop of international price. Therefore, it is not necessarily clear whether sufficient ground persists to establish causal link between the sharp rise in imports and "threat of serious injury to domestic industry". In any case, the imposition of safeguard measures should be understood akin to *droit de nécessité* and should not be abused. If a safeguard measure were to be introduced, it should meet the prerequisite stipulated in WTO Agreement, and its extent of necessity and period should be construed strictly. Should a safeguard duty be imposed, it would affect not only the users of the product concerned, but also the industry as a whole. Japan would like to observe future measures by the Government of India, with serious interest.

D. VIEWS OF THE INDIAN ASSOCIATIONS

The following main points have been made by some of the Trade Associations and ICMA.

(a) Indian Chemical Manufacturers Association, Mumbai

(i) Hindustan organic Chemicals Ltd. and Herdillia Chemicals Ltd. are members of ICMA and they have requested for restoration of customs duty on Phenol to peak level duty on chemicals. Their request was considered favourably in the Trade & Business Development Expert Committee meeting and they have recommended to the Govt. of India that the customs duty on Phenol should be restored to peak level duty on chemicals.

(ii) Phenol consistently attracted maximum rate of customs duty applicable for chemical products for the last 3 decades. However, during the last 4 fiscal years, duty on Phenol was fixed at a lower level. In the Union Budget 1998-99, basic customs duty on Phenol continued to be lower (at 25%) than on other chemicals (by and large at 30%).

(iii) Phenol is manufactured after number of stages of processing from building block stage (Benzene and Propylene). With liberalisation, import duty on Benzene and Propylene have been reduced to 10%. Despite this, in the past few years the differential between customs duty on Phenol and its importable feedstock benzene has come down from 70% to 15% which has led to serious erosion of the value addition potential available to domestic manufacturers.

(b) Laghu Udyog Bharti, Faridabad

(i) It is a fact that Phenol is manufactured in India by Hindustan Organic Chemicals Ltd. (HOC) and Herdillia Chemicals Ltd and both these manufacturers have monopoly. They should be governed by Monopoly Act.

(ii) It is absolutely false that a serious injury has been caused to the domestic producers by the increase in imports of Phenol into India.

(iii) The increased imports of Phenol have not caused serious injury to the domestic producers of Phenol. As a matter of fact both the manufacturers enjoyed monopoly in this business and they increased the price of Phenol by creating artificial shortage as and when they desired. The shortage of Phenol was manipulated and Phenol was sold at a very high price.

(iv) There was no justification in initiating of any safeguard against import of Phenol into India and there is absolutely no ground for imposition of safeguard duty on import of Phenol.

(v) An inquiry as to why the shortage of phenol is created and then phenol is made available at a premium ranging from 25% to 50% by the domestic producers should be initiated.

(c) The Institute of Indian Foundrymen, Calcutta

(i) They represent more than 6000 foundries in the country. In the last 50 years foundries were starved of Phenol and the prices were increased as and when the manufacturers wanted. The manufacturers also created artificial shortage using special methods. There is no justification of levying safeguard import duty etc on Phenol imported into India.

(ii) This was for the first time in 50 years that during last two months the Phenol price has decreased and the manufacturers had to contact the consumers otherwise it was always the consumers who were knocking the doors of the manufacturers. Therefore, there was no justification of imposing any additional import duty on Phenol even when the present market price which the manufacturers are charging is higher than the international price of Phenol.

E VIEWS OF IMPORTERS/USER INDUSTRIES

They have made the following main points:

(a) **Indian Core Oils Pvt. Ltd., Faridabad**

(i) They are the consumers of phenol and manufacture various types of resins based on phenol.

(ii) It is a fact that phenol is manufactured in India by Hindustan Organic Chemicals Ltd. and Herdillia Chemicals Ltd. and both these manufacturers have monopoly. They should be governed by Monopoly Act.

(iii) It is absolutely false that a serious injury has been caused to the domestic producers by the increase in imports of phenol into India.

(iv) They are manufacturing resins to be used by foundries. These days the foundries have started importing resins and many of the big foundries are not buying resins from Indian manufacturer because they find it cheaper to import. It is a fact the prices of raw materials of chemicals required to manufacture Phenol, Formaldehyde, Furan resins etc. are much cheaper abroad. For example, Methanol, the basic raw material required is sold at less than US \$ 90 per MT where as the price of Methanol in India is more than 200 Dollar per MT Same is the situation for other solvents required to manufacture resins

(v) There was absolutely no justification for increase in the duty on imports of raw material like Phenol.

(vi) The increased imports of Phenol have not caused serious injury to the domestic producers of Phenol. As a matter of fact both the manufacturers enjoyed monopoly in this business and they increased the price of Phenol by creating artificial shortage as and when they desired. The shortage of Phenol was manipulated and Phenol was sold at a very high price.

(vii) An inquiry as why the shortage of phenol is created and then phenol is made available at a premium ranging from 25% to 50% by the domestic producers should be initiated.

(b) **Kesar Petroproducts Ltd., Mumbai**

(i) They are the largest consumers of Phenol in India manufacturing Bisphenol-A. Phenol is the main raw material alongwith Acetone for manufacturing Bisphenol-A.

(ii) Imposing of Safeguard duty would benefit only two manufacturers viz. M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd. and M/s. Herdillia Chemicals Ltd. These two manufacturers are enjoying monopolistic position and have been increasing the price

in unison with each other on regular basis which is detrimental to interest of users of Phenol and national economy, as such, undesirable increase in Phenol prices due to monopolistic position would result in lower production and revenue to nation.

(iii) Normal imports of Phenol in country is around 10000-15000 TPA. This year the imports have somewhat increased due to local manufacturers having shut down their plant for 2 and 1/2 months which resulted in increase in imports to around 25000 Mt.(from normal annual imports of 15000 MT).

(iv) International Prices of all chemicals i.e. Benzene, Cumene, Acetone and Bisphenol-A have been substantially reduced due to demand and supply gap and recession in South East Asia and Phenol prices are no exception.

(v) Demand of Phenol in India is increasing due to the fact that Phenol is the main Building Block for Chemical Industry. Hence any increase in Phenol prices will very adversely affect the other products of Phenol-Chain.

(vi) Imports of Phenol in last quarter of 1998 has increased due to local manufacturers' reluctance to reduce the prices based on Imported landed cost at the right time. They have reduced the prices only after large quantity of Phenol have been imported in the country. Now, HOC has also started offering the price matching to international rates and they have entered into a contract with them for supply of 1000 Mt Phenol during Jan-March 99

(vii) During May-July 98 local manufacturers had created shortage of Phenol, even though the international prices were lowered, they had increased the rates of Phenol.

(viii) Consumers of Phenol were compelled to import Phenol as the local manufacturers did not pass on the benefit of reduction in their input costs. Whenever there was any reduction in price of their raw materials viz. Benzene, Cumene or reduction in duty, the benefit of the same was not passed on to consumers of Phenol. This monopolistic attitude in delaying the reduction of prices have attributed to larger quantity of imports which could have been avoided by them.

(ix) Inefficient plant has been set up by local manufacturers during 1970 and 1980 with old technology and small capacities, whereas international plant capacities of 100,000 TPA with better technologies achieving economical scale of production.

(x) For the local industry to survive in the domestic and international market, Phenol consumers should get goods at international prices.

(xi) Imposing any Safeguard Duty on Phenol, definitely injure the consumers of Phenol and in turn the Chemical Industry at large.

(xii) It is evident from the information provided by the petitioners that there is apparently dumping of phenol in the Indian market and Director General (Safeguards) was prevented from proceeding further in the matter by virtue of the Rules.

(xiii) The applicants consume phenol captively also and the facilities available with them to that extent are not available for the merchant market and should be excluded from the capacities of the applicants to cater to the demand in the country.

(xiv) Since phenol and acetone are joint products, it would not be appropriate to assess injury to the domestic industry for phenol alone without assessing position with regard to acetone. Profitability of acetone needs to be considered while examining the serious injury to the domestic industry.

(xv) The notice of initiation states that domestic industry has requested for duty for a period of two years. This is contrary to the request made by the petitioners.

Petitioners have requested for imposition of duty for three years extendable at the end of three years.

(xvi) There is no evidence of the imports of phenol claimed for the period April-December 1998 and are unauthenticated. A mere statement of imports on a piece of paper prepared by the company does not constitute an evidence and in the absence of full information raises doubt about the authenticity of information furnished by the applicants. The applicants have also quoted different figures of their closing stock which was within their control.

(xvii) Steep decline in share price has been argued as an indicator of serious injury. If share prices are an indicator of serious injury, the entire Indian industry is seriously injured. The entire case of the petitioners seems to be deteriorating profitability and losses in December 1998. Net loss in one month and deteriorating profitability cannot be described as serious injury.

(xviii) Import of Phenol for those goods going in for export promotion (protection) can not be claimed as imports affecting the petitioners. No duties are chargeable on such imports. Such goods are said to have not entered the Commerce of the country. Import of Phenol for export purposes should therefore, be excluded. In case these imports are excluded, it would be evident that the imports have not increased at all.

(xix) HOC's profitability is under pressure due to high interest cost and depreciation on account of its recently completed projects, viz Chloro Alkali and Hydrogen Peroxide. These diversification projects involved substantial capital expenditure relative to the size of the existing operations of the company and were funded mainly through debt. These investments are yet to produce positive cash flows and has a significant impact on the company's overall financial position.

(c) **Marvel Thermosets Pvt. Ltd., Mumbai; and**

(d) **Romit Resins Pvt. Ltd., Panvel, Maharashtra**

(i) They are Small Scale Industrial Unit manufacturing Phenol Formaldehyde Resins being used for Thermosetting and Cold Setting binding in Bakelite, Laminates, Plywood, Grinding Wheels, Refractory Bricks, Cork, Foundries etc. This basic organic thermosetting binder is manufactured from Phenol.

(ii) Presently it is a known fact that on an average, 20,000 tonnes of Phenol per year is being imported into India since 1995-96, which is steady constant import

(iii) Imported Phenol is a source of checking basic price of indigenous manufacturers of Phenol.

(iv) The Indian manufacturers of Phenol shut down their manufacturing plants of Phenol twice in a year for maintenance of their machinery which appears to be technically necessary. However, shut-down of Phenol manufacturing plants but at the same time raising its prices shows arm-twisting tactics of the manufacturers

(v) Price revision of Phenol is done by the Indian manufacturers at their will. This affects the S.S.I. Units as the yearly or half-yearly orders or tenders are finalised in advance which is a commitment and any increase in the price of Phenol increases their burden and leads to losses in the year

(vi) In 1998-99, the domestic production of Phenol upto December'98 is shown as 48703 Ton and is claimed as declined compared to the figure of 1997-98. If 48703 tons are produced in 9 months period, the figure for twelve months would touch 65000 tons which is the average production.

(vii) In 1998-99, between June 98 and August 98, the Indian Manufacturers stopped producing and marketing Phenol and simultaneously prices were raised as shortage was created. During this period, the manufacturers of Resin products survived due to imported Phenol.

(viii) By using Phenol, value-added products like Resins are manufactured. The Phenol users' list can be had from the Indian Manufacturing Units which will show the finance and investments made in this Phenol-user line which again is much higher than those made by Phenol manufacturers. Further, more employment opportunity is provided in the Phenol-user line than the Phenol manufacturers.

(e) Foseco India Ltd., Pune

(i) They are one of the leading manufacturers of Foundry Resins and Fluxes in India and supplying materials to all leading foundries and steel plants. These foundries produce specialised castings for core sectors like automotive, railway, thermal power and exports.

(ii) They have been procuring their 100% requirement of Phenol exclusively from the Indian manufacturers - M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd. and M/s. Herdillia Chemicals Ltd. After the Govt. has liberalised their policy, both the Indian manufacturers have been pricing their products based on the price of imported Phenol rather than their own costing. They keep their price Rs.0.50 to Re.1/- per kg higher than landed cost of imported Phenol.

(iii) In the Union Budget of 1998, the duty on Phenol as well as Cumene was reduced. They requested both HOC and Herdillia to reduce the price of Phenol due to reduction in duty on their input cost HOC and Herdillia very clearly told that their pricing was not based on budget, but based on international prices of Phenol and they were denied the benefit which the Govt. had offered to industry.

(iv) The Govt. of India has liberalised their policy and introduced reforms to make Indian goods globally competitive, which would ultimately help to grow the business/export, but both HOC and Herdillia increased the price of Phenol whenever no imported Phenol was in the pipe line.

(v) HOC and Herdillia took advantage of natural calamities. In the month of June 98, devastating cyclone hit Gujarat and all activities at Kandla Port came to a standstill, which only has unloading facilities for imported Phenol. Both the Indian manufacturers knew that in the near future no imports of Phenol will be possible due to the devastating effect of cyclone and they increased their basic price of Phenol to Rs.40/- per kg, even though landed cost of imported Phenol was coming to Rs.33.50 per kg. at that time.

(vi) HOC and Herdillia totally ignored the demand of Indian industries and started profiteering. FOSECO requested not to be unreasonable and to reduce the price of Phenol since the customers will not be able to bear any increase due to the recessionary trend in the market. Both the manufacturers did not even bothered to

give a reply They ultimately reduced their prices when imported. Phenol landed at Kandla Port.

(vii) The automotive sector/steel sector/textile machinery manufacturers are reeling under deep recession and it is not possible to get any price increase from their customers. They have to absorb all the increase due to unjustified price increase by HOC and Herdillia. This situation forced them to look for imports since they had no other alternative.

(viii) They are afraid that once the Govt. imposes safeguard duty, both the Indian manufacturers will again increase their prices and their customers will not be able to give any price increase. Some of their customers had told them that they will import the resin itself in case of price increase because both HOC and Herdillia were likely to increase their price once safeguard duty is put on imported Phenol.

(f) Gargi Huttenes - Albertus Ltd., Mumbai

(i) The manufacturers Hindustan Organic Chemicals Ltd and Herdillia Chemicals Ltd. have not given the true picture, have formed a cartel and played with the price of phenol since last few years.

(ii) They are a small scale industry registered with the Govt. of India, manufacturing Phenol Formaldehyde Resins used in the foundry industry. Their main raw material is liquid phenol. They have their plant located near Herdillia Chemicals and purchase from both M/s. HCL and HOC.

(iii) About 3 years back, phenol was in short supply. Whenever shortage was created, prices were increased. It has been the imported material which has helped the Industry in India to get the material at low cost and also as per their requirement. Both HCL and HOC have always tried to make profit whenever there was shortage.

(iv) The erosion in profitability of HOC and HCL could be due to their efficiency in manufacturing Phenol. This cannot be a reason for increasing Import Duty on Phenol.

(v) They as buyers would like to buy from local sources as it saves time, cost and foreign exchange to the country. But due to the cartel game played by the suppliers, import is the only answer to keep members of the cartel in control and disciplined.

(vi) Phenol Industry in India does not need a safeguard as there is no onslaught of foreign producers.

(vii) The prices were raised by HOC and HCL immediately during the period 3rd June to 24th June 1998 when Kandla had faced natural calamities and most of the storage tanks were destroyed, which can be proved by them with documents.

(viii) Both the Indian manufacturers always shut down their plant at least once a year or twice a year and they abruptly stop supply of Phenol to the customers. They never informed the customers in advance which increased the local prices, as the prices are settled between them. There was no choice but to accept the fresh prices and take delivery of the material.

(ix) Because of the liberal policy of Govt. of India, the foundries can import Phenolic Resins at International prices. Due to high cost of Indian Phenol two of the

M/s. Borden Chemicals, UK have planned to make a break through in the Indian market and already supplied material at lower price to M/s DCM Engg. Ropar; HDC, Calcutta; M/s. Secals, Ranipet and many others.

(g) Atul Ltd., Gujarat

- (i) They are one of the leading manufacturers of Phenoxy Herbicides in India and fourth largest in the world wherein Phenol is used as a major raw material alongwith MCA Acid. Their consumption of Phenol is to the tune of approximately 3000 MT per annum and the products manufactured are exported to various countries in large quantities apart from that sold in domestic market.
- (ii) The two major manufacturers of phenol in the country enjoy a monopolistic situation and have been deciding the price in congruence with each other at regular intervals which is harmful and causing loss to the users of Phenol.
- (iii) The local manufacturers of Phenol are unable to meet the total domestic requirement(on account of various reasons, viz. higher price, artificial shortage, plant shutdown) and therefore quantity of approx.20000MT was imported to meet the requirement.
- (iv) The two local manufacturers have been maintaining their price at a comparatively higher level as against the current international price thereby rendering the imports more lucrative.
- (v) Phenoxy Herbicides are manufactured by many multinational companies some of whom are also manufacturers of the basic raw material - Phenol. They (Atul) have to compete with such companies in the global market and imposition of Safeguard Duty would render their products totally uncompetitive.
- (vi) The expected annual turnover from Phenoxy herbicides (manufactured from Phenol) is to the tune of Rs 45-50 crores. Any increase in Phenol prices would not only adversely affect this business, but also force closure of a large part of their production capacity which caters to the international market requirements

(h) Alta Laboratories Ltd., Mumbai

- (i) They are the manufacturers of Aspirin (Acetyl Salicylic Acid I P.) and Phenol is their basic raw material. Their annual consumption of Phenol is approximately 1400 MT. The price of Aspirin is statutorily controlled by the Govt. under DPCO 1987. Phenol being the main raw material for manufacture of this product, the cost of Phenol has a direct bearing on the price of Aspirin. Due to unusually high price of Phenol charged by indigenous manufacturers during the last three years, they have incurred losses as the selling price is revised by the Government once in three years and the process of getting interim relief is lengthy and laborious. There is always inordinate delay between the escalation in the cost and the revision of price.
- (ii) M/s. Herdillia Chemicals Ltd. were the sole manufacturer of Phenol in the country until the advent of M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd. in the year 1987. Even today there are only two manufacturers in the country and M/s.

Hindustan Organic Chemicals Ltd. controls almost 65% of the total market share. In effect, this is a virtual monopoly situation and it would not be wrong to say that there is a strong price cartel between M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd. and M/s. Herdillia Chemicals Ltd.

(iii) Low production and under utilisation of capacity is a general phenomena applicable to all the major industries in the various sectors of the economy during the last three years. All domestic producers were subject to serious injury as the winds of liberalisation swept the Indian economy and the reduction of custom duties from 200% to 35% further aggravated the situation and adversely affected the market share of Indian manufacturers.

(iv) The emphasis should be on the cost reduction and cost competitiveness rather than maximisation of profits. The quantum of profitability is always subjective and debatable issue. Due to high cost of Phenol, people are hesitant to enter into the production of Phenol based products. In case, the price of Phenol is settled at reasonable level in the long term, the demand for this product would accelerate and as a corollary to this the manufacturers would be able to operate at most beneficial economic scale of operations.

(v) They are not aware of any quantity of Phenol imported into India for less than 410 U.S. \$ per MT. At present the international price is more than 500 U.S.\$ per M.T and the upward trend has already started.

(vi) Fiscal exercise is the annual event and every year, a review is made on the basis of national and international development and the demand for imposing dumping duties for two years is unreasonable and unjustified.

(vii) In case, the request for levy of dumping duties is accepted it will open the flood gates to all other petroleum based chemicals and this disease may also spread to various other manufacturing sectors.

(viii) During the last five years the Phenol manufacturers especially M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd have exported huge quantities to all the countries world over. In the year 1997-98 itself the total export of Phenol was 7675 MT. They fail to understand, that in case the prices of Phenol were unremunerative in the international market, how such a huge quantity of 7675 M.Tons could be exported by the domestic manufacturers.

(ix) It would be wrong for the Phenol manufacturers to make the general statement that profitability is adversely affected due to cheap imports of Phenol. In fact, they have a broad range of many other products. It is accepted fact that due to general slackness in the economy followed by demand recession major manufacturing units in all sectors of economy are facing problems and Phenol manufacturers cannot be exception to this. The cost of Phenol to the domestic consumer is determined not only by the price of Phenol offered by the various foreign suppliers and duty structure, but also by Foreign Exchange Rate which is very volatile and the experts anticipate that the dollar price may go up to Rs.45/- as against the present Rs.42.50/-.

(x) The sluggish growth in export is a cause of great anxiety for the Indian economy and supporting of higher sale price for Phenol would adversely affect the export of Phenol based products. In other words the cost competitiveness would be lost in the international market.

(xi) They strongly feel, that in case the request for imposition of Safeguard Duty is acceded it would amount to retracting from the globalisation of Indian Economy and would lead the manufacturers of Phenol to disintegrate from international market. The Government therefore, should not take any hasty step which would pose a threat to the new liberalisation policy.

(i) Winlam Industries Ltd. Calcutta

- (i) They are a leading manufacturer and exporter of decorative laminate in Eastern India and have requested for quashing the demand for imposing anti-dumping duty on phenol.
- (ii) Imposition of anti-dumping duty will help only the local manufacturers at the cost of general consumers
- (iii) They have observed in the past that when there were no imports, the local manufacturers increased their prices substantially. Moreover, such high are also contrary to the healthy environment of business and promotes monopoly and high price regime.
- (iv) Import of Phenol at low price makes Indian Product competitive in the international market and thus earns precious foreign exchange.

(j) Andamans Timber Industries Ltd., Calcutta

- (i) They have come to know that Govt. was planning to impose 72% Safeguard duty against import of Phenol into India.
- (ii) They are not in favour of such imposition, since it will only help the local suppliers to increase prices substantially as they have done in the past when there were no imports.
- (iii) Imposition of such high duties are contrary to the healthy environment of business and promotes monopoly and higher price regime
- (iv) Domestic prices are very high and imports are actually benefiting the local industrial consumption of Phenol.

(k) Wonder Laminates Pvt. Ltd., West Bengal

- (i) They have come to know that there is a proposal to impose anti-dumping duty/safeguard duty against import of Phenol into India for a period of 3 years
- (ii) They as a major importer of Phenol are not in favour of such imposition of duty
- (iii) It will help only the local manufacturers like HOC and HCL to increase their prices substantially as it was their regular practice whenever there was no import.
- (iv) Imposition of such high duties are contrary to the healthy environment of business and promotes monopoly and higher price regime.

(l) Kiran Trading Company, Calcutta

- (i) They have come to know that there is a proposal to impose anti-dumping duty/safeguard duty against import of Phenol into India for a period of 3 years.
- (ii) They as a major importer of Phenol are not in favour of such imposition of duty

(iii) It will help only the local manufacturers like HOC and HCL to increase their prices substantially as it was their regular practice whenever there was no import.

(iv) Imposition of such high duties are contrary to the healthy environment of business and promotes monopoly and higher price regime.

(m) **M/s. ABC Products Ltd., Calcutta; and**

(n) **M/s. Kitply Industries Ltd., Calcutta**

(i) Policy of Liberalisation & Globalisation is irreversible. As per the agreement with WTO, Custom Duty has to be reduced to the accepted level. Having brought down the duty from 85% in 1992-93 to now 25%, any increase in the duty under the guise of Safeguard Duty is nothing but backtracking from the accepted policy.

(ii) From the information provided by the Director General's (Safeguard) Office, it is clear that demand for Phenol in India has been always more than the domestic capacity. This is even after accounting for the exports of Phenol made by the domestic producers. Thus, import of Phenol is inevitable even if international prices of Phenol are higher than the domestic price

(iii) It is surprising that the existing plants even at 85-90% capacity utilisation can not break-even. Taking advantage of the huge trade barrier, Indian Manufacturers opted for easier route of keeping domestic prices higher than global prices. Prudent route for the existing manufacturers should have been to increase plant efficiency and upgrade capacities. Existing Manufacturers themselves admit that the cost of production of Phenol can be reduced by Rs.4/- to Rs.6/- per kg. It is unfortunate that even now they are lobbying for easier route of safeguard duty rather implementing cost reduction measures.

(iv) While 12% return of Capital in such recessionary trend itself is unreasonable, even the assumption of Rs.53 crores of Investment in Phenol plant by M/s. Herdillia is not acceptable. These plants are more than 15 years old and are already fully depreciated. Incidentally, this was the time when the trade barrier of 30 to 85% duty was available to them. Surely, enough profits would have been made in the earlier years of the plants, more so when the domestic demand was more than the production capacity. With fully depreciated plants, there is no justification to ask for any safeguard duty.

(v) It is true that in the year 1998, the phenol prices globally has come down significantly. But this can be considered only a short-term phenomena. Phenol prices do fluctuate from year to year quite substantially. This year's lowest price can not be considered as the basis for working out the landed price.

(vi) In order to prove wide difference between the so called reasonable price and landed price, the cost of clearing and forwarding has been shown too low. As against the CNF cost of Rs.510/- per MT, the present clearing and forwarding costs is between Rs.1200/- to Rs.1500/- per MT. Further, the importer also incurs L/C opening cost (upto 1.25% of value), inventory cost (large quantity has to be imported at a time), storage cost (tank rent is Rs 165/- per MT per month), exchange risk cover cost, extra custom duty on high seas sales margin, etc. At least Rs.1500/- per MT must be added to the landed cost worked out by M/s. Herdillia Chemicals Ltd

(vii) The domestic manufacturers are silent about the advantage of negligible custom duty on raw materials of Phenol. They should take the advantage of reduced duties and thereby reduce their own costs instead of demanding safeguard duty.

(viii) Many of the users of Phenol manufacture value-added products for exports. Even, with the trade barrier of duty (25% CD + 10% Surcharge), if the domestic manufacturers are not able to break-even, it is better that such units are allowed to close down rather than passing on their inefficiency to the users of Phenol and in turn, making them uncompetitive in the International Market.

(o) Schenectady Specialties Asia Ltd., Mumbai

(i) They are joint venture company between Schenectady International Inc (SII) of USA (the world's largest manufacturer of Alkylated Phenols) and Sunshield Chemicals Ltd. (SCC) a listed company manufacturing speciality chemicals. They manufacture with the state-of-art technology widest range of Alkylated Phenols which finds its use in various vital and core sectors.

(ii) Phenol is the basic raw material, accounting for 50% of their raw material input for manufacture of Alkylated Phenols, and its purity, reliable quality and competitive prices are of utmost importance to the successful quality production of their products.

(iii) Phenol which is available indigenously contains moisture upto 1000 PPM and moisture is the biggest enemy to manufacture of Alkyl Phenols.

(iv) Alkyl Phenol are readily available from plants outside India at very competitive prices based on international prices of Phenol. If there is any increase in cost of Phenol in India because of increased Import Duty and consequential increase in price of Phenol by the local manufacturers it will destroy the Indian Alkyl Phenols manufacturing sectors. In fact, FICOM Organics and Hico Products could not withstand the competition and have virtually remained inactive manufacturers' of Alkyl Phenols.

(v) Besides Phenol, Herdillia Chemicals also manufacture Alkyl Phenols and if they get an opportunity to hike the price of Phenol it will no more remain viable to manufacture Alkyl Phenols in India by others. In such a situation, the Alkyl Phenols Industry will become a total monopoly of Herdillia and end product industry such as Surfactants, Antioxidants which go in Agriculture, Textiles, Pesticides, Plastics, Food and many more industries producing day to day necessities of Indian public will also become cost inefficient.

(vi) The Government needs to consider very carefully whether Safeguard Duty should be imposed on Phenol. If the Safeguard Duty is to result into increased price of Phenol by the local manufacturer, it will destroy Alkyl Phenol industries.

(vii) The problems of import are by themselves a benefit for local Phenol manufacturers like Herdillia and HOC because of which the user industry is agreeable to pay a little more price than the landed cost of Phenol

(viii) There are constraints in importing 100% pure Phenol due to its melting point; requirement of Special Sea Worthy Tankers; Heated Road Tankers; Heated Storage Tank at the port of Import

- (ix) The higher cost is due to higher Ocean Freight, Storage Charges, port to factory gate freight and besides Special Additional Customs Duty (SAD).
- (x) The present capacity of the Indian manufacturer to manufacture Phenol is about 70,000 tonnes (45,000 tonnes - HOC and 26,500 tonnes - Herdillia) and the requirement in India is about 100,000 tonnes. In light of the above, there is bound to be import of Phenol and it will not affect domestic manufacturers if they can maintain prices at international level plus a little more than they get because of infrastructural cost of import of Phenol.
- (xi) Request of Herdillia and HOC to levy Safeguard Duty on 100% solid Phenol should not be accepted.
- (xii) If manufacturers in Asia and Europe, USA who have smaller capacity plants and they are able to compete in the world market, why should Indian Government protect only 2 manufacturers in India, namely Herdillia and HOC by giving them a special Safeguard Duty.

(p) United Metachem Private Ltd., Pune

- (i) They are a small scale Industry manufacturing supplying Phenol-Formalene Resins (P.F. resins) and Flux to Automobile Industry, Foundry, and Steel Industries, all over India
- (ii) They are procuring requirement of Phenol either from Hindustan Organic Chemicals Ltd. or from Herdillia Chemicals Ltd. Their sister concern Ajay Metachem Ltd. is having export, and Phenol is purchased from Hindustan Organic Chemicals Ltd. against advance license.
- (iii) Consequent to reduction in import duty on inputs they requested HOC and Herdillia to reduce the price of Phenol as their input cost is reduced and were informed by them that their price is based on International prices of Phenol, and has nothing to do with the import duty.
- (iv) The basic price of both the companies is always same.
- (v) HOC and Herdillia increased the price in June and July and took advantage of natural calamities in Kandla port. It may be recalled that during June and July, the operation at Kandla port which has unloading facilities for imported Phenol came to a standstill due to devastating floods in Gujarat.
- (vi) The manufacturers knew that in near future, no imports of Phenol will be possible due to devastating effect of Cyclone and they increased the price of Phenol to Rs.40/- per kg. even though Landed cost of imported Phenol was approximately Rs.33.50 per kg. at that time.
- (vii) Instead of helping the Indian Industries by supplying the material at the same rate, the HOC and Herdillia took advantage of shortage of material in market and increased the price, which resulted in great hardship to their Industry
- (viii) In case the imported Phenol is made costly either by increasing the duty or by levying anti-dumping charges, their Overseas buyer will not accept any increase in cost of finished product, which will result in stoppage of export. Government of India is encouraging export, and if the export is stopped, it will be against the policy of Government of India.

(ix) They are afraid that once the Government imposes safeguard duties, both the Indian manufacturers will again increase their prices and it will not be possible for them to absorb the increase in cost of Phenol.

(x) In case, the prices of Phenol goes up, the cost of imported P.F. Resin will be less than that manufactured by them and customers will prefer the imported PF resins and stop purchasing from them.

(q) Farinson Pharmaceutical Gujrat Ltd., Vadodara

(i) They manufacture bulk drug Paracetamol through Phenol route. Phenol constitutes approx. 30-35% of their Raw Material cost. More than 40% of their production is exported globally and any imposition of additional duties will jeopardise their exports.

(ii) They have long term commitments and prices are based on the prevailing international prices and the present duty structure.

(iv) They are facing severe competition from China and with stringent approval norms announced by the EEC, the Indian exports are badly affected and any increase in duty will severely affect their exports. Due to restrictions of import of Acetic Anhydride against the QABAL based licenses, they have to carry out exports under DEPB scheme which does not permit duty free imports.

(iv) The applicants have enjoyed monopoly during the controlled regime and have opportunistic track record and hence are not favoured by bulk consumers of Phenol.

(v) The domestic prices are controlled by their cartel and the consumers have been severely affected in the past because of their monopolistic attitude and artificial price hikes.

(v) More or less, their imports are export oriented and the safeguard measures are uncalled for if exports are taken into account.

(vii) In the past Phenol was also being imported by the petitioners against the export of value added products by them.

(viii) They sincerely wish and endeavour to promote Indian Manufacturers but experience with both Herdillia and HOC has left them with no other option but to import Phenol. On one hand, Phenol was being imported in the country while at the same time HOC and Herdillia were exporting Phenol at much lower prices than prevailing in the International Market. The prices offered on deemed export basis to local exporters were much higher with stringent credit terms and conditions.

(ix) Any imposition of safeguard duty will start a wrong precedent and will be against the basic notion of free trade. In the globally competitive economy, the inefficiencies are to be shrugged off if one has to survive. The Industry will have to learn to adjust to the globally competitive world and it is only the efficient and fittest who will survive.

(r) C.J.Shah & Co., Mumbai.

(i) They are one of the bulk importers of various solvents and chemicals in India and have been regularly importing Phenol into India.

(ii) They have been regularly importing Phenol for actual users from Japan, Korea, USA etc., and that their prices are more or less competitive compared to local material and to the best of their knowledge, no foreign suppliers are dumping the material into India.

(iii) They feel that the proposed imposition of Safeguard duty on Phenol into India is totally unwarranted and if the same is implemented it will have adverse impact on the Indian economy which is already in bad shape.

(iv) The locally available phenol is inadequate to meet the ever increasing demand from the end-users and this is being taken care of by imported material, the price of which is more or less the same as compared to locally available material. In case the proposed Safeguard duty is implemented, it will not be economical to import this item and the production activities will come to a stand still as the local manufacturers will not be able to cater the entire needs of the end-users.

(v) In case the proposed imposition of Safeguard duty is implemented, it will not be economical to import this item and automatically the price of indigenous material will go up and accordingly the end-users will be compelled to jack up the price of their products. This will put additional burden on the Indian economy.

(vi) In case of any shut down of the local manufacturer's plant due to technical or other reasons, and if there is no import of Phenol into India, the end-users of Phenol will have to shut down their plants for want of material which will have adverse impact on the economy, which in the past has happened.

(s) **M/s. Kantilal Manilal & Co., Mumbai**

(i) They have been importing Phenol into India from various Overseas sources and serving various customers. The prices prevailing internationally has been regularly coming down during the course of this year, which is in relation to the steep fall in the key raw material prices like Benzene/Cumene.

(ii) The Indian import duty is already very high compared to most of the countries in the World and despite this difference, the imports are regularly coming due to competitive nature of the terms offered by the overseas suppliers.

(iii) In case these imports are curbed, a lot of Industries, who are consuming Phenol as one of their key inputs, may suffer in term of their competitiveness and may also become uncompetitive while looking at the global market. It is also clear from the demands/supply situation that both local makers are not in a position to meet the 100% demand in the country and if any higher duty is imposed, it will cause damage to the competitiveness of the downstream products.

(iv) The market forces should be allowed to take care of the demand/supply situation and allowing the consumer to source their raw material from the most competitive areas/suppliers.

(t) **Haresh Kumar & Company Mumbai**

(i) The consumption of Phenol is much higher compared to local capacity of mainly two producers i.e Hindustan Organic Chemicals Ltd. and Herdillia

Chemicals Ltd. The gap between the demand and supply has led to the increased imports. It may also be noted that the domestic sale of the local manufacturers has not decreased in 1998-99 compared to the earlier year. In fact the exports of HOC has decreased by almost 7700 MTs which might have forced them to decrease their production.

(ii) The exports of finished products manufactured from Phenol such as Laminates, Pharmaceutical Bulk Drugs like Paracetamol, Aspirin, Pesticide and Agro Products have increased.

(iii) The major import is still against duty free and is one of the reasons for the increased import of Phenol.

(iv) Few major importers who have imported Phenol against advance license along with their consumption are as under:

Mitsui Industries Ltd. and	2500 Mts
Hindustan Inks & Resins Ltd.	
Century Laminating Co. Ltd.	1800 Mts
Atul Limited	2000 Mts
Kesar Petroproducts Ltd.	3000 Mts
United Phosphorus Ltd.	300 Mts
Farmson Pharmaceuticals Guj Ltd.	1500 Mts
Other laminate manufacturers such as Meghdev & Milton Laminates	3000 Mts
Misc. Importers against duty free	2500 Mts

The duty free imports is more than 50% of the total imports which is approximately 23000 Mts on annualised basis

(iv) The other main reason for increased imports is due to monopolistic situation created by the two manufacturers. At times they have increased the price without intimation taking advantage of the monopoly situation. For example in June 1998 during cyclone at Kandla (almost 100% of the quantity is imported at Kandla) imports and deliveries were suspended until August 1998. Both the manufacturers increased their price sharply whereas the price of their imported Cumene were unchanged or dropping. (Phenol manufacturers imported their raw material i.e. Cumene at Mumbai/Mangalore). They took the advantage of their monopoly during cyclone increasing their price from Rs.35/- per KG in May'98 to Rs.40/- per KG in July'98 till the imports/deliveries from Kandla re-started.

(v) Quality of Phenol is not of international standard for few end users who export their final product like Bisphenol-A. They have to rely on imports.

(vi) Inconsistent deliveries and sudden upward price revisions have forced the Phenol users to import as they are left with no alternative and have lost the confidence in indigenous manufacturers. Manufacturers have invariably delayed the deliveries of the material, increased the price even after the delivery order was issued. (Price is subject to change at time of delivery) as a result of which the Phenol users were put to hardship, creating uncertainty on the final cost of their finished products, because of upward price revision by the Phenol manufacturers.

(vii) The increase in imported Phenol is not because of lower international price. In fact the prices of both i.e. Phenol and its raw materials has dropped. Also the duty on Phenol is much higher 30% as compared to duty of 15% on Cumene/Benzene.

	CIF 97-98	CIF 98-99	Duty
Phenol	690	400	30%
Cumene	475	275	15%
Benzene	280	210	15%

From the above figures of international prices/duties it is quite evident that local manufacturers are getting a better price realisation and as such there is no threat against imports.

(viii) Based on the raw material price and other cost they are achieving a value addition of approximately 60% which is quite higher than the normal value addition. Even the other major Phenol plants world over with much higher capacity and low over run do not achieve such higher value addition.

(ix) It may be noted the phenol division of both manufacturers are making good profit inspite of old plants, higher run-over cost etc.

(x) From the stock statement of domestic producers they carry inventory of 2000-3000 MTs which is not even 5% of their annual production and 3% of total consumption. The stock position itself suggest that they have no difficulty in their sale/price realisation and as such there is no threat against imports which is only covering the demand and supply gap.

(xi) Imposition of safeguard duty would lead to a total monopolistic situation which shall pose a serious threat to the several domestic industries.

F. VIEWS OF DOMESTIC PRODUCERS

The domestic producers have made the following main points:

(a) **M/s, Hindustan Organic Chemicals Ltd., Cochin.**

(i) They have their manufacturing units at (1) Rasayani-410027, Distt. Raigad Maharashtra (2) Ambalamugal-682302, Distt. Ernakulam, Kerala and Phenol plant is located at Ambalamugal only.

(ii) They manufacture Basic Organic Chemicals namely Phenol also known as Carbolic Acid or Hydroxy Benzene, Acetone, Aniline, Nitrotoluenes, Nitrochlorobenzens, Monochlorobenzene, Formaldehyde, Nitrobenzene, Sulphuric Acid, Cyclohexylamine, Acetanilide, Caustic Soda, Hydrogen Peroxide, Butene-1, 4-Diol.

(iii) Phenol manufactured by them, both Crystal and Hydrated form, is used in the manufacture of Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Pharmaceuticals, etc. In the manufacture of Leather Chemicals, Bisphenol-A and Alkyl Phenols only Crystal form of Phenol is used

(iv) Benzene and Propylene are the major raw materials while Cumene is an intermediate in the manufacture of Phenol. Acetone is formed as a co-product in the manufacture of Phenol. Phenol and Acetone are formed in the ratio of 1:0.6.

(v) Their product has similar qualities and characteristics as of imported product.

(vi) Their present cost of production of Phenol is in excess of Rs.25,000/-Ton. The indigenous selling price is governed by the landed cost of imported Phenol.

(vii) Even when total domestic demand of Phenol has improved over the years their capacity utilization has come down due to abnormal increase in imports causing injury to their unit.

(viii) There was a sharp fall in prices of imported Phenol during 1998-99 resulting in steep fall in domestic prices.

(ix) According to current Union Budget 1999-2000 Customs Duty on Phenol has been further reduced from 25% + 5% to 25% + 2.5%. Thus, making imported Phenol cheaper by about Rs.420/- MT. Present landed cost including Customs Duty works out to be about Rs.22,000/-MT.

(x) Increased imports will lead to lower capacity utilisation. This will also result into losses due to increase in cost of production and poor sales realisation. The unit which remained a healthy unit for a long time and provided Phenol to consumer industry consistently will turn to loss making unit and may become unviable.

(xi) Whereas the cost of production has been by and large increasing over a period of time, the domestic prices (which are a function of international prices (CIF India), import duty and the exchange rate) have had to be by and large either held stable or drastically reduced (as has been done of late) in order to maintain the market share, because if the market is once lost, it would be very difficult to regain the same, which has led to compression of margins.

(xii) CIF India Phenol prices, which used to be in line with the prices in other parts of the world, have come down more drastically than in other parts of the world like U.S.A. Europe and Far East. Whereas the drop in USGC (US Gulf Coast) prices has been to the extent of USD 110/Ton till end September'98 (from USD 716/Ton in Jan. 1998 to USD 606/Ton in Sept. 1998, a drop of 15.36%), the drop in CIF India prices has been more drastic at USD 275/Ton (from USD 715/Ton to USD 440/Ton, a drop of 38.46%, for the same period). The CIF India prices have dropped further till end December to USD 395 per Ton (an overall drop of 44.75%).

(xiii) In view of economic crisis in other parts of Asia, overseas Phenol producers look at the Indian market as a safe and lucrative target because of the reliability of Indian banking system and the consequent payment security. As a result, they are willing to sell to India at very low prices.

(xiv) The prices to India are at a discount of around USD 70/Ton over the USGC prices for Dec. 1998. This is causing serious injury to the Indian industry, which needs to be safeguarded by a suitable additional levy on imports. In view of the rapid fall in CIF India prices to an all time low in the past 5 years, there is a significant further spurt in import over and above the past three year average of 18500 TPA and there is a further compression of margins equivalent to the compression of landed cost of import over and above current levels.

(xv) Imports equal to 1.63 times of the whole of past year's imports have arrived in a short span of 9 months out of which imports equal to 60% of last years imports have

arrived in the 3rd quarter of 1998-99. Due to these extremely low priced imports, Indian manufacturers will have to reduce their prices (which have already been reduced from Rs.37/kg in January 1998 to Rs.29/kg in October 1998 to the present price level of Rs.28/kg, all prices being list prices) to nearly match the landed cost of import at around Rs.24/kg net of CVD setoff. So far, there is a drop of Rs 9/kg in list prices on a January 1998 level of Rs.37/kg.

(xvi) There has been no corresponding reduction in the raw material prices. In view of this, cost of manufacture remains to be high and profitability is under pressure. Steep fall in realisation and margins is causing serious injury to their unit on the following fronts also (a) Share prices of HOC has come down, and (b) Credit rating by CRISIL has been down graded from AA(-) to A(-) on long term and from P1(+) to P2(+) on short term borrowings.

(xvii) The profit on Phenol sale in bulk condition has fallen sharply since August, 1998 to a loss of Rs 1,198 / Ton in December, 1998 with corresponding drop in gross margins of 63% in a span of just 4 months due to increased imports at lower prices.

(xviii) The increased imports have not only come at low prices but also at long credit to the traders. The additional benefit accruing on this account led to similar demand by the consumers from the domestic industry. The debtors of Phenol increased from 62 days of sales during July, 1998 to 69 days in December, 1998. The lower gross margins, increased stock/inventory and longer credit resulted in reduced cash flows and thereby reducing availability of funds to maintain normal operation.

(xix) There is steep drop in price realisation from Rs. 30,420 / MT in September, 1998 to Rs 24,620 / MT (drop of 19%) in December, 1998 and this was the period when Phenol in substantial quantities was imported at lower prices.

(xx) They sold 3,137 MT of Phenol during April- December, 1998 under Deemed Export Scheme to various end users of Phenol and this will prove that they were export competitive.

(xi) The real injury is going to be caused in the weeks and months that follow. The injury in case of extinction of the Phenol Industry, with its impact on downstream industries and consequent unemployment, will be far beyond.

(xxii) They have been upgrading their technology and debottlenecking manufacturing facilities with the objective of reducing the operating costs per unit and increasing effective capacity to satisfy the increasing domestic demand from most of the sectors. They have recently increased their effective capacity from 40000 TPA to 45000 TPA. To reduce the power cost, they have taken steps to setting up of captive power generation facilities by the co-generation route and gains could start accruing in the current financial year 1998-99. They are planning to set up a World Scale Greenfield Phenol manufacturing facilities either 100000 TPA or 150000 TPA at Dahej at Maharashtra or Gujarat State. There is a possibility of a co-operative effort between HOC and HCL. They intend to become internationally competitive by extending their capacities, upgrade and modernise technology with the help of technology suppliers and consultants.

(b) Herdillia Chemicals Ltd. Mumbai

(i) They manufacture Basic Organic Chemicals and Specialties like Phenol, Acetone, Phthalic Anhydride, Diacetone Alcohol, Dodecyl Phenol, Nonyl Phenol, Diphenyl Oxide, Isobutyl Benzene, Isophorone, Heat Transfer Media, Acetophenone.

(ii) There are two grades of Phenol manufactured by them namely Crystalline and Hydrated. Whereas Crystalline Phenol is solid Phenol in crystal form, hydrated Phenol is a composition of Phenol and water with a percentage of water being less than 10%. Due to this, Phenol remains in molten form even in ambient or cold conditions and simplifies material handling procedure by the end users during unloading. The purity of Crystalline Phenol is minimum 99.5% by weight. However, the billing of Hydrated Phenol is done on the basis of the actual Phenol content in the material.

(iii) Phenol is used in the manufacture of Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide etc. Applications such as Leather Chemicals and Bisphenol-A normally require only Crystalline Phenol.

(iv) The imported Phenol and the Phenol manufactured by them is same in all respects.

(v) The average of cost of production of the first nine months of the present fiscal year and of the previous three fiscal years is Rs.33,900 per MT.

(vi) Phenol facility of 10,000 TPA capacity was set up in the 1960s and became operational in 1968. Initial investment in the Phenol manufacturing facility was Rs.3.31 crores. Over a period of time, the capacity was increased to well over 20,000 TPA till the end of the fiscal year 1996-97 through investments in debottlenecking financed entirely through internal accruals. The present capacity of the plant is 30000 TPA.

(vii) Packing cost for Phenol was around Rs.3.5/Kg. for the year 1995-96, Rs 3.75/Kg (Average) for the year 1996-97, and Rs.4/Kg for the years 1997-98. This is approximately the difference between the net sales realisation of Bulk and packed Phenol. The selling price of Phenol is based on the landed price parity and not on a cost plus basis concept. As a result there is no correlation between the raw material cost and the selling price.

(viii) Whereas the cost of production has been stable or increasing over a period of time, the domestic prices (which are a function of international prices (CIF India), import duty and the exchange rate) have had to be by and large either held stable or drastically reduced (as has been done of late) in order to maintain the market share, because if the market is once lost, it would be very difficult to regain the same.

(ix) CIF India Phenol prices, which used to be in line with the prices in other parts of the world, have come down more drastically than in other parts of the world like USA, Europe and Far East.

(x) Whereas the drop in USGC (US Gulf Coast) prices has been to the extent of USD 110/Ton Till end September'98 (from USD 716/Ton in Jan. 1998 to USD 606/Ton in Sept. 1998, a drop of 15.36%), the drop in CIF India prices has been more drastic at USD 275/Ton (from USD 715/Ton to USD 440/Ton, a drop of 38.46%, for the same period). The CIF India prices have dropped further till end December to USD 395 per Ton (an overall drop of 44.75%).

(xi) In view of economic crisis in other parts of Asia, overseas Phenol producers looked at the Indian market as a safe and lucrative target because of the reliability of Indian Banking System and the consequent payment security. As a result, they were willing to sell Phenol to India at very low prices.

(xii) The prices to India are at a discount of around USD 70/Ton over the USGC prices for Dec.1998. This is causing serious injury to the Indian industry, which needs to be safeguarded by a suitable additional levy on imports.

(xiii) In view of the rapid fall in CIF India prices to an all time low in the past 5 years, there is a significant further spurt in import over and above the past three year average of 18500 TPA and there is a further compression of margins equivalent to the compression of landed cost of import over and above current levels.

(xiv) Imports equal to 1.63 times of the whole of past year's imports have arrived in a short span of 9 months out of which imports equal to 60% of last years imports have arrived in the 3rd quarter of 1998-99.

(xv) Due to these low priced imports, Herdillia had to reduce its prices from Rs.37/Kg in January 1998 to Rs.29/Kg in October 1998 to the present price level of Rs.28/Kg, all prices being list prices. On this, discounts are required to be given for the net price to nearly match the landed cost of imported material. As a sequel profitability of Herdillia is under severe pressure.

(xvi) They acted as a catalyst in the development of a host of downstream industries many of whom were export oriented with assured domestic availability of Phenol

(xvii) During May-June, 1998, they reduced their captive consumption of Phenol by sacrificing production of high value Phenol derivatives to maintain adequate supplies to the consumers.

(xviii) Imports of Phenol have more than doubled during the first three quarters of 1998-99 and during September, 1998 to December,1998 it far exceeded the entire imports made during 1997-98. The imports effected in 1998-99 were even more than the market share of Phenol enjoyed by Herdillia.

(xix) The price realisation for Phenol (bulk) which stood at Rs. 35,772 PMT during April, 1998 reduced to Rs. 24,934 PMT in December, 1998. The profit on Phenol sale in bulk condition fell sharply since August, 1998 to a loss of Rs. 3,298 per ton in December, 1998.

(xx) The decrease in capacity utilisation would be resulting in a substantial increase in the fixed costs per ton of Phenol for Herdillia, thus further shrinking the margins.

(xxi) Due to the large scale Phenol imports at substantially lower costs and long credit periods flooding the Indian Markets, the situation is forcing the domestic manufacturers to offer more credit period to the customers. The debtors have gone up substantially during the past few months elongating the Working Capital cycle finally resulting in a severe cash crunch. As a result Herdillia is finding it difficult to pay to the suppliers on time. They have to borrow funds, as inter-corporate deposits, at rates substantially higher than the prevailing market rate resulting in a further loss of profitability.

(xxii) Herdillia's performance parameters for credit rating have also deteriorated due to low Phenol prices making it further difficult to access funds at reasonable cost.

(xxiii) Due to the liquidity crunch (and the consequent loss of profitability), Herdillia is finding it extremely difficult to access funds from financial

institutions. This is, in turn, resulting in delay of implementation of the long-term plans to build a Greenfield Phenol plant of capacity 100,000 TPA. On the other hand, the quick implementation of this project is imperative for future survival of Herdillia in the emerging economic situation consequent to India's commitments to the WTO.

(xxiv) The import duty on Phenol has been lowered drastically in the past few years whereas the import duty on its raw materials has been reduced by a much smaller margin. The differential between the import duty on Phenol and its raw materials Benzene and Propylene has been steadily narrowing. Moreover, the freight on Propylene is very high (and a significant % of the FOB price) due to it being a gas under atmospheric conditions. Furthermore, Propylene cannot be imported due to absence of adequate facilities at our ports for its handling. Propylene prices to Herdillia are substantially higher than in USA, Europe or the Middle East to add to the hardship.

(xxv) From the available information, it is being felt that the growth in Phenol capacity expected in the coming five years will far outstrip supply. Actually, there is a concern about the future demand supply balance of co-product Acetone also. Based on the new project as well as expansion/debottlenecking plans of the existing/new Phenol manufacturers, 40% additional capacity is expected to come up. Recent and the near future expansions include a majority in Europe including 70,000 TPA of Phenolchemie at Gladbeck, of Caproleuna (70,000TPA), and of DSM (20,000 TPA) apart from 1,50,000 TPA of Ertisa, Spain as has been reported by an international market agency of repute.

(xxvi) Major US projects are still to come on stream and Phenolchemie's Mobil Alabama plant and Shell's investment are still poised to be introduced in the year 1999 as has been reported by an international agency of repute. Kumho and Mitsui are also reported to be active on their plans in Asia, which would mean significant additional capacity in our region in addition to the threat of import from the other continents/regions. Asian Phenol capacity is set to rise with Mitsui Chemicals announcing plans for 200,000 TPA plant. Only the Indian sub-continent with its one of the fastest expected future demand growth and its strategic location vis-a-vis feedstock availability from the Middle East offers best opportunity for a Greenfield Phenol facility in a somewhat longer term than the commissioning of the Mitsui project.

(xxvii) The proposed expansions in global Phenol capacity look broadly on track. This is clearly unwarranted in view of concerns about demand not likely to keep pace with the growth in capacity following the Asian economic crisis. As has been forecasted by one of the globally leading agencies watching the Phenol scenario, the market is headed for a very difficult patch between 1999 and 2005. Prices are expected to continue to remain at very low levels.

(xxviii) Herdillia imports small quantities of Phenol only duty free for the manufacture of Diphenyl Oxide for export.

(xxix) They have taken a number of steps to make positive adjustments to improve competitiveness of their product vis-a-vis the imported phenol.

(xxx) The import figures submitted by them are authentic, taken from various reliable sources

(xxvi) In mentioning the closing stock there has been some clerical error. The closing stock figures mentioned in the Petition are the correct one.

(c) **Neyveli Lignite Corporation, Neyveli**

(i) Phenol also known as Carbolic Acid is manufactured by them as byproduct in Carbonisation process of Lignite Briquettes in Briquetting and Carbonisation Plant.
(ii) Their installed capacity, production, sales and closing stock of Phenol during the year 1995-96 onwards is as under:

(MT)

	Installed capacity	Production	Sales	Closing Stock
1995-96	800	504 210	541 611	109 846
1996-97	800	352 597	419 206	48 805
1997-98	800	835 215	571 007	307 445
1998-99	800	529 002	541 222	295.245

(iii) Phenol manufactured by them is used in the manufacture of various chemical products like Polymers, Bakelite laminates, Resins, explosives, perfumery disinfectants, electrical insulation etc.

(vi) Against the production of 835 tonnes during 1997-98 the production during 1998-99 was only 529 tonnes and the loss of production was 306 tonnes. Fall in capacity utilisation was around 35%.

(v) They have lost nearly Rs one crore because of inventory of 309 tonnes as on 31.3.99. Because of loss of production of 306 tonnes during 1998-99 compared to last year (i.e. 1997-98), the loss of sales realisation is around Rs. one crore.

(vi) At the present price of Rs.34000/- Per Tonne, they are already losing around Rs 2500/Tonne. If one matches the sales price to the imported cost of Rs.24000/Per Tonne, the loss will increase additionally to Rs 10000/Per Tonne. Against the targeted production of 800 tonnes, the additional loss will be around Rs 80 lakhs

G FINDINGS

I have carefully gone through the case records and the replies filed by the domestic producers, users/importers, exporters and exporting governments. Submissions made by various parties and the issues arising therefrom are dealt with at appropriate places in the findings below. However, before proceeding to discuss the merits of the case it is considered necessary to discuss a preliminary issue concerning Service of the Notice of Initiation

(a) **Service of the Notice of Initiation**

It has been alleged that the Notice of Initiation was not served on all interested parties. In this regard, it is observed that the Notice dated 2nd February, 1999 was

published in the Official Gazette of the Government of India on 8th February, 1999 and a copy of the Notice of Initiation was served on all known interested parties whose names and addresses were made available by the petitioners. Paragraph 10 of the Notice specifically provided for any other party to the investigation who wished to be considered as an interested party to submit its representation to the DG. Some parties that were not initially named in the petition did represent to the DG and they were included in the investigation as interested parties. It is, therefore, observed that the requirement of notifying all interested parties as per the law has been met with

2 Product under Investigation

- (i) The product under investigation is 'Phenol', a basic organic chemical with chemical formula C₆H₅OH, also known as 'Carbolic Acid'.
- (ii) Phenol is manufactured out of tar obtained by the destructive distillation of lignite/coal or synthetically by the oxidation of Cumene using air at elevated temperature and pressure. The product is Cumene Hydroperoxide at lower concentration, which is then alkali washed and concentrated to a higher strength. This is then mixed with H₂SO₄, which causes a cleavage reaction to give Phenol and Acetone. This is washed to remove acidity and distilled in a series of distillation columns to give Phenol, Acetone and unreacted Cumene (which is recycled for conversion to Phenol and Acetone). Cumene in turn is produced by the reaction between Propylene and Benzene.
- (iii) Phenol is manufactured in two forms viz. Crystal form and Hydrated form. The melting point of Phenol is 43 degree celsius and unless ambient temperatures are high it is in crystalline form. In hydrated Phenol, a small quantity of water is added to keep the Phenol in liquid condition. However, sale of Hydrated Phenol is based on actual Phenol content i.e. on 100% Phenol content basis.
- (iv) Phenol is used in the manufacture of Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Plastic Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals etc
- (v) Phenol is classified under sub-heading 2907 11 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 and under 29071101 and 29071102 of the Indian Trade Classification (based on Harmonised Commodity Description and Coding System). This classification of Phenol under the Customs Tariff Act, 1975 and the Indian Trade Classification has been indicated for the purpose of convenience and in no way restricts the scope of the coverage of the product under investigation
- (vi) A claim has been made to exclude 100% pure Phenol i.e. Phenol in crystal form because of its melting point and need to have Special Sea worthy Tankers, Heated Road Tankers and Heated Storage Tank at the port of Import. This claim, however, needs to be examined in the light of the fact that Phenol in Hydrated form is obtained by adding a small quantity of water to pure Phenol to keep it in liquid form. The exclusion of 100% pure Phenol would, therefore, defeat the whole purpose. The factors enumerated in favour of exclusion of 100% pure Phenol do not distinguish 100% pure Phenol from the Hydrated Phenol, but only point out towards additional handling requirements and/or the additional costs involved in importing 100% pure Phenol as compared to Hydrated Phenol. This

claim, therefore, has no merit. The present investigation, therefore, covers both Crystalline Phenol and Hydrated Phenol

3 Domestic Industry

The application has been filed by M/s Hindustan Organic Chemicals Ltd., Mumbai (HOC) and M/s Herdillia Chemicals Ltd., Mumbai (HCL), who are the only two producers of Phenol through the synthetic route i.e. through the Cumene route. They have a combined capacity of 75,000 MT (1998-99) of Phenol production. During 1997-98, they produced 69,281 MT of Phenol (capacity 71,500 MT) and in the first nine months of 1998-99, they produced 48,703 MT of Phenol. M/s Neyveli Lignite Corporation Ltd. (NLC) also manufacture Phenol out of tar obtained by the destructive distillation of Lignite/Coal but their production capacity is only 800 MT. HOC and HCL together, therefore, constitute a major proportion of domestic production. NLC although did not join the petitioners in filing the application, they have participated in the investigation and extended their support for imposition of safeguard duty on imports of Phenol. The application by HOC and HCL is, therefore, considered to have been made on behalf of the domestic industry.

4. Increased Imports

- (i) Phenol is imported into India from China, Chinese Taipei, France, Germany, Indonesia, Italy, Japan, Korea DPR, Korea RP, Kuwait, Malaysia, Netherlands, New Zealand, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, United Kingdom and United States of America. Currently, the major exporters of Phenol to India are South Africa, South Korea, Japan and Taiwan. The import duty on Phenol that was 85% in 1993-94 was brought down to 65% in 1994-95, 40% in 1995-96 and to 30% in 1996-97. Initially in 1997-98, the import duty on Phenol was 25% + 2% but later on an additional 3% duty was levied on imports of Phenol. Currently, Phenol attracts import duty @ 25% + 2.5% *ad valorem* excluding Additional Duty of Customs and Special Additional Duty of Customs.
- (ii) In 1994-95 a total of 6664 MT of Phenol entered into India mainly from Japan (2002 MT), Germany (1225 MT), USA (968 MT) and South Africa (1263 MT). In 1995-96, the imports of Phenol rose phenomenally to 21752 MT with major imports from Japan (4767 MT), Taiwan (1048 MT), Germany (638 MT), Netherlands (6731 MT), France (1075 MT), USA (4539 MT), South Africa (1871 MT) and New Zealand (539 MT). The imports during the next two years declined gradually from the high of 21752 MT in 1995-96 to 19545 MT in 1996-97 and to 15352 MT in 1997-98. The imports in the first nine months of 1998-99 (April, 1998 to December, 1998) have been claimed to be 25048 MT by the petitioners including duty free imports of Phenol. M/s Kesar Petroproducts have argued that import of Phenol for use in export production cannot be claimed to be affecting the petitioners. This argument of M/s Kesar Petroproducts is not tenable in as much as whether for domestic production or for export production, whatever Phenol is used constitutes the market for the domestic producers. The quantity of

Phenol imported for use in export production, therefore, needs to be included in the total imports.

(iii) Doubts have been expressed by some parties about the authenticity of import data provided by the applicants, particularly in respect of import data for the period April-December, 1998. It has been submitted that domestic producers who filed the application for initiation of safeguard duty on Phenol on 8th January, 1999 could not have had with them authentic data of imports till December, 1998 and that while the domestic producers have claimed that some imports of Phenol have entered through Goa port, there has not been any import of Phenol at Goa port. The domestic producers in this regard have submitted that the data for the years up to 1997-98 has been taken from the DGCIS, Calcutta. Due to time lag in publication of DGCIS figures, for the first three quarters of 1998-99, they have taken the data based on market intelligence sources. They have claimed that they continuously monitor data on month to month basis through various market intelligent sources like traders (domestic and international), tank operators at ports, importers and exporters and that the import data has been provided by them with adequate details. In regard to the authenticity of the import data, it is observed that the data provided by the petitioners for the period from 1994-95 to 1997-98 is based on the DGCIS statistics and is authentic. As far as 1998-99 (April-December) data is concerned, it is observed that the petitioners have provided details of imports giving name of the Vessel, date of arrival, quantity, port of loading and price in respect of 23,348 MT, 22348 MT imported at Kandla port and 1000 MT imported at Calcutta port. They have also claimed 1700 MT of Phenol to have been imported in packed condition. As regards imports through Goa port, they have categorically stated that M/s Kesar Petroproducts Ltd., Mumbai who had raised doubts about imports through Goa port had themselves imported Phenol through Goa/Mormugao port and HCL had provided expert assistance. It is also observed that no specific discrepancy in the import data for the period April-December, 1998 has been pointed out by any party. However, the import data of Phenol was subjected to verification. Kandla Custom House has confirmed imports of 22028.414 MT of Phenol during April-December, 1998. 1,000 MT of Phenol was imported at Calcutta port and 1521 943 MT in packed condition at various ports. The small difference between figures of imports through Kandla port-22348 MT mentioned by the petitioners and 22028.414 MT confirmed by the Kandla Custom House is due to the difference between the Bill of Lading quantity (relied upon by the petitioners) and Ullage quantity (considered as imported by the Kandla Custom House). M/s Samsung Corporation on behalf of M/s Kumho P&B Chemicals Inc., Korea, have confirmed exports of 9,801 MT of Phenol to India in 1998 as compared to 2,099 MT in 1996 and 4,351 MT in 1997. Verification of some of the importers has revealed that during April to December, 1998 M/s Kesar Petroproducts imported 1683 MT of Phenol, M/s C.J. Shah & Co. 2,487 MT of Phenol and M/s Kantilal Manilal 289 MT of Phenol.

(iv) In view of the above discussions, it is observed that imports of Phenol into India in 1998-99 (April-December) were 24550 MT. Table 1 below gives import figures of Phenol from 1994-95 to 1998-99 (up to December)

Table I

Year	Imports	
	Quantity (MT)	Value (Rs. Mn.)
1994-95	6663.963	130 707
1995-96	21752.174	450 512
1996-97	19545.737	443.566
1997-98	15312.373	380.512
1998-99(April-December)	24550.357	-

(v) The imports thus have increased from 6,664 MT in 1994-95 to 21,752 MT in 1995-96. In 1996-97 and 1997-98, the imports declined as compared to 1995-96 to 19,546 MT and 15,312 MT respectively. On an average during this period i.e. 1995-96 to 1997-98 the quantum of imports of Phenol into India was 18,870 MT per annum (MTpa). In the first nine months of 1998-99, the imports, however, jumped to 24550 MT i.e. an increase by 73.5% over the average imports during 1995-98 on a pro-rata basis. As compared to the immediately preceding year 1997-98, the imports in the first nine months of 1998-99 increased by 113.8% on a pro-rata basis. In comparative terms the imports were 11.53% of domestic production in 1994-95, 34.14% in 1995-96, 34.01% in 1996-97, 22.1% in 1997-98 and 50.4% in 1998-99 (April-December). The domestic production, import figures and imports as %age of domestic production are given below in Table 2

Table 2

Year	Domestic Production(MT)	Imports(MT)	Imports as %age of Domestic Production
1994-95	57780	6664	11.53
1995-96	63719	21752	34.14
1996-97	57466	19546	34.01
1997-98	69281	15312	22.1
1998-99(April-December)	48703	24550	50.4

(vi) The imports have thus increased both in absolute terms as well as compared to domestic production.

(vii) An issue has been raised by M/s Kesar Petroproducts that the initiation notification does not follow a uniform period. The increased imports have been considered since 1994-95 apparently because the imports were quite low in that year and comparatively shows substantial increase in the subsequent years. The market share has been considered since 1995-96 and the production of the domestic industry has been considered from 1996-97. In this regard, it is observed that one of the fundamental requirements for taking a safeguard measure is that the increased imports should be the cause of injury to the domestic industry. The fact of increased imports, therefore, must precede or co-exist with the serious

injury or threat of serious injury to the domestic industry. It is, therefore, necessary to examine the import figures over a period so as to enable a proper appreciation of the fact of increased imports. In the instant case, no undue advantage is conferred on the applicants by taking into account imports of Phenol in 1994-95, which saw a lower quantum of imports as compared to subsequent years. In fact, during the next year the imports of Phenol increased phenomenally to 21,752 MT but thereafter the imports declined to a low of 15,312 MT in 1997-98 before rising again to 24550 MT in the first nine months of 1998-99. As has been observed in the foregoing discussions, the imports in the first nine months of 1998-99 increased by 73.5% over the average imports during 1995-98 on a pro-rata basis and by 113.8% as compared to 1997-98 on a pro-rata basis. This clearly establishes the fact of increased imports without any reference to the quantum of imports in 1994-95. In the present case the existence of threat of serious injury to the domestic industry is to be considered. It is, therefore, obvious that the domestic industry would need to establish a threat of serious injury in the recent period by comparing the present state of affairs of the domestic industry with what was prevailing in the recent past. The issue raised by M/s Kesar Petroproducts, therefore, has no merits.

- (viii) M/s Kesar Petroproducts have also raised another issue in the context of increased imports. They have submitted that the legal provisions are silent as to what constitutes increase in imports in absolute term and that an increase from 100 units to 103 units cannot be interpreted to constitute an increase in absolute terms. They appear to suggest considering only excess imports i.e. excess of imports over shortage in domestic demand and domestic production to determine whether imports have increased in absolute terms. In the context of increased imports, Rule 2(c) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 defines 'increased quantity' to include increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production. The two phrases 'in absolute terms' or 'relative to domestic production' have been used in juxtaposition and derive their meanings from a plain reading of the definition itself. The words 'in absolute terms' clearly refer to an increase in imports in absolute terms e.g. an increase in quantity/number of units. An increase in imports from 100 units to 103 units would, therefore, be undoubtedly a case of increase in imports in absolute terms. The law does not require excess of imports, as argued by M/s Kesar Petroproducts to be considered for determination whether imports have increased in absolute terms. In fact, it would be impractical to imagine, in the wake of imports allowed without any restrictions, that one should like to import more than what is required i.e. 'excess imports' and build up inventory. What the law, therefore, requires is to consider imports in absolute terms and relative to domestic production. Whether the imports have entered because these were needed to meet the demand may be relevant for determination of injury caused by such imports but it is not relevant for the determination of the fact of increased imports. In the present case, as indicated in Table 2, the imports have increased both in absolute terms as well as relative to domestic production.

(a) Domestic Production

An analysis of various factors attributing to the present status of domestic industry reveals that the domestic production was 57466 MT in 1996-97. On an average the domestic production was about 59,655 MTpa during the period 1994-95 to 1996-97 which increased to 69,281 MT in 1997-98 but declined to 48,703 MT in the first nine months of 1998-99. On an annualised basis the domestic production for 1998-99 works out to 64,937 MT. Thus, the domestic production that registered a growth of about 16 1% in 1997-98 over the average production during 1994-97 and 20 6% over 1996-97 production registered a fall of 6.69% in 1998-99 over 1997-98.

(b) Capacity Utilisation

(i) The domestic producers have constantly improved upon their capacities to produce phenol HOC have increased their capacity from 40,000 MTpa in 1994-97 to 45,000 MTpa in 1997-99. HCL have improved their capacity from 20,000 MTpa in 1994-95 to 24,000 MTpa in 1995-96, 26,500 MTpa in 1996-98 and to 30,000 MTpa in 1998-99. The two domestic producers have thus increased their combined capacity from 60,000 MTpa in 1994-95 to 75,000 MTpa in 1998-99, an increase of 25%. The capacity utilisation, however, declined in 1998-99 to 86.58% as compared to 96.89 % during 1997-98, a loss of 10.31%age points.

(ii) It has been argued by some of the interested parties that one of the petitioner's has reported highest ever-capacity utilisation and sales volume, as appeared in some newspapers. This reference appears to have been made in the context of HOC. In fact, M/s Mitsui Chemicals have specifically referred to official Press release dated November 4, 1998 and April 16, 1999 of HOC published by the Press Trust of India (PTI). The Press release dated April 6, 1999 in the context of capacity utilisation mentions that "capacity utilisation was 94% compared to 91% in the previous year". This capacity utilisation, however, does not refer to capacity utilisation of Phenol plant, but refers to the capacity utilisation of the HOC as a whole, which is a multi-product, multi-plant enterprise. As the total Phenol production capacity of HOC was 45,000 MT, the capacity utilisation of 2.71 lakh tonnes in 1998-99 as compared to 2.69 lakh tonnes in the previous year and sales volumes of 1.85 lakh tonnes do not refer to Phenol production and sales alone although production and sales of Phenol may be included in these figures. This argument, therefore, is irrelevant for the purpose of present investigation, which is in respect of Phenol alone. What needs to be considered for the purpose of determination of the state of affairs of the domestic industry is the performance of the Phenol plant.

(iii) Some parties have submitted that the capacity utilisation of the domestic producers to meet the domestic demand has remained stable at about 86% and that capacity utilisation in all streams of production needs to be considered rather than to consider capacity utilisation for the domestic demand alone. In this regard, it is observed that capacity Utilisation can not be considered for domestic demand alone as the same plant is used to meet the demand for domestic production as well as export production. Accordingly, capacity utilisation both for domestic

demand and exports would need to be considered. On this basis, the total production in 1997-98 including both to meet domestic demand and exports was 69,281 MT, 61,606 MT for domestic demand and 7,675 MT for exports and 48,703 MT in 1998-99 (April to December) including 52 MT for exports and 48,372 MT for domestic demand. The domestic producers thus achieved capacity utilisation of 96.89% in 1997-98 and 86.58% in the first three quarters of 1998-99, and thus suffered a loss of 10.31%age points in the capacity utilisation.

(c) Sales

The domestic producers registered a total domestic sales of 51,538 MT in 1994-95 ($3,172 + 57,780 - 3,448 - 5,244 - 722 = 51,538$), 61,490 MT in 1995-96, 56,535 MT in 1996-97, 62,390 MT in 1997-98 and 48,372 MT in April-December, 1998. As compared to 1997-98, on a pro-rata basis, the domestic producers in 1998-99 (April-December) achieved 3.38% more sales. This growth in sales, however, is to be viewed in the background of growth in the total apparent consumption which stood at 58,202 MT in 1994-95, 83,242 MT in 1995-96, 76,081 MT in 1996-97, 77,742 MT in 1997-98 and 73,922 MT in the period April-December, 1998. The growth in the apparent consumption in 1998-99 (April-December) over 1997-98 on a pro-rata basis was 25.1% whereas the growth in domestic sales of domestic producers was only 3.38%. The domestic producers could achieve this small growth only at the cost of a drastic reduction in their average sales price which was reduced to Rs. 28 per kg in December, 1998 as compared to Rs. 37 per kg in January-March, 1998.

(d) Stocks

The closing stocks of domestic producers which reduced from 3,248 MT in 1996-97 to 2,464 MT in 1997-98 has increased to 2,743 MT at the end of December, 1998 i.e. by 10.2% over 1997-98.

(e) Employment

The domestic producers have submitted that the talented, experienced and contributing employees have started resigning from the services of the companies thereby leading to irreparable loss to the knowledge pool and skills inventory of the domestic industry. They are also facing difficulties in attracting new recruits as they see lack of growth prospects in the limping Phenol industry. In this regard, it is observed that the number of employees with the domestic industry has remained almost the same.

(f) Productivity

As the domestic industry has lost production (6.69% in April-December, 1998 over 1997-98) and capacity utilisation (by 10.31%age points in April-December, 1998 as compared to 1997-98), the domestic industry has obviously lost productivity i.e. quantum of production per employee engaged by the domestic industry.

(g) Profitability

(i) The domestic producers had to reduce the list price of Phenol and offer various additional discounts to prevent their customers from shifting to imports completely. On an average, they reduced their selling price from Rs. 37 per kg in March, 1998 to Rs. 28 per kg in December, 1998 i.e. a decline of about 24.3% in the list price. HCL's net realisation of Phenol (bulk), which was Rs. 35,772 per MT during April 1998, reduced to Rs. 24,934 per MT in December 1998. In case of HOC, the net realisation dropped from Rs. 32,620 per MT in August 1998 to Rs. 24,620 MT in December 1998. The reduction in net realisation has had serious effect on profitability of the domestic industry. Both HOC and HCL have started incurring losses. In the case of HOC the losses in December 1998 were Rs. 1,198 per MT and in the case of HCL the losses were Rs. 3,298 per MT. This also had the effect of depressing the share prices of both the companies. The share prices of HOC reduced from Rs. 18 per share in April 1998 to Rs. 9 per share in December 1998 and in the case of HCL, the share price declined from Rs. 23.50 to Rs. 18.70 per share in the same period.

(ii) M/s Kesar Petroproducts have claimed that the domestic producers till at least November 1998 made profits and as they have made profits in the past it can hardly be held that the petitioners have suffered injury. In this regard, it is observed that with the list price of Rs.28 per Kg., the domestic producers incurred losses of Rs 1198 PMT in the case of HOC and Rs.3298 PMT in the case of HCL. The domestic producers, therefore, could not have made profits unless the list price was a minimum of (28 + 1198) i.e. Rs29.20 per Kg in the case of HOC and (28 + 3298) i.e. Rs31.30 per Kg in the case of HCL, presuming that they maintained same level of discounts etc. It is, however, seen from the information provided by the petitioners that the list price of both HOC and HCL was Rs.29 per Kg in Oct 98 and Nov 98. The claim of M/s Kesar Petroproducts, therefore, does not appear to be borne out on the face of the facts in question. As regards their argument concerning injury in the wake of past profits, it is observed that for determination of injury various factors have to be evaluated in an objective manner. If it appears that the domestic industry is suffering a significant overall impairment, a determination of existence of serious injury can be made. It may also be kept in mind that the present investigation concerns determination of existence of a threat of serious injury i.e. a situation where serious injury is clearly imminent. The turning of profits into losses is, therefore, to be viewed in the above background

(h) Threat of Serious Injury

Clause 6(d) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 defines 'threat of serious injury' to mean a clear and imminent danger of serious injury. Clause 6(c) of this Section defines 'serious injury' to mean an injury causing significant overall impairment in the position of a domestic industry. An analysis of various parameters as discussed above clearly brings out that the domestic industry in the first three quarters of 1998-99 has witnessed a severely depressed condition of operation. As compared to 1997-98, it has lost on account of production, capacity utilisation, sales realisation, profit, and productivity and has ended up in build up of inventory. It achieved a small growth in sales but which was far below the

growth in apparent consumption, that too only at the cost of a sharp reduction in the sale price. Serious injury to the domestic industry is thus clearly imminent. It is, therefore, observed that the domestic industry is suffering a threat of serious injury.

6 Cause of Injury

(a) Supply-Demand Gap

- (i) Some of the parties have claimed that the cause of injury to the domestic industry was not increased imports as the imports were necessitated to meet the gap between domestic supply and domestic demand. It may be appropriate to mention at the outset that HCL, which was the first unit to produce Phenol in India was set up in 1968 with an installed capacity of 10000 Mtpa of Phenol. In 1979 it requested for expansion of capacity by 20000 MT, but the request of the Company was turned down by the Government as per the then prevailing law, observing that HCL had a dominant presence in the Indian market. However, the domestic industry, which had a capacity to produce 60,000 MTpa of Phenol in 1994-95, gradually improved its capacity to 64,000 MT pa in 1995-96, 66,500 MTpa in 1996-97, 71,500 MTpa in 1997-98 and to 75,000 MTpa currently i.e. 1998-99. The total apparent consumption in the domestic market (i.e. domestic sales + imports) during this period increased from 58,202 MT in 1994-95 to 83,242 MT in 1995-96 and declined thereafter to 76,081 MT in 1996-97, 77,742 MT in 1997-98 before rising again to 72,922 MT in the first three quarters of 1998-99. On an average, the apparent domestic consumption, during the last three years i.e. 1995-96 to 1997-98 was 79,022 MTpa. Comparing individually the apparent consumption figures during each of these years with the average apparent consumption during this period or with the apparent consumption in the previous year it appears that the total domestic demand during this period has remained stagnant at around 80,000 MTpa. There was a sudden increase in total apparent domestic consumption in 1995-96 but thereafter, the apparent domestic consumption declined to around 76,000-78,000 MTpa in 1996-97 and 1997-98. A claim has been made by some parties that currently the domestic demand is about 1,00,000 MTpa which works out to about 25% more than the average consumption during the last three years. No evidence of increased demand of Phenol in 1998-99 has, however, been produced by any party nor any explanation has been provided by any party for this increase of 25% in the total apparent consumption in the current year, which is a substantial increase and appears difficult to be accepted without any reasonable basis. The total apparent consumption during the current year, therefore, does not appear to be indicative of the domestic demand i.e. the real requirement of Phenol for the domestic market. It appears that the domestic demand during the last few years has been of the order of about 80,000 MT and the possibility that the imports in the first three quarters of 1998-99 increased to take advantage of cheaper prices cannot be ruled out.
- (ii) As mentioned above, the domestic producers have upgraded their production capacity gradually from 60,000 MTpa in 1994-95 to 75,000 MTpa in 1998-99 i.e.

an improvement of 25% in 1998-99 over 1994-95. They, however, could not utilise their production capacity to the full extent and were constrained to produce only 48,703 MT in April-December, 1998. The domestic producers did in the past achieve nearly 100% capacity Utilisation, 99.56% in 1995-96 and 96.89% in 1997-98. They could have achieved similar capacity utilisation in 1998-99 also. On a pro-rata basis, they could have thus produced about 56,250 MT during this period ($75,000 \times 0.75$). The domestic producers thus lost about 7,547 MT of production. They also carried a stock of 2,743 MT at the end of December 1998. M/s Neyveli Lignite Corporation also could not utilise their full production capacity and carried on with a substantial inventory. It is, therefore, not correct to say that whatever imports have taken place were due to the inability of domestic producers to cater to the domestic demand. On the contrary, the cheaper imports restrained domestic producers to achieve their full capacity utilisation and caused price depression and inventory build up.

(b) Shut Downs

It has been argued that HCL shut down their operation for a period of 15 days and HOC for 40 days during 1998-99 (April-December) and, therefore, they were not in the market for 15% of the year during which period the domestic demand was met by the imports of Phenol. In this regard, it is observed that it is a matter of fact that HOC took shut down from 14.1998 to 9.5.1998 and HCL took shut down in early 1998-99 from 22.4.1998 to 8.5.1998. The total period of shut down for the two units, therefore, was 39 days in the case of HOC and 17 days in the case of HCL, which does not account for 15% of the year. Some period of shut down of the two companies over-lapped. However, shut downs are a normal feature for any chemical plant and they are taken into account in determining the normal plant capacity. HCL's shut down of 15 days was for capacity enhancement and to improve supplies thereafter. HOC accumulated stock of 2,180 MT of phenol before the commencement of shut down. Besides, during the period of shut down HCL reduced its captive consumption of Phenol by curtailing production of high value derivatives to maintain adequate supplies to the consumers. After the shut down, in the July-September 1998 quarter, the domestic producers produced 19751 MT of Phenol, which on a pro-rata basis works out to about 79000 MTpa. It is also seen from the details of India's Phenol imports in the first three quarters of 1998-99 furnished by the petitioners that during this period only three consignments of Phenol were imported. First of 1,105.152 MT from South Africa in Vessel 'Bow Fortune' which arrived on 3rd April, 1998 and the second of 1045.499 MT from Japan in Vessel 'Lodestar Spirit' which arrived on 9th April, 1998 and the third of 1,262.846 MT from South Africa which arrived on 8th May, 1998 in Vessel 'Bow Spring'. These total up to 3,413 MT which does not even account for 15% of the 24550 MT imported in April-December, leave aside the imports for the whole of 1998-99. In view of the above discussion, it does not appear that the shut down of HCL and HOC for a short duration in early 1998-99 had any impact on the surge of imports in the first three quarters of 1998-99.

(c) Loss of Exports

It has also been claimed that the reason for the woes of the domestic industry is loss of its export market that has declined to 52 MT in 1998-99 as compared to 7,675 MT in 1997-98 and not the imports of Phenol. In this regard it is observed that the domestic producers have specifically mentioned in their application that inspite of the freight disadvantage, Indian manufacturers were forced to export Phenol in 1997-98 at low realisation out of desperation. It is important to keep in mind that the production line for production of Phenol is common both for the domestic consumption and for the export market. A domestic industry that was not able to compete in the domestic market could hardly have been expected to compete in the international market, specially when the domestic supplies were the major market for the domestic industry and exports constituted only a fraction of its market. The injury caused to the domestic producers by the increased imports, therefore, had its effect on the export performance of the domestic producers as well. Nevertheless, the domestic producers did supply 3137 MT of phenol in 1998-99 during April-December, 1998 under the Deemed Export Scheme, which are considered as exports without goods physically leaving the Indian shore.

(d) Market Share Taken Over by Imports

(i) The domestic producers had a market share of 51,538 MT i.e. 88.52% in the total apparent consumption in 1994-95. Their market share fell down to 73.86% in 1995-96 and to 74.3% in 1996-97 before rising to 80.25% in 1997-98. In the first three quarters of 1998-99, however, the domestic producers lost their market share accounting for a mere 66.3%. The share of imports in the apparent consumption increased from 11.48% in 1994-95 to 26.14% in 1995-96 which decreased to 25.7% in 1996-97 and to 19.75% in 1997-98 before rising to 33.7% in the first three quarters of 1998-99. On a comparative basis the share of imports has increased by 70.6% in 1998-99 (April-December) over 1997-98. The Table below gives the market share of the domestic producers from 1994-95 onwards.

Table 3

Year	OB MT	Prod. MT	CB MT	Exports MT	D.Sales (2)+(3)- (4)-(5) MT	Total App. Cons. MT	Share of D.Sales in App. Cons. %	Share of Imports in App. Cons. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1994-95	3172	57780	3448	5966	51538	58202	88.52	11.48
1995-96	3448	63719	3323	2354	61490	83242	73.86	26.14
1996-97	3323	57466	3248	1006	56535	76081	74.3	25.7
1997-98	3248	69281	2464	7675	62390	77742	80.25	19.75
1998-99(A-D)	2464	48703	2743	52	48372	72922	66.33	33.67

(ii) The total apparent consumption in 1997-98 stood at 77,742 MT, which on a pro-rata basis increased by 25.1% to 72922MT in the first nine months April-December of 1998-99. The domestic sales, however, did not grow at the same pace. The domestic producers who should have achieved sales of $\{(62,390/12) \times 9 \times 125.1\% \}$ 58537MT could sale only 48,372 MT of Phenol in the domestic market during this period (including 3137 MT supplied on deemed export basis by HOC) The domestic producers thus lost a sale of 10165 MT which was taken over by the increased imports which captured an additional market of $\{24550 - (15,312/12 \times 9 \times 125.1\%) \}$ 10184 MT taking into account the growth of 25.1% in the apparent consumption The quantitative increase in imports during this period on a pro rata basis was 13066 MT.

(iii) The domestic producers have submitted that they had to make several adjustments in the price in order to match the domestic prices with the expected landed cost of Phenol Apart from reducing the list price of Phenol, the domestic producers had to offer various additional discounts to prevent their customers from shifting to imports completely. It is pertinent to note here that from mid 1994 to March, 1998 the CIF (Indian) prices of Phenol have shown a pattern different from that seen after March, 1998 as indicated in Table 4 below.

Table 4

Month	US sourced CIF	Europe sourced CIF	Asia Pacific	CIF India
July94	780	780		540
Nov 94	780	820		750
May95	790	855		780
July95	790	870		685
Oct 95	850	920		530
Mar96	814	945		530
May96	792	820		640
Aug96	726	670		710
Nov96	605	630		710
Mar97	583	603		720
May97	720	760	710	720
June97	730	795	685	700
Sept97	730	810	665	680
Nov 97	790	860	700	680
Mar98	754	885	700	670
June98	732	760	600	560
Sept98	666	610	555	440
Oct98	545	570	470	420
Nov98	523	543	445	405
Dec98	422	515	440	395

It is seen from the information provided in Table 4 above that the CIF India prices started falling from about the level of \$ 750-780 in Nov 94/May95 to \$530 in

March96 and firming up thereafter to \$720 in May 1997. The CIF India prices started falling slowly in June1997 from \$700 to \$680 in Sept./Nov97 and to \$670 in March98. After March98, however, the CIF India prices fell sharply to \$560 in June98, \$440 in Sept.98 and to a level of about \$400 in Nov./Dec.98. The declining import prices had its effect on the domestic industry. The domestic producers with the enhanced capacity, after shut down in April-May 1998, recorded a production of 19751 MT in the quarter July-Sept.98 but were forced to reduce production thereafter to 6,138 MT in October, 6,080 MT in November and to 5,167 MT in December 1998.

- (iv) M/s Mitsui Chemicals Inc. have submitted that 3 shipments made in December, 1998 were at prices higher than US \$ 395 PMT claimed by the domestic producers, which is an exceptional case and should not be used for general consideration. As regards the import prices in December 1998, Kandla Custom House has confirmed that imports have entered in December 1998 at prices of US \$ 408-430 PMT as compared to US \$ 617-675 PMT in April 1998. Most of the bulk imports of Phenol entered through Kandla port. It is observed from the information obtained from the Kandla Custom House that while in the first quarter of 1998-99 when the CIF prices of Phenol ranged between US\$ 530-675 PMT the quantum of imports was 3989.505 MT which was slightly higher than the pro-rata imports in the previous year in spite of both the domestic producers having taken shut down in April-May 1998. With the CIF import prices falling to US\$480-555 PMT the imports in the second quarter more than doubled to 8886.534 MT and the imports further increased to 9152.375 MT in the third quarter with the CIF prices declining to US\$ 408-475 PMT. There has, therefore, been a drastic fall in the CIF import prices of Phenol entering into India during this period, which was the main reason for the increased imports during this period. The increased imports entering at cheaper prices forced the domestic producers to cut-down their production and to reduce their list prices from Rs. 37 per kg in March 1998 to Rs 36.5 per kg in June 1998, Rs. 31.5/33 per kg (HCL/HOC) in September1998, Rs. 29 per kg in October and November, 1998 and to Rs. 28 per kg in December, 1998, even at the cost of incurring losses.
- (v) Some parties have claimed that chemical industry at large has been passing through a global recession and the Indian Chemical Industry has also felt its impact. The down turn in business and prices is, therefore, not peculiar to India. This argument, however, does not appear to be borne out on facts as while on the one hand the imports have increased substantially, the apparent consumption of the domestic market, on the other hand has also increased substantially in the first three quarters of 1998-99. The depressed condition of domestic Phenol industry thus is not due to lack of domestic demand or due to general recession, if any, in the Chemical Industry but due to the increased imports at cheaper prices.

7. Other Issues

(a) Dumping of Phenol

M/s Kesar Petroproducts have submitted that it was evident from the information provided by the petitioners that there is apparently dumping of Phenol in the

Indian market and, therefore, the DG was prevented from proceeding further in the matter. In support they have quoted from the petition that " CIF India Phenol prices, which used to be in line with the prices in other parts of the world, have come down more drastically than in other parts of the world like USA, Europe and Far East" and that 'whereas the drop in USGC prices has been to the extent of US \$ 110 PMT till end-September 1998, the drop in CIF India price has been more drastic at US \$ 275 PMT'. In this regard, it is observed that lower prices for Indian market as compared to other markets *per-se* are no evidence of dumping of Phenol into the Indian market as a product is to be considered as being dumped i.e. introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade for the like product when destined for consumption in the exporting country. No information on the normal value or any evidence of injury to the domestic industry having resulted from dumping from any specified sources has been provided by any party and, therefore, the claim of M/s Kesar Petroproducts is unsubstantiated and does not merit consideration.

(b) Captive Consumption of Phenol

It has been argued that the petitioners consume Phenol captively also to some extent. The facilities available with them to that extent are not available for the merchant market and should be excluded from the capacities of the petitioners to cater to the demand in the country. This argument is erroneous in as much as if the domestic demand includes the captive requirements of the domestic producers, the facilities of the petitioners to that extent can not be excluded from the consideration. Throughout this investigation, the domestic demand has been taken including the captive consumption of the petitioners and, therefore, this argument is without merit.

(c) Joint Product Evaluation

It has been argued that Phenol and Acetone are joint products and, therefore, it would not be appropriate to assess injury to the domestic industry for Phenol alone without assessing position with regard to Acetone. In this regard, it is observed that both the domestic producers maintain their records in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and the injury in respect of Phenol has been assessed in accordance with GAAP for joint products. Assessment of the position of the domestic industry with regard to Acetone is, therefore, not relevant for the purpose of present investigation.

(d) Monopoly/Duopoly of Domestic Producers

(i) Some of the parties have argued that the domestic producers of Phenol have enjoyed monopolistic situation as their production accounts for upto 91% of the domestic consumption of Phenol and that the current complaint is with a view to secure and sustain the complainant's duopolistic dominance in the Indian market whereby they can continue to exploit the domestic market. In this regard it is observed that any monopoly is not to be considered illegal *ipso facto* but a

balance needs to be struck between the injury caused as a result of monopolistic or restrictive trade practices and the reasonableness thereof in the context of benefits accruing thereby. There are three domestic producers of Phenol, namely HCL, HOC and M/s Neyveli Lignite Corporation Ltd. While HCL is in the private sector, the other two namely HOC and M/s Neyveli Lignite Corporation Ltd. are in the Public Sector who account for more than 50% of the production capacity of Phenol. Besides, the import of Phenol is under Open General License. Nearly one-third of the total apparent consumption has been catered to by the imports. The petitioners have not requested for banning the import of Phenol, instead they have requested for imposition of safeguard duty on the imports of Phenol in accordance with the law so as to enable them to adjust to the new situation of competition offered by the increased imports. The domestic Phenol industry has acted as a catalyst in the development of a host of downstream industries with the assured domestic availability of Phenol. HCL has made valuable contribution in the development of various applications of Phenol such as Phenol Formaldehyde Resins used in the Plywood, Laminates, Foundry Resins and PF Molding Powder; Salicylic Acid, Aspirin and Paracetamol for use in Pharmaceuticals; 2,4-D (Herbicide) for use in Agrochemicals; and Synthetic Tanning Agents for use in the Leather Industry. This accelerated the development of the downstream industries and as the demand in the Indian industry increased, HOC commenced production in 1988, using the state-of-the-art technology. HOC and HCL have since then catered to the requirements of the downstream industries, many of which are export oriented and HOC sold good quantities of Phenol to them on deemed export basis. It may also not be out of place to mention here that this situation is not peculiar to India alone. The current major suppliers of Phenol to India namely South Africa and South Korea have only one plant each and in Japan, three industrial groups control over 70% of the Japanese capacity.

(ii) Some parties have alleged against the domestic producers that they exploited the domestic market. In spite of significant decline in customs duties, the selling prices of the petitioners remained more or less unchanged, the reduction in raw material prices was not passed on to the customers and that their selling prices were not based on the import prices. In this regard, it is observed from the information provided by the domestic producers that during the period from July, 1994 to December 1998, the landed cost of imported Phenol and the corresponding list prices of HCL and HOC were as given in Table 5 below.

Table 5

Period	Landed cost of imported Phenol Rs/MT	List Price -Basic Ex-works Rs./Kg (Bulk)	
		HCL	HOC
July 94	28687	29	27
Nov 94	39844	32	32
May 95	35569	34	34
July 95	31327	34	34
Oct 95	26981	32	32

17/8/98-15

March96	28121	29	29
May96	31663	31	33
Aug96	34588	35	35
Nov96	34588	38	38
March97	33625	36.5	36.5
May97	33616	36.5	36.5
Sept97	32298	35.5	35
Nov97	34037	35	35
Mar98	35340	37	37
June98	33705	36.5	36.5
Sept98	26346	31.5	33
Oct98	25376	29	29
Nov98	24205	29	29
Dec98	23646	28	28

From the information tabulated above, it is abundantly clear that it is not correct that the domestic prices remain unchanged or that the domestic producers did not reduce their prices or that they did not match them with the landed cost of the imported Phenol. The domestic prices have followed the trend of the landed cost of the imported Phenol. This allegation, therefore, is not supported by the facts and is accordingly rejected.

- (iii) It has also been alleged that the domestic producers resorted to steep hike in the price at the time of storm at Kandla port, when the goods could not be imported. In this regard, it is observed that the domestic producers have explained that since Phenol could also be imported in bulk at Calcutta, Chennai, Goa and Mangalore ports, price increase to Rs. 40 per kg consequent to Kandla port being non-operational was not an exclusive reason. In fact, Phenol consumers who generally patronise Kandla for import of Phenol were unable to get the product and they resorted to buying from open market, which pushed up the demand beyond the normal offtake and consequently prices. Initially, it was felt that the outrage of Kandla port would be for a period of around three months and there was a panic buying to some extent. During the same period, prices of Benzene (the key raw material for Phenol) also went up by 10%. Prices of several other products went up during this period. The domestic Phenol producers accordingly adjusted prices. This was just a normal market mechanism, which was working. In the process, both Phenol manufacturers succeeded in not permitting market middlemen to reap profits at the cost of their own shareholders. Both HCL and HOC are active members of the Indian Chemical Manufacturers Association, which sent a team to Kandla to assess the damage. Apart from this, HCL sent a team of Safety Officers, technicians etc. soon after the natural calamity and the service rendered by this team was appreciated by the Chairman of the Kandla Port Trust.
- (iv) Another allegation made against the domestic producers is that they have taken shut down at the same time to create shortages. The domestic producers in this regard have submitted that this argument does not stand to logic and commercial sense as simultaneous shut downs will lead only to shortages without any company reaping the benefit of the same. It is observed that generally HCL and

HOC have not taken simultaneous shut down except in 1998 when there was an overlap of about 15 days. However, during the shut down, HOC had a stock of 2,180 MT before the commencement of the shut down and the Phenol price was reduced from Rs 37,000 PMT to Rs. 36,000 PMT in April, 1998 and further to Rs 35,000 PMT during May, 1998. This argument, therefore, has no merit in view of the above facts.

(e) Import Duty Structure in India

Some parties have submitted that in keeping with the growing policy of liberalisation the import duty of Phenol has been reduced over the years but still it is the highest in this region and, therefore, provides an in built protection and competitive parity to the manufacturers of Phenol in India. This argument, however, is considered to be irrelevant in the context of safeguard duty as the level of import duty on a particular product depends upon various factors some of which are level of imports duties on comparable and competitive products and on inputs, the need to raise revenue and the disadvantages suffered by the domestic producers vis-à-vis international producers etc. Each country, therefore, decides the level of import duties according to its needs, which cannot be viewed as a reference point for others. It is also relevant here to mention that the duty differential between Phenol and its raw materials has reduced from 55% in 1993-94 to 11.5% currently.

(f) Quality

(i) Some concern has been expressed by some of the parties about the quality of domestically produced Phenol. In this regard it is pertinent to note that the domestic producers have submitted that both the Indian Phenol manufacturers by the synthetic route are ISO 9002 accredited units. HCL has obtained ISO 14001 certification as well and HOC is in the process of obtaining it. HCL and HOC are both signatories to the Responsible care movement. Elaborate systems for quality assurance are in place. It is mandatory to keep records of quality complaints (if any). During the entire fiscal year 1998-99, HCL received only one complaint, which after scrutiny was found to be due to contamination during transportation outside HCL's factory premises on the way to the consumer's factory. There have been no quality complaints received by HOC. On the other hand, HOC have been complemented for maintaining standard quality.

(ii) As regards quality of Phenol for manufacture of Polycarbonate grade Bisphenol-A it has been submitted by the domestic producers that Polycarbonates are not produced in India and hence there is no domestic requirement for Polycarbonate grade Bisphenol-A in India. The Bisphenol-A manufacturer M/s Kesar Petroproducts Ltd. has not asked for any Phenol from HCL or from HOC of a superior quality. However, just in case Kesar Petroproducts Ltd. are in a position to manufacture and export Polycarbonate grade Bisphenol-A, and if they need special grade Phenol for the same, the domestic Phenol manufacturers claim to be able to rise to the occasion to meet the quality requirements of M/s Kesar Petroproducts. Until recently, Bisphenol-A producers have procured majority of their requirements from the domestic producers and continue to do so.

(iii) It has also been stated that the domestic Phenol is not suitable for the manufacture of Alkyl Phenols due to high moisture content. In this regard, it is observed that the domestic industry has successfully supplied Phenol to Alkyl Phenols manufacturers for number of years without quality complaints. In fact, HCL itself is one of the producers of Alkyl Phenols and manufacturers Alkyl Phenols of international quality from its own manufactured Phenol without any technical difficulties. HCL has been manufacturing Alkyl Phenols based on its in house technology for the development of which it has received the prestigious Acharya Sir P C Ray Award. The most stringent specifications for Alkyl Phenols in India are laid down by the Perfumery Chemical industry for an Alkyl Phenols known as P T B P. HCL has a letter from M/s Naiknavare Chemicals Ltd who have manufactured the perfumery grade of P.T.B.P. from HCL's Phenol. HOC has received a letter from Schenectady conveying that the quality of Phenol supplied by them fully meets the specifications and standards of Schenectady.

8 Adjustment Plan

(i) Some parties in regard to adjustment plans of the domestic industry have submitted that one of the petitioners claims to enhance the capacity to 65,000 MT within 2-2.5 years. It is not understood how the petitioners would become competitive in two years time, even if it is assumed that this company would be able to increase the capacity to 65,000 MT in 2.5 years, particularly when the petitioners have sought a relief of as high as Rs. 16,000 PMT, and the measures proposed by them would improve their competitiveness by hardly Rs. 1500. Evidently, it cannot be claimed by the petitioners that they would become competitive in two years, notwithstanding the policies of the government with regard to either rate of interests or other infrastructural bottlenecks. The submission made by the domestic industry that an investment is being envisaged to set up a Greenfield world scale plant of 100,000 MT capacity at a cost of Rs. 650 crores is not economically viable and deserves to be rejected outright. In fact, this argument of the petitioners alone is sufficient to hold that the petitioners are not at all serious about improving their competitiveness. That the positive adjustment plan proposed by the petitioners are not viable is borne out by the simple fact that the cost of interest, depreciation and reasonable return on an investment of the tune of Rs. 650 crores comes to Rs. 27,000 PMT even if the domestic industry projects to achieve 100 percent capacity utilisation in the very first year of its operation. The whole purpose of safeguard duty being to facilitate positive adjustment by the domestic industry, it is the duty of the DG to ensure that the efforts proposed by the domestic industry towards positive adjustments are technically and commercially viable.

(ii) In regard to making a positive adjustment to import competition both the domestic producers have categorically stated that they understand that the relief granted as safeguard duty is a short-term measure. HCL have stated that the existing facilities were built in the pre-liberalisation, MRTP era and lack economies of scale leading to high fixed costs. However, the Indian industry has been regularly upgrading its technology and debottlenecking its manufacturing facilities with the

objective of reducing the operative costs per unit and increasing its effective capacity to satisfy the increasing domestic demand from most of the sectors. On the capacity enhancement front (with consequent reduction in the fixed costs of manufacture), HCL, which has very recently increased its capacity from 26,500 TPA to 30,000 TPA has active plans to increase it to 40,000 TPA. To reduce the power cost, steps have already been taken by them towards setting up of captive power generation facilities by the Co-generation route. The facility has already been installed and would get stabilised by 1999. Apart from this (in HCL), external consultants had been appointed to suggest various cost reduction measures. Some such suggestions (e.g. improvement in quality of feedstock (Cumene)) are extremely valuable from the point of view of reduction in the cost of manufacture of Phenol. All this is an ongoing exercise, which would continue. In the medium term Propylene will be imported by the industry through the new facilities being generated at ports like the J.N.P.T. near Mumbai (for which HCL has been one of the promoters and which has got clearances from the Ministry of Surface Transport and the Ministry of Environment and Forests) and GCPTL at Dahej. The capacity of IOC refinery at Panipat is being increased and the process would be completed by mid 1999. Also the global sized refinery of Reliance Industries Limited at Jamnagar is expected to be commissioned in 1999. With the cracker complexes at GAIL and Haldia also expected to be commissioned in the near future and with debottlenecking of the existing facilities, the domestic Propylene availability could ease out and prices could soften and sourcing would be possible from the new sources. HCL is planning to set up world scale Greenfield Phenol manufacturing facilities (either 100,000 TPA or 150,000 TPA). The HCL facility is being planned at Dahej in Gujarat state. Technologies have also been tied up. State-of-the-art Zeolite technology for Cumene has been tied up with UOP of USA. Similarly, latest generation technology has been tied up for Phenol manufacture with ABB Lummus Global of USA. Both technologies are environment friendly and would give HCL certain operational and cost advantages. The raw materials would either be imported or could be sourced from the new facilities such as the ones mentioned above. Land has been allotted for the HCL project. Environmental Impact Assessment study has been completed. The Gujarat Pollution Control Board has granted N.O.C. for the project. HCL's water requirements have been included in the common water supply schemes of GIDC at Dahej and they have made initial payments towards the same. Power is planned to be generated captively by the co-generation route. On the funding aspect, HCL has already approached the financial institutions. The raw material and finished product traffic figures of the HCL project have been factored in the overall traffic figures of Gujarat Chemical Port Terminal Complex coming up at Dahej. This port is expected to be operational by the end of 1999. There is a further possibility of a co-operative effort on this front between the two manufacturers, HOC and HCL. However, due to the liquidity crunch (and the consequent loss of profitability), HCL is finding it extremely difficult to access funds from financial institutions. This is, in turn, resulting in delay of implementation of the long-term plans to build a Greenfield Phenol plant of

capacity 100,000 TPA. On the other hand, the quick implementation of this project is imperative for future survival of our organisation.

(iii) HOC in this regard have stated that on the capacity enhancement front (with consequent reduction in the fixed costs of manufacture), HOC, has very recently increased its effective capacity from 40,000 TPA to 45,000 TPA. To reduce the power cost, steps have already been taken by HOC towards setting up of captive power generation facilities by the Co-generation route. The facility has already been installed and the gains could start accruing in the current fiscal year. All this is an ongoing exercise, which would continue. HOC is planning to set up world scale Greenfield Phenol manufacturing facilities of 100,000 TPA as a joint venture with refinery. The HOC facility is being planned at coastal location in either Maharashtra or Gujarat State. Technologies are in the process of being tied up State-of-the-art Zeolite technology for Cumene and latest generation technology is in process of being tied up for Phenol manufacture. Both technologies would be environment friendly and would give HOC certain operational and cost advantages. There is a further possibility of a co-operative effort on this front between the two manufacturers, HOC and HCL.

(iv) Thus, the plans of the domestic industry to make adjustment to the import competition are not hypothetical. They have identified the reasons for their being not able to meet with the competition offered by the increased imports. One of the reasons identified by them is the lack of economies of scales. The domestic producers have constantly been upgrading their production facilities During the last few years, they have enhanced their capacity gradually from 60,000 MT pa in 1994-95 to 75,000 MTpa in 1998-99, which accounts for an increase of 25% in the capacity The domestic producers have furnished essential details of cost saving schemes being pursued by them and the cost reduction likely to be achieved therefrom in response to the questionnaire. This appears to be a viable adjustment plan, which is likely to be implemented and give results in a period of two years The domestic industry, although had requested for imposition of safeguard duty for a period of three years in their petition but keeping in view the efforts planned by them, this period in the Notice of Initiation itself was restricted to two years. As regards the long-term plan, in view of the fact that it is proposed to consider the application of safeguard duty only for a period of two years, it is not necessary to discuss the long-term efforts planned by the domestic producers. However, for the sake of argument it is observed that setting up of 100,000-150,000 MT plant by the domestic producers using Greenfield Phenol manufacturing facilities at high costs is no exception in the case of HOC or HCL as such Phenol plants are capital intensive world over. Besides, such plants do not produce a single product-Phenol alone and, therefore, the costs have to be shared by different products. If world over such plants can produce Phenol efficiently, it is not understood why in similar circumstances they can not produce Phenol efficiently in India. It is, therefore, observed the domestic industry is in the process of making positive adjustment to compete with imports and that they require two years to become competitive.

9 Public Interest

- (i) Some of the parties have argued that imposition of safeguard duty would not serve any public interest. On the contrary imposition of safeguard duty would severely prejudice the public interest as a number of end user industry may close down. In this regard, it is observed that the expression 'public interest' does not cover in its ambit consumer interest alone. It is a much wider term, which covers in its ambit the general social welfare taking into account the larger community interest. While the imposition of safeguard duty may result in increased cost of imported Phenol in the hand of buyers and therefore, it may also effect the end products manufactured therefrom, it is important to keep in mind the objective of imposition of safeguard duty. The purpose of imposition of safeguard duty is to provide time to the domestic industry to make positive adjustment to meet with the new situation of competition offered by the increased imports. The imposition of safeguard duty, for the period and to the extent just adequate, would, therefore, not only minimise the adverse effect, if any, for the customers but also allow them a wider choice to source their requirements, and at competitive prices. The domestic producers who have set up plants with huge public investments provide employment to a large number of people and make valuable contribution to the national economy. Safeguard duty, which would enable the domestic producers to survive in the face of competition offered by the increased imports, will, therefore, also be in the long-term interest of the buyers of Phenol as well as of the buyers of products manufactured therefrom. It is, therefore, considered that imposition of safeguard duty on Phenol will be in public interest.
- (ii) It has also been submitted that imposition of safeguard duty will adversely affect country's exports, as imported Phenol used in export production will become costlier. In this regard, it is observed that in international trade exports are net of duties and taxes i.e. all duties and taxes including safeguard duty paid on inputs used in the manufacture of export production are entitled to be refunded as duty drawback etc. Duties and taxes including safeguard duty paid on imported Phenol used in export production would also, therefore, be entitled to be refunded. The objective of safeguard duty is to enable the domestic producers to become internationally competitive. If, therefore, the domestically produced Phenol is not internationally competitive for use in export production, imposition of safeguard duty should help it in becoming internationally competitive, which should be in the long-term interest of the exporters. As far as duty free imports of Phenol under various schemes for use in export production are concerned, the same principle as discussed above applies i.e. either such imports may not be subjected to levy of safeguard duty *ab initio* or if safeguard duty is collected, it should be entitled to be refunded on export of final product, in accordance with the existing laws. It is, therefore, observed that imposition of safeguard duty on Phenol is neither likely to affect adversely the export production, nor is it against the Public interest.

10 Provisional Safeguard Duty

In view of the fact that critical circumstances indicating that the domestic industry is likely to suffer irreparable damage in case imposition of safeguard duty was delayed till the completion of the investigation did not exist, no recommendation to impose provisional safeguard duty was made.

11 Share of Countries in Exports to India

On the basis of information in regard to imports of Phenol into India during the period April-December, 1998, it is observed that only six countries exported Phenol to India during this period. Their shares in India's imports during this period on the basis of Bill of Lading quantities were as under.

Country/Territory	Imports-MT	%age share
France	31.20	0.125
Japan	3932.46	15.81
Netherlands	31.20	0.125
South Africa	8063.41	32.42
South Korea	11813.03	47.50
Taiwan	999.01	4.02
Total	24870.31	100

H CONCLUSION AND RECOMMENDATION

1. In view of the Findings above, it is concluded that increased imports of Phenol into India have threatened to cause serious injury to the domestic producers of Phenol and it will be in the Public interest to impose safeguard duty for a period of two years on imports of Phenol into India.
2. In arriving at the amount of safeguard duty that would be adequate to prevent serious injury to the domestic industry and to facilitate positive adjustment, weighted average cost of production for HCL and HOC has been taken into account for the period April-December, 1998. The domestic producers have claimed a certain amount of profit on the basis of expected return on capital employed etc. which is considered to be on the higher side and, therefore, a lower amount of profit (confidential) based on the weighted average cost of production has been considered appropriate and allowed. Similarly, the C.I.F. import prices of Phenol also have been considered on weighted average basis for the last six months i.e July-December, 1998. Adjustments have been made in the C.I.F. import price for credit terms and handling charges on an average basis. Change in the applicable rate of customs duty has been taken into account in working out the landed price of imported Phenol. No adjustment in landed price of imported Phenol has, however, been made for internal freight as the domestic prices also have been considered ex-works, and for storage at Kandla port as storing of imported Phenol at Kandla port is an option available to the importers with attendant costs and benefits.

3. Considering the need to progressively liberalise the safeguard duty in order to facilitate positive adjustment by the domestic industry, it is recommended that safeguard duty be imposed on imports of Phenol into India at the rates specified below on ad-valorem basis for a period of two years as under being the minimum necessary for the protection of the domestic industry from the serious injury threatened to be caused by the increased imports of Phenol.

Period (1)	Level of total protection recommended % (2)	Existing protection % (3)	Safeguard duty recommended % (3)-(2) (4)
First year	27.5+22	27.5	22
Second year	27.5+15		15

[F No. SG/INV/2/98]

R K. GUPTA, Director General

